



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2004/28 कार्तिक, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचाल) विनियम, 2004

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संव्यवहार) विनियम, 2004

अधिसूचना

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2004

संख्या एच०पी०इ०आर०सी०/सचिव/151/2004.— निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) खण्ड (छ) (यछ) तथा (पठ) के साथ पठित धारा 86 की उप-धारा (1) तथा धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, पर विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्यौथल, कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला-171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

अध्याय -1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संव्यवहार) विनियम, 2004 है ।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
- (घ) "सदस्य" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ङ) "अधिकारी" से आयोग के अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (च) "याचिका" से सभी याचिकाएँ, आवेदन, परिवाद, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर तथा अनुपूरक अभिवचन अभिप्रेत हैं;
- (छ) "कार्यवाही" से वे सभी कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं और उसके अन्तर्गत वे सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ आती हैं जो अधिनियम के अधीन आयोग, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर सकता है परन्तु कार्यवाहियों के आरम्भ के पूर्व आयोग की प्रारम्भिक बैठक या कार्यवाई इन विनियमों के प्रयोजन के लिये कार्यवाही नहीं मानी जाएगी ;
- (ज) "प्राप्तकर्ता अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयोग याचिकाएँ प्राप्त करने के लिए पदाभिहित करे;
- (झ) "विनियम" से ये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत हैं;
- (ट) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैं; तथा
- (ठ) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु यहां परिभाषित नहीं हैं; वही अर्थ होंगे जो कि उन्हें अधिनियम में नियत किया गया है ।

3. आयोग कार्यालय, कार्यालय समय तथा बैठकें.—(1) आयोग, समय-समय पर, आदेशद्वारा, आयोग कार्यालय स्थल विनिश्चित करेगा ।

(2) जब तक अन्यथा निर्देशित न हो, आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय, प्रत्येक मास के दूसरे शनिवार, रविवार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अवकाश दिवसों को छोड़कर, प्रतिदिन खुले रहेंगे।

(3) आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ऐसे समय पर, जैसे आयोग निर्देशित करे, खुले रहेंगे।

(4) जहां कोई काम करने का अन्तिम दिन ऐसे दिन को पड़ता है जिसको आयोग का कार्यालय बन्द रहता है और उस कारण से उस दिन कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है तो वहां वह काम अगले कार्य दिवस, जिस दिन कार्यालय खुलना है, को किया जायेगा।

(5) आयोग मामलों की सुनवाई मुख्यालय तथा किसी अन्य स्थान, दिन और समय, जैसे आयोग विनिश्चित करें, कर सकेगा।

(6) आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विभिन्न उपभोक्ता हित-समूहों, गैर सरकारी संगठनों अथवा अन्य स्टेक-होल्डरों से अन्योन्यक्रिया हेतु, मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर, आयोग द्वारा विनिश्चित दिन तथा समय को औपचारिक या अनौपचारिक सुनवाई कर सकेगा।

4. आयोग की भाषा.—(1) आयोग की कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएंगी।

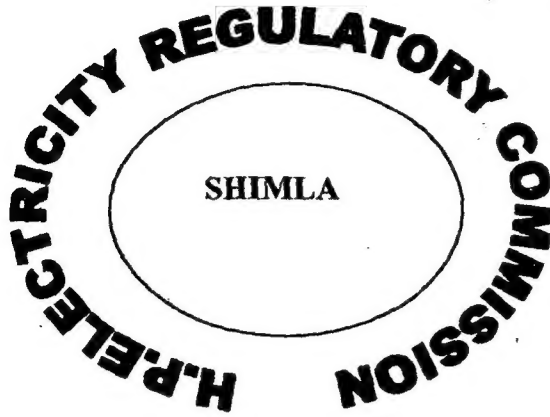
(2) आयोग द्वारा, कोई याचिका, दस्तावेज या अन्य सामग्री, जब तक कि उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न न हो, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में, स्वीकार नहीं की जाएगी।

(3) उपयुक्त मामले में, आयोग कोई भी अनुवाद जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों में सहमति है, अथवा जिसके बारे में कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जिस द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, अधिप्रमाणिकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, सही अनुवाद के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

(4) आयोग, उपयुक्त मामलों में याचिका, अभिवचन, दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के अंग्रेजी अनुवाद के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी या व्यक्ति को इसके अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

5. आयोग की मुद्रा, संप्रतीक तथा झंडी.—(1) आयोग की अलग प्राधिकारिक मुद्रा, संप्रतीक तथा झंडी होगी, जो यह उपदर्शित करेगी कि वह मुद्रा, संप्रतीक तथा झंडी आयोग की है।

(2) आयोग की मुद्रा वृत्ताकार जिसके बाहर वृत्त में "HP Electricity Regulatory Commission" तथा आन्तरिक वृत्त में "SHIMLA" उत्कीर्णित होगा, निम्नदत्त होगी :-



(3) आयोग द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, लिया गया विनिश्चय या किये गए पत्राचार या जारी की गई सूचना या दी गई प्रमाणित प्रतिलिपि पर आयोग की मुद्रा अंकित की जायेगी तथा सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप में प्राधिकृत तथा पदाभिहित करे, द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

(4) प्रदेश की पर्वतीय पृष्ठभूमि के साथ उत्पादन केन्द्र से जुड़े हुए पारेषण टॉवर पर रखे हुए, बहिर्विष्ट तराजू के दोनों ओर के पलड़े उपभोक्ता तथा उपयोगिता को रूपित करते हुए और उसके बाह्य वृत्त के ऊपरी भाग में "H.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION" तथा बाह्य वृत्त के निचले भाग में "TRUTH TRIUMPHS" उत्कीर्णित करता हुआ, आयोग का संप्रतीक, निम्नवत् होगा:-



(5) दोनो ओर पीली पृष्ठ भूमि में जुम्बुकी नीले रंग में आयोग के संप्रतीक के साथ 250 X 150 मी.मी. की निम्नवत आयतकार की झंडी अध्यक्ष अथवा सदस्यों की स्टाफ कार पर संप्रदर्शित की जाएगी :-



6. आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) आयोग, भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी रख सकेगा। यह अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप, ऐसे सचिव, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ, अनुभव तथा अन्य निबन्धन एवं शर्तें भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा आदेशित न किया गया हो, आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) आयोग अपने कार्य निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगा।

7. सचिव के कृत्य एवं कर्तव्य.— (1) सचिव ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इन विनियमों के अन्तर्गत या अन्यथा अध्यक्ष द्वारा, सौंपे जाएं।

(2) विशिष्टतया और उप-विनियम (1) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सचिव निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् -

- (क) वह आयोग से सम्बन्धित सभी याचिकाओं, आवेदनों तथा संदर्भ को प्राप्त करेगा अथवा करवाएगा ;
- (ख) वह आयोग के समक्ष किये गये सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार करेगा या करवाएगा ;
- (ग) वह आयोग द्वारा संचारित कार्यवाहियों में आयोग का सहयोग करेगा;
- (घ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करेगा ;
- (ङ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
- (च) उसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा उनके अभिकर्ताओं, राज्य विद्युत बोर्डों अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, आयोग द्वारा ऐसी सूचना जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिये उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकार होगा ;
- (छ) वह -

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा पश्चात्पूर्वी संशोधन अधिनियमों की अधिकृत प्रतियाँ रखेगा या रखवाएगा तथा उनसे सम्बन्धित विशिष्टियाँ एवं विवरण के इन्द्राज हेतु उपाबन्ध-I में प्ररूप सी.बी.-1 में एक रजिस्टर बनाएगा;

(ii) वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों, निर्देशों तथा विनियमों जो -

(क) केन्द्रीय सरकार;

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार द्वारा जारी अथवा बनाए गए हैं का कालानुक्रमिक संग्रहण रखेगा या रखवायेगा तथा उनसे सम्बन्धित विशिष्टियाँ एवं विवरण उपाबन्ध-I के प्ररूप सी.बी.-2 में रजिस्टर में रखेगा;

(iii) आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों, वैधानिक अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों की अधिप्रमाणित प्रतियों का कालानुक्रमिक संग्रहण करेगा तथा उनके सम्बन्धित विशिष्टियाँ एवं विवरण उपाबन्ध-I के प्ररूप सी.बी.-3 में रजिस्टर में रखेगा;

(iv) आयोग के सभी आदेश, निदेश व विनियम बनाये जाने के तत्पश्चात् आयोग के ई-मेल पर उपलब्ध करेगा ; और

(ज) वह, आयोग की ओर से,—

(i) आयोग के विरुद्ध वादों में समन लेगा ; तथा

(ii) आयोग द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में, वादपत्र और अभिबचन हस्ताक्षरित और सत्यापित करेगा ।

(3) सचिव आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा अभिरक्षा में रखेगा ।

(4) सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से, इन विनियमों अथवा अन्यथा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को आयोग के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(5) आयोग को सदैव प्राधिकार होगा कि वह किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार से आवेदन पर, अथवा स्वप्रेरणा से, यदि आयोग को ऐसा किया जाना उपयुक्त लगे, सचिव द्वारा अथवा आयोग के अन्य अधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश अथवा की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपान्तरण, संशोधन, परिवर्तन अथवा अन्यथा बदलाव कर सकेगा ।

(6) जहाँ सचिव अधिनियम अथवा तदधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत उसे सौंपे गए किसी अथवा सभी कृत्यों के निर्वहन में, किसी अथवा सभी कर्तव्यों के अनुपालन करने में, विफल रहता है या लापरवाह रहता है तो अध्यक्ष, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यदि उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के अन्यथा हुई है तो उसे निकाल देगा और यदि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है, तो उसके मूल विभाग को सम्यक् नोटिस देकर, उसे प्रत्यवर्तित करेगा ।

8. शक्तियों का प्रत्योयोजन.—(1) अधिनियम की धारा 14, 18, 86, 91, 94 तथा 181 के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों के सिवाय, आयोग, जैसे वह आवश्यक समझें, लिखित साधारण अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा, किसी भी आयोग के (सदस्य अथवा) अधिकारी को अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्योयोजित कर सकेगा जैसी आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाएँ ।

(2) अध्यक्ष, इन विनियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को आयोग के किसी भी अधिकारी को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्योयोजित कर सकेगा जैसी अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाएँ ।

(3) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किया जाए, सचिव के किसी अथवा सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

अध्याय-2

आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य उपबन्ध

9. आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ.—(1) आयोग, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, जैसा वह उचित समझे, समय समय पर कार्यवाही कर सकेगा ।

(2) आयोग, ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, कार्यवाहियों में भाग लेने तथा उसे सहायता देने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(3) उन सभी मामलों में जिनकी आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन सुनवाई अपेक्षित है, उनकी सुनवाई अधिनियम तथा तदधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी ।

(4) यहाँ आयोग कारणों को अभिलिखित करके अन्यथा आदेशित करता है के सिवाय, अनुज्ञप्तिधारी अथवा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के हक अथवा हित को प्रभावित करने वाले सभी मामलों का निपटारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से सुनवाई करके किया जाएगा ।

(5) उप-विनियम (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में आयोग, यदि समुचित समझे, सुनवाई कर सकता है ।

(6) आयोग, कार्यवाही शुरू करने के विनिश्चय करने से पूर्व पक्षकारों, अथवा उनमें से एक अथवा एक से अधिक के साथ परामर्श कर सकेगा ।

10. आयोग के आगे प्राधिकृत प्रतिनिधि की हाजरी.—(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं, या अपने किसी अधिकारी को अपने स्थान पर, आयोग के समक्ष हाज़िर होने और उसकी पैरवी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष अपनी पैरवी करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित रीति से किसी अधिवक्ता या किसी कानूनी वृत्तिक निकाय के ऐसे सदस्य को जो कि विधिक व्यवसाय का प्रमाणपत्र धारक हो, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) आयोग, समय समय पर, ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने तथा पैरवी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और उसे आयोग को इस प्रयोजन के लिए, किस किसम के प्राधिकार प्रस्तुत करने होंगे, विनिश्चित कर सकेगा ।

(4) उपरोक्त के होने पर भी, आयोग, जैसे आयोग उचित समझे, किसी उपभोक्ता समूह या संगम या ऐसे उपभोक्ता समूह या संगम द्वारा सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों को आयोग की कार्यवाहियों में या कार्यवाहियों के लिये आयोजित आरम्भिक बैठक में, हाज़िर होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(5) आयोग, कार्यवाही को समय पर पूरा करने की दृष्टि से, ऊपर निर्दिष्ट संगमों, समूहों/फोरम को सामुहिक रूप से याचिका/शपथपत्र देने के लिए इकट्ठा होने का निदेश देने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

(6) आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे, संगमों, समूहों, फोरम अथवा निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ पंजीकृत उपभोक्ता संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा ।

(7) अध्यक्ष उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नियुक्त अथवा प्राधिकृत कर सकेगा तथा उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति को ऐसा शुल्क, लागत या खर्च के भुगतान के लिए कार्यवाही के ऐसे पक्षकारों द्वारा वहन करने का, जैसा अध्यक्ष उपयुक्त समझे, निदेश दे सकेगा ।

11. कार्यवाहियों का शुरू होना.—(1) आयोग स्वतः अथवा किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्यवाही शुरू कर सकेगा ।

(2) जब आयोग कार्यवाई शुरू करता है, तो आयोग का कार्यालय सूचना जारी करेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे, तो प्रभावित पक्षकारों को ऐसी सूचना की तामील के लिए और याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर ऐसे प्ररूप में, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, दाखिल किए जाने के निदेश दे सकेगा ।

(3) आयोग, यदि उचित समझे तो, कार्यवाई के विवाद्यको पर टीका टिप्पणियां, ऐसे प्ररूप में जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, आमंत्रित करते हुए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा ।

(4) नोटिस जारी करते समय आयोग स्वतः कार्यवाहियों अथवा अन्य मामलों में आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग मामले में याचिकाकर्ता के रूप में मामले को प्रस्तुत करने के लिए उचित समझे, पदाभिहित कर सकेगा ।

12. आयोग के समक्ष याचिकाएँ.—(1) सभी याचिकाओं में तात्त्विक विशिष्टियों, माँगी गई राहत, लागू विधिक उपबन्धों तथा उक्त राहत के आधार सहित तथ्यों का स्पष्ट तथा संक्षिप्त विवरण होगा।

(2) आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली सभी याचिकाएँ सफेद कागज़ पर पठनीय तथा साफ टंकित, साइक्लोस्टाइल या मुद्रित होनी चाहिए तथा उसका प्रत्येक पृष्ठ क्रम में संख्यांकित होना चाहिए। याचिका के साथ 10 प्रतियाँ अथवा उतनी प्रतियाँ जितनी आयोग निदेशित करे, के साथ दागर की जाएंगी और वे सभी प्रतियाँ हर प्रकार से पूर्ण होंगी। आयोग, इसके अतिरिक्त, जैसे निर्देशित करे, निबन्धन तथा शर्तों पर इलैक्ट्रानिक माध्यम में याचिका को दाखिल करने की भी अपेक्षा कर सकेगा।

(3) याचिका की विषयवस्तु अलग-अलग अनुच्छेदों में समुचित रूप से विभाजित होनी चाहिए, जो कि क्रम से संख्यांकित हों।

(4) याचिका के साथ अभिलेख पुस्तिका (पेपरबुक) जिसमें वे दस्तावेज़ समर्थक आंकड़े और विवरण, जो याचिका में विवादकों से सुसंगत हों, संलग्न होने चाहिए।

(5) याचिका दाखिल करते समय या उससे पूर्व आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क दिया जाएगा।

(6) प्राप्त शुल्क राशि की प्रविष्टि उपाबन्ध-II के अनुसार प्ररूप सी.बी.-4 में बनी विहित पंजिका में होगी।

13. सामान्य शीर्षक.—आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं के और सभी प्रकाशनों तथा सूचनाओं के सामान्य शीर्षक प्ररूप सी.बी.-5 (उपाबन्ध-III) में होंगे।

14. समर्थन में शपथपत्र.—(1) याचिकाएँ, शपथपत्र द्वारा सत्यापित की जाएंगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथपत्र उपाबन्ध-IV में प्ररूप सी.बी.-6 में होंगे :

परन्तु यह कि आयोग, स्वविवेकानुसार, किसी विशेष मामले में शपथपत्र की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकेगा।

(2) प्रत्येक शपथपत्र प्रथम पुरुष में लिखा जायेगा तथा उसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय और पता तथा वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है दिया जायेगा तथा शपथ-पत्र लेने के लिए और प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप में प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षरित तथा शपथित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक शपथ-पत्र में कथन स्पष्ट तथा अलग से उपदर्शित किए जाएंगे जो -

- (i) अभिसाक्षी की जानकारी,
- (ii) अभिसाक्षी को प्राप्त सूचना; तथा
- (iii) अभिसाक्षी के विश्वास;

के अनुसार सत्य है ।

(4) शपथ-पत्र में यहां किसी कथन को अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य कहा गया हो, वहाँ शपथ-पत्र सूचना में स्रोत भी प्रकट किया जायेगा तथा एक कथन भी संलग्न किया जायेगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि उक्त सूचना सत्य है ।

15. याचिकाओं का प्रस्तुतिकरण तथा जाँच.—(1) सभी याचिकाओं की दस (10) प्रतियाँ दाखिल की जाएंगी तथा याचिका का प्रत्येक सेट सभी प्रकार से पूर्ण होगा ।

(2) सभी याचिकाएँ व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा मुख्यालय में अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थान या स्थानों पर नियत समय के दौरान आयोग द्वारा इस निमित्त पदामिहित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी । आयोग को याचिकाएँ उपरोक्त स्थानों पर रजिस्ट्री रसीद डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है ।

(3) अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा, तथा प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर, याचिका के साथ अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज भी दाखिल किए जाएँगे। विधि व्यवसायी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो आयोग के समक्ष किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है प्ररूप सी.बी.-7 (उपाबन्ध-V) पर उपसंजात होने का ज्ञापन दाखिल करेगा ।

(4) याचिका के प्रस्तुतिकरण तथा प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग के कार्यालय द्वारा प्ररूप सी.बी.-8 (उपाबन्ध-VI) में इस निमित्त रखी गई पंजी में सम्यक् रूप से की जाएगी ।

(5) याचिका प्राप्ति पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी मुहर लगाकर तथा जिस तारीख को याचिका प्रस्तुत की गई है वह तारीख डालकर प्राप्ति की पावती देगा तथा याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ प्राप्ति सूचना भी देगा । याचिका यदि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को याचिका आयोग के कार्यालय में वास्तविक रूप से प्राप्त होती है वही तारीख याचिका के प्रस्तुतिकरण को तारीख मानी जाएगी ।

(6) प्राप्तकर्ता अधिकारी किसी ऐसी याचिका को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जो अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों या आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप नहीं है या जिसमें

कोई अन्य त्रुटि है जो विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुसार न होकर किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत की गई है :

परन्तु किसी याचिका को (अभिबचनों में या प्रस्तुतिकरण में त्रुटियों की वजह से) याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को अनुज्ञात समय में त्रुटि सुधारने के लिए अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा । प्राप्तकर्ता अधिकारी दाखिल की गई याचिका की त्रुटियों को तथा कालावधि, जिसमें त्रुटियाँ सुधारी जा सकती है, याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को प्ररूप सी.बी.-9 (उपाबन्ध-VII) में लिखित रूप से सूचित करेगा ।

(7) याचिका के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति यह प्रार्थना कर सकता है कि मामले को समुचित आदेशों के लिए आयोग के सचिव के समक्ष रखा जाए ।

(8) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त पदाभिहित सदस्य को, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका मांगने का हक होगा तथा वह याचिका के प्रस्तुतिकरण और मंजूरी से सम्बन्धित ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

(9) यदि जाँच करने पर, याचिका नामंजूर नहीं की जाती है अथवा आयोग के सचिव या अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित आयोग का सदस्य नामंजूरी के किसी आदेश को उपान्तरित करता है, तो याचिका सम्यक् रूप से पंजीकृत की जाएगी तथा आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति में इसे एक संख्या दी जाएगी ।

(10) जैसे ही याचिका तथा सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर दिए जाते हैं तथा त्रुटियाँ और अपत्तियाँ, यदि कोई हों तो, दूर कर दी जाती हैं तथा याचिका की जाँच कर ली गई है तथा उसे संख्याकित कर दिया गया है तो याचिका आयोग के समक्ष रखी जाएगी :

परन्तु किसी व्यक्तिक उपभोक्ता, उपभोक्ता वर्ग या उपभोक्ता संगठन द्वारा शिकायत की दशा में आयोग सचिव याचिका की अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (5) तथा उक्त उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा बनाए विनियमों के प्रयोजन हेतु उपभोक्ताओं की शिकायतों के दूर करने के लिए प्रस्थापित फोरम के पास भेज सकेगा ।

(11) आयोग, याचिका दाखिल करने वाले पक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना भी याचिका को सुनवाई हेतु दाखिल कर सकता है । आयोग सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना दाखिल न करने के आदेश पारित नहीं करेगा । आयोग यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें वह चाहे याचिका दाखिल की सुनवाई के लिए सूचना जारी कर सकता है ।

(12) यदि आयोग याचिका स्वीकार करता है तो प्रयार्थी (प्रयार्थियों) तथा अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्ररूपों में, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करे, याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तथा याचिका को यथास्थिति आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए रखने के ऐसे आदेश तथा निर्देश दे सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

16. आयोग द्वारा जारी सूचना तथा आदेशिका की तामील।—(1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाली किसी सूचना या आदेशिका या तलवनामें की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी —

- (i) आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट मामले के पक्षकार द्वारा अपने तौर पर तामील;
- (ii) किसी संदेशवाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना ;
- (iii) पावती प्राप्य सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ;
- (iv) उन मामलों में, जहां आयोग की यह संतुष्टि हो गई है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त रीति से नोटिस, आदेशिका इत्यादि तामील करना व्यावहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा;
- (v) किसी अन्य प्रकार से, जैसा आयोग उचित समझे ।

(2) कोई नोटिस या आदेशिका, जिसकी तामील की जानी अपेक्षित है या किसी व्यक्ति को पहुँचाई जानी है उस व्यक्ति या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर या उस स्थान पर जहां पर वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्रायः व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, को भेजी जा सकेगी ।

(3) उस दशा में जब आयोग के समक्ष कोई मामला लम्बित है तथा तामील किए जाने वाले व्यक्ति ने किसी अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को, मामले में प्रस्तुत होने या स्वयं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो अभिकर्ता को सभी मामलों में संबंधित पक्षकार की ओर से नोटिस तथा आदेशिकाएँ तामील होने के लिए सशक्त समझा जाएगा तथा ऐसे अभिकर्ता का प्रतिनिधि को की गई तामील को, तामील किए जाने वाले पर सम्यक् तामील माना जाएगा । ऐसे अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सूचना की तामील के बारे में सम्यक् रूप में अवगत करे ।

(4) यदि नोटिस कार्यवाहियों में किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दिया है तो वह पक्षकार तामील के सम्बन्ध में शपथ-पत्र आयोग में आदेशिका तथा नोटिस के तामील तथा रीति का विवरण देते हुए दाखिल करेगा ।

(5) यदि किसी याचिका को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करना अपेक्षित हो तो उसे ऐसी अवधि में, जैसी आयोग निर्दिष्ट करें, में प्रकाशित किया जाएगा तथा उसका प्रकाशन, जब तक कि आयोग अन्यथा निर्दिष्ट न करें, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में व्यापक रूप में परिचालित अंग्रेजी भाषा तथा हिन्दी भाषा के दैनिक समाचारपत्र के प्रत्येक के एक अंक में किया जाएगा :

परन्तु यह कि प्रकाशन, सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व, जो सात (7) दिन से कम न हो, किया जाएगा ।

(6) आयोग किसी अन्य प्रकार से, जैसे उचित समझे, भी तामील कर सकेगा अथवा तामील करने के लिए निर्देश दे सकेगा ।

(7) प्रत्येक मामले में आयोग को यह निर्णय करने का हक होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार की तामील/प्रकाशन के व्यय का वहन करेगा ।

(8) अधिनियम अथवा इन विनियमों में अथवा इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा उन निदेशों, जो आयोग अथवा सचिव या आयोग द्वारा जिसे इस निमित्त पदाभिहित किया जाए, द्वारा जारी किए जाएँ, के अधीन रहते हुए, याचिकाकर्ता, आवदेक तथा अन्य व्यक्ति जिसे आयोग उत्तरदायित्व सौंपे, सूचनाओं, समनों, आदेशिकाओं की तामील तथा उन सूचनाओं तथा तामीलों जिनका प्रकाशन अपेक्षित है, के प्रकाशन की व्यवस्था करेगा ।

(9) नोटिस, समन या आदेशिकाओं की तामील या उनके प्रकाशन के सम्बन्ध में विनियमों या आयोग के निदेशों की अनुपालना न होने पर आयोग या याचिका खार्ज कर सकता है या ऐसे अन्य या अतिरिक्त निदेश दे सकता है, जिन्हें वह ठीक समझें ।

(10) जबकि आयोग की यह सन्तुष्टि हो गई हो कि तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है तब व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि होने की वजह से किसी तामील या प्रकाशन को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

(11) तामील अथवा प्रकाशन में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब तक अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग उठाई गई आपत्ति पर यह न समझे कि उस तामील अथवा प्रकाशन में त्रुटि या अनियमितता के कारण वास्तव में अन्याय हुआ है या ऐसे करने के लिए अन्य पर्याप्त कारण हैं ।

17. उत्तर विरोध, आपत्तियों इत्यादि को दाखिल करना.— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच का नोटिस या याचिका जारी की गई है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है), जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहता है, उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को, जिन पर निर्भर किया गया है, की दस प्रतियों में अथवा उतनी प्रतियों में तथा ऐसी अवधि के भीतर, जैसे आयोग विनिर्दिष्ट करें, दाखिल करेगा ।

(2) दाखिल किए गए उत्तर में प्रत्यर्थी जाँच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप में स्वीकार या अस्वीकार या स्पष्ट करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेगा जिन्हें वह न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझता है ।

(3) उत्तर उसी रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथपत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिस रीति में याचिका की जाती है। प्रत्यर्थी यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या वह कार्यवाहियों में शामिल होना चाहता है तथा उसे मौखिक रूप में सुना जाए।

(4) प्रत्यर्थी उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की सच्ची प्रति के रूप में सभ्य रूप में सत्यापित प्रतियों के साथ याचिकाकर्ता को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा उत्तर दाखिल करते समय आयोग के कार्यालय में ऐसी तामील का प्रमाण भी दाखिल करेगा।

(5) यदि प्रत्यर्थी मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है, तो आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकता है। उत्तर दाखिल करने की ऊपरी वर्णित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए लागू होगी।

(6) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति (ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर जिन्हें उत्तर मानते हुए नोटिस, आदेशिकाएँ इत्यादि जारी की गई हैं) जो आयोग के समक्ष लम्बित मामले में इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रकाशन के अनुसरण में आपत्तियों या टिप्पणियों दाखिल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर आपत्तियों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित अधिकारी को पहुँचाएगा।

(7) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रतिभागिता मामले की कार्यवाहियों तथा निर्णय में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दे सकता है।

(8) जब तक कि आयोग ने अनुज्ञा न दी हो, आपत्ति या टिप्पणियाँ दाखिल करने वाला व्यक्ति कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा। तथापि, आयोग आपत्तियों या टिप्पणियों को ध्यान में रखेगा।

18. मामले की सुनवाई.—(1) आयोग मामले की सुनवाई के लिए, अधिनियम में निर्दिष्ट समय निर्धारण अपेक्षाओं, अन्यथा मामले की सत्वर निर्णय हेतु आवश्यकताओं, के अनुरूप प्रक्रम, रीति, स्थान, तारीख और समय निर्धारित कर सकता है।

(2) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विनिश्चय कर सकता है या पक्षकारों को शपथपत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(3) यदि आयोग, शपथपत्र द्वारा पक्षकार को साक्ष्य देने का निर्देश देता है तो आयोग यदि आवश्यक समझे तो दूसरे पक्षकार को शपथपत्र देने वाले अभिसाक्षी की प्रति-परीक्षा करने का अवसर दे सकता है ।

(4) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदामिहित व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य लिपिवद्ध करने के लिए निर्देश दे सकता है ।

(5) आयोग, उसके समक्ष कार्यवाहियों में, जैसे समुचित समझे, पक्षकारों को मामले के तर्कों या निवेदनों की लिखित टीप दाखिल करने का निर्देश दे सकता है ।

19. आयोग की अतिरिक्त जानकारी इत्यादि मांगने की शक्तियाँ.—(1) आयोग किसी भी मामले पर आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय पक्षकारों या उनमें से किसी एक या अधिक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग उपयुक्त समझे, ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है जिन्हें आयोग स्वयं को आदेशों को पारित करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से आवश्यक समझे ।

(2) आयोग को साक्ष्यों की उपस्थिति, किसी अभिलेख की खोज व प्रस्तुति, या अन्य भौतिक वस्तुओं की साक्ष्य में प्रस्तुति, किसी सार्वजनिक अभिलेख की किसी कार्यालय से मांग, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा पुस्तकों व अभिलेखों की जाँच व अन्य पत्रजात या सूचना जो किसी व्यक्ति के अभिरक्षण या नियन्त्रण में है की प्रस्तुति के निर्देश उचित लगने पर जारी करने का अधिकार होगा ।

(3) आयोग, यदि समीचीन समझे तो किसी भी पक्षकार अथवा उप-विनियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, किसी पक्षकार अथवा उक्त उप-विनियम के अधीन अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के बारे में, और दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा ।

(4) आयोग, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति को बुलवा और हाजिर करवा सकेगा तथा उसका शपथ पर ब्यान ले सकेगा ।

(5) आयोग शपथ-पत्र से साक्ष्य ले सकेगा ।

20. विवादकों को अन्यो को संदर्भित करना.—(1) आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मामले के ऐसे विवादक या विवादकों को, जिन्हें वह उचित समझता है, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं, परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं हैं,

जिन्हें आयोग सुविज्ञ अथवा विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिए अर्हित समझता है, संदर्भित करने का हकदार होगा ।

(2) आयोग, समय-समय पर किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या दशा या वहाँ की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित हैं, परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं हैं, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) आयोग, यदि ठीक समझे तो पक्षकारों को, उप-विनियम (1) अथवा (2) में पदाभिहित व्यक्तियों के सम्मुख निर्दिष्ट विवादकों व मामलों पर अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है ।

(4) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त प्रतिवेदन या सलाह मामले के अभिलेखों का भाग होगी तथा आयोग द्वारा पदाभिहित व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिवेदन या सलाह की प्रतियाँ पक्षकारों को दी जाएँगी । पक्षकार प्रतिवेदन या सलाह के समर्थन या विरोध में अपने पक्ष का विवरण दाखिल करने के हकदार होंगे ।

(5) आयोग, मामले का विनिश्चय करते समय, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन या सलाह, पक्षकारों द्वारा दाखिल उत्तर को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो प्रतिवेदन या सलाह देने वाले व्यक्ति का बयान लेगा :

परन्तु यह कि दिया गया प्रतिवेदन अथवा सलाह आयोग के लिए बाध्य नहीं होगी और जैसे वह समुचित समझें, विनिश्चय कर सकेगा ।

21. पक्षकार के उपस्थित न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) यदि कोई मामला सुनवाई के लिए लाया जाए और सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों में से कोई या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि पेश न हो तो आयोग, स्वविवेकाधिकार से, याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के, जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए यदि दूसरा पक्षकार अनुपस्थित है, याचिका की सुनवाई कर सकेगा और उस पर विनिश्चय दे सकेगा ।

(2) जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता तथा यदि आयोग की यह सन्तुष्टि हो जाए कि जब याचिका सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, तो आयोग उन शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझें, आदेश वापस कर सकता है ।

22. आयोग के आदेश.—(1) आयोग याचिका पर आदेशों को पारित करेगा तथा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, जिन्होंने मामले की सुनवाई की हो, आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(2) आदेश, निर्णय घोषित करते समय, दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा । बाद में उक्त आदेशों में उन्चेक्षा या लोप से हुई लिपिकीय या गणितीय गलती के सिवाए, कुछ भी परिवर्तन या जोड़ा नहीं जाएगा ।

(3) आदेश में संक्षिप्त तथ्य विवरण तथा प्रति-विवरण, अवधार्य प्रश्न अथवा विवाद्यक, उन पर लिया गया निर्णय तथा उक्त निर्णय के कारण (आधार) अंतर्विष्ट होंगे ।

(4) आयोग द्वारा आदेशों के समर्थन में दिए गए कारण, जिसमें भिन्न राय रखने वाले सदस्य द्वारा दिये गए कारण भी आते हैं, यदि कोई हो, आदेश का भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण तथा प्रतियों के प्रदाय के लिए उपलब्ध होंगे ।

(5) आयोग को, उसके सन्मुख किसी कार्यवाही, सुनवाई अथवा मामले में इस प्रकार के अंतरिम आदेश अथवा निदेश, जिन्हें वह उचित समझे, देने की शक्ति होगी ।

(6) आयोग द्वारा जारी या संसूचित किए गए सभी आदेश, निर्देश तथा निर्णय सचिव के या अध्यक्ष द्वारा इस आशय से सशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग के कार्यालय की मुद्रा अंकित होगी ।

(7) आयोग के सभी अंतिम/आदेश कार्यवाही के सभी पक्षकारों को सचिव के या अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा इस बाबत सशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किए जाएंगे ।

23. कार्यवाही के अभिलेखों का निरीक्षण.—(1) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों का निरीक्षण कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित हो जाने के पश्चात्, पक्षकारों अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा, फीस के संदाय तथा ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन, जो आयोग द्वारा निदेशित की जाएं, साधिकार किया जा सकेगा ।

(2) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों का निरीक्षण, कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित हो जाने के पश्चात्, उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, आवेदन के पक्षकारों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन, जो समय-समय पर आयोग द्वारा निदेशित की जाएं और जिनमें निरीक्षण के समय, स्थान और रीति तथा फीस के संदाय सम्बन्धी शर्तें भी सम्मिलित हैं, किया जा सकेगा ।

(3) दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन सी.बी.-10 (उपाबन्ध-VII) में यथाविहित प्ररूप पर इन विनियमों में अनुसूची में यथाविहित देय फीस प्रति निरीक्षण प्रतिदिन, सचिव हिमाचल प्रदेश

विद्युत विनियामक आयोग, शिमला, के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश (पे-आर्डर) के साथ दिया जाएगा ।

(4) अभिलेखों का निरीक्षण इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के सामने की उपस्थिति में किसी भी कार्य दिवस पर सामान्यतः 2.30 बजे से 4.30 बजे अपराह्न के बीच अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(5) अभिलेखा निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अभिलेखों को किसी प्रकार से विस्थापित, विकृत, अस्त-व्यस्त या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा ।

(6) पर्यवेक्षक अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी भी समय यदि उस की राय में आगे निरीक्षण से अभिलेखों को क्षति होने की सम्भावना है तो निरीक्षण को रोक सकता है और इस संदर्भ में सचिव को तत्काल सूचित करेगा और अगले आदेश प्राप्त करेगा ।

(7) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्ररूप सी.बी.-११ (उपाबन्ध- IX) पर आधारित एक रजिस्टर रखा जाएगा ।

24. अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ देना.—(1) कोई व्यक्ति, आदेशों, विनिश्चियों, निर्देशों और आयोग द्वारा उनके समर्थन में दिये गये कारणों की प्रतियाँ लेने का हकदार होगा और साथ ही ऐसे अभिवचनों, कागजातों तथा आयोग के अभिलेखों के अन्य भाग की, जिनका वह फीस के संदाय पर निरीक्षण कर सकता है और ऐसी अन्य शर्तों, जिन्हें आयोग निर्देशित करे, के अनुपालन करने पर, प्रतियाँ लेने का हकदार होगा ।

(2) प्रत्येक आदेश, जो अंतरिम राहत तथा अन्तिम आदेश को स्वीकृत, अस्वीकृत या शोधित करता हो, की प्रतिलिपि पक्षकारों को निशुल्क भेजी जाएगी :

परन्तु यह कि जब तक आयोग द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, अन्तिम आदेश की प्रति ऐसी किसी पक्षकार को नहीं भेजी जाएगी जो उपस्थित न हुआ हो ।

(3) आयोग के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति या आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के अभिलेख के भाग रूप की प्रति कोई दस्तावेज अभिप्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति विहित प्रारूप सी.बी.-12 (उपाबन्ध-X) में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(4) आवेदन प्रति का रजिस्टर प्ररूप सी.बी.-13 (उपाबन्ध-XI) में रखा जाएगा ।

(5) प्रमाणित प्रतियाँ, यथासाध्य, उसी क्रम में तैयार की जाएंगी जिस क्रम में आवेदित प्रति के रजिस्टर में आवेदनों की प्रविष्टि की गई हो ।

(6) प्रमाणित प्रतियां फोटोकॉपी करने वाली प्रक्रिया या टाइपिंग द्वारा तैयार की जाएगी और जब प्रति इस प्रकार तैयार की जाती है तो, उसकी प्रति तैयार करने वाला व्यक्ति अपना यह सन्तुष्टि करने के लिए कि प्रति निष्ठापूर्वक तैयार की गई है और वांछित दस्तावेज को पढ़े जाने योग्य प्रत्युत्पादित किया गया है, द्वारा मिलान किया जाएगा ।

(7) प्रतिलिपि के अंतिम पृष्ठ के पीछे निम्नवत पृष्ठांकित किया जाएगा:—

- (क) आवेदन का संख्यांक
- (ख) आवेदक का नाम
- (ग) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
- (घ) पृष्ठों की संख्या
- (ङ) प्रति फीस का प्रभार
- (च) प्रति तैयार होने की तारीख
- (छ) जारी करने की तारीख

(8) पृष्ठांकन इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई रबर की मोहर की सहायता से किया जाएगा। प्रविष्टियां स्याही से होंगी ।

(9) प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए देय फीस, प्रत्येक पृष्ठ में शब्दों/पंक्तियों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, इन विनियमों में अनुसूची में यथाविहित प्रति पृष्ठ होगी ।

अध्याय-3

अन्वेषण, जाँच, सूचना एकत्रण तथा आदेशों इत्यादि का प्रवर्तन

25. सूचना एकत्रण.—(1) आयोग, निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना एकत्रण, जाँच, अन्वेषण, प्रवेश तलाशी, अभिग्रहण के लिए अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे आदेश, जिन्हें वह अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ठीक समझे, दे सकता है :—

- (क) यदि आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के अधीन किसी जाँच अथवा न्यायनिर्णयन की विषयवस्तु के सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है तो आयोग किसी अधिकारी को, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, आयोग की ओर से, किसी भवन अथवा स्थान में प्रवेश करने तथा उक्त दस्तावेज को कब्जे में लेने अथवा उनके उद्धरण अथवा उनकी प्रतियाँ लेने के लिए विशेषतः प्राधिकृत कर सकेगा ;
- (ख) यदि आयोग की तुष्टी हो जाती है कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी अनुज्ञप्ति की शर्तों, अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो आयोग, अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा किसी भी अन्वेषण प्राधिकारी, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, को अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी के कामकाज का अन्वेषण करने तथा आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिये निदेश दे सकेगा । इस प्रयोजन के लिए आयोग अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों को अपनी पुस्तकों में न्यूनतम सूचना रखने के लिए निदेश दे सकेगा तथा यह भी आदेश दे सकेगा कि उक्त सूचना किस रीति में रखी जाए तथा उसकी जाँच और सत्यापन किस तरह किया जाए ।
- (ग) आयोग, किसी भी समय अधिनियम के अधीन, आयोग की अधिकारिता के भीतर किसी मामले के सम्बन्ध में, सचिव अथवा एक या अधिक अधिकारियों अथवा सलाहकारों या किसी अन्य व्यक्ति को, जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता है, अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है ;
- (घ) आयोग, उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य निदेश, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, दे सकता है तथा ऐसी समय-सीमा निर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर प्रतिवेदन अथवा सूचना प्रस्तुत की जानी है ;
- (ङ) आयोग, सचिव अथवा किसी अधिकारी को ऐसे निदेश जारी कर सकता है या प्राधिकृत कर सकता है कि वह उसकी ओर से किसी व्यक्ति को आदेश जारी कर

सके कि वह, अधिनियम में यथाउपबन्धित, बहियों को आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को जाँच व अभिरक्षण हेतु प्रस्तुत करे और सूचना दें ।

(च) आयोग, किसी ऐसी जानकारी, विशिष्टियों अथवा दस्तावेजों के, जिन्हें अयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में आवश्यक समझता हो, एकत्रण के प्रयोजन के लिए ऐसे निदेश, जिन्हें आयोग समुचित समझे, जारी कर सकता है और अधिनियम में उपबन्धित किसी एक या अधिक रीतियों का अनुसरण कर सकता है ;

(छ) यदि प्राप्त की कोई रिपोर्ट या जानकारी आयोग को अपर्याप्त या अधूरी प्रतीत होती है तो आयोग या सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, अतिरिक्त जाँच करने, रिपोर्ट तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है ;

(ज) आयोग, उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस प्रकार के आनुषंगिक, परिणामिक तथा अनुपूरक मामलों पर, जिन्हें सुसंगत समझा जाए, ध्यान देने के लिए निदेश दे सकता है ।

(2) अधिनियम तथा विनियमों के अधीन कृत्यों के निर्वहन हेतु यदि आयोग उचित समझता है, तो जाँच का एक नोटिस जारी किए जाने और इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबन्धित रीति के अनुसार मामले पर कार्यवाही किए जाने के निदेश दे सकता है ।

(3) आयोग, किसी नियुक्त अन्वेषण प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने तथा यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी को रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने का अवसर देने के उपरान्त, उक्त रिपोर्ट से उद्भूत मामले के बारे में अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कम्पनी से ऐसी कार्यवाही, जो आयोग उचित समझे, करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(4) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी अथवा यथास्थिति उत्पादन कम्पनी को युक्तियुक्त नोटिस देने के उपरान्त, अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अथवा उसके ऐसे अंश, जो आयोग को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकाशित कर सकेगा ।

26. विशेषज्ञीय सहयोग.—(1) आयोग किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, अभियन्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता, सर्वेक्षक तथा अन्य तकनीकी तथा वृत्रिक व्यक्तियों का, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सहयोग ले सकता है तथा उनको किसी भी मामले अथवा विवादक का अध्ययन, अन्वेषण, जाँच करने तथा प्रतिवेदन या प्रतिवेदनों को देने अथवा सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है । आयोग इस प्रकार के वृत्तिकों की नियुक्ति के लिए निबन्धनों एवं शर्तों का निर्धारण कर सकता है ।

(2) यदि विनियमों या उसके किसी भाग के निबन्धनों के अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन अथवा सूचना पर, किसी कार्यवाही में आयोग की राय अथवा दृष्टिकोण तैयार करने के लिए निर्भर किए

जाने का प्रस्ताव हो तो कार्यवाही के पक्षकारों को प्रतिवेदन अथवा सूचना पर आपत्तियाँ दाखिल करने तथा निवेदन करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3) आयोग उपभोक्ता, जब कभी भी यह उचित समझे, उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त की गई संस्था, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, अभियन्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता, सर्वेक्षक तथा अन्य तकनीकी तथा वृत्तिक व्यक्ति को ऐसा शुल्क, लागत या खर्च के भुगतान के लिए कार्यवाही के ऐसे पक्षकारों द्वारा वहन करने का, जैसा आयोग उपर्युक्त समझे, निर्देश दे सकेगा ।

अध्याय-4

अनुज्ञप्ति

27. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.—(1) कोई व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत पारेषण, वितरण अथवा व्यापार में लगना चाहता है, उस प्ररूप पर तथा उस रीति से, जो आयोग निर्दिष्ट करे, समुचित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन देगा तथा उसके साथ ऐसी फीस, जो इस प्रयोजन के लिए विहित की जाए, संदत्त करेगा ।

(2) आयोग द्वारा जारी की जाने वाली वितरण अनुज्ञप्तियों के मोटे तौर पर दो प्रवर्ग होंगे, नामतः—

(क) प्रवर्ग-I अनुज्ञप्ति—यहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा और उसे प्राप्त करेगा ।

(ख) प्रवर्ग-II अनुज्ञप्ति—यहाँ इन विनियमों में अन्तर्विष्ट शर्तों के अनुपालन के बल पर, विनियम 48 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया और आयोग द्वारा उसे वितरण अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई समझी जाती है ।

(3) आयोग, यदि समुचित समझें, अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन आमन्त्रित करने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन दे सकता है या अन्यथा ऐसी अन्य समुचित रीति से, जैसा आयोग विनिश्चित करें, अधिसूचित कर सकता है ।

(4) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन अधिनियम के उपबन्धों और इन विनियमों के अनुसार इन विनियमों के (उपाबन्ध—XII से XIV तक) यथा लागू प्ररूप 14, 15 तथा 16 पर दिया जाएगा और प्राधिकृत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(5) अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पर अनुज्ञप्ति के आवेदक द्वारा या उसके निमित्त हस्ताक्षर किये जायेंगे और सचिव या ऐसे अधिकारी को जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे सम्बोधित किया जायेगा और आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(क) आवरण—पृष्ठ पर मुद्रित आवेदक और उसके अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम और पते सहित प्रोफार्मा जिसमें वे विशिष्ट निबन्धन व शर्तें, जो आवेदक अनुज्ञप्ति में सम्मिलित करना चाहता है, तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट साधारण शर्तों के वांछित उपवर्जन का विवरण और उसका न्यायोचित्य अन्तर्विष्ट हो, की दस अथवा उतनी प्रतियाँ जितनी आयोग निर्दिष्ट करे;

- (ख) आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित पारेषण अथवा वितरण क्षेत्र के प्रत्येक मान-चित्र की दस अथवा उतनी प्रतियाँ जितनी आयोग निर्दिष्ट करे ;
- (ग) विवरणी, जिसमें भूमि अथवा आस्तियों का, जिनको आवेदक अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव करता है और उक्त अर्जन के साधनों का ब्यौरा दिया हो;
- (घ) कारवार योजना, जिसके साथ उपयोगिता के सम्बन्ध में व्यय किए जाने वाली प्रस्तावित पूंजी; पूंजीगत व्यय के लिए आर्थिक साधन, परिणामस्वरूप दक्ष अभिवृद्धि तथा आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य विशिष्टियों की अनुमानित विवरणियों हो, की एक प्रति;
- (ङ) कम्पनी की दशा में संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद अथवा अन्य विधिक आस्तित्व की दशा में उसके निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की एक प्रति;
- (च) यथापेक्षित वार्षिक विनिर्दिष्ट फीस के संदाय अभिस्वीकृति की रसीद ।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में काम करना चाहता है, आवेदन करते ही आवेदन की एक प्रति राज्य पारेषण उपयोगिता को अग्रेषित करेगा । राज्य पारेषण उपयोगिता आवेदन की पावती देगा और उक्त आवेदन के प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर आयोग को अपनी सिफारिशें, यदि कोई हों, भेजेगा ।

28. प्रोफार्मा की विषय वस्तु.—विनियम 27 में निर्दिष्ट प्रोफार्मों में वे विशिष्टियाँ, जो उपाबन्ध XII, XIII तथा XIV के प्ररूप सी.बी.-14,15 या 16 में अन्तर्विष्ट हैं, तथा विशेषतः निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी:—

- (क) प्रस्तावित क्रियाकलापों का द्योतक संक्षिप्त शीर्ष जिसके साथ आवेदक का पता और विवरण हो और यदि आवेदक कम्पनी है तो कम्पनी के सभी निदेशकों का नाम;
- (ख) आवेदित अनुज्ञप्ति की प्रकृति;
- (ग) प्रस्तावित सेवा क्षेत्र का स्थान;
- (घ) आवेदित अनुज्ञप्तियों में, आयोग द्वारा अधिकथित साधारण शर्तों तथा विनिर्दिष्ट शर्तों को भी (यदि कोई हों), सम्मिलित करने तथा उनमें चाहे गए पथांतर का औचित्य;
- (ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करे ।

29. अनुज्ञप्ति शर्तें.—(1) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्ति साधारण शर्तें) विनियम, 2004, या हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति साधारण शर्तें) विनियम, 2004, या हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति साधारण शर्तें) विनियम, 2004 में अन्तर्विष्ट साधारण शर्तें, जिनके

अध्याधीन प्रत्येक प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, और उन शर्तों की स्वीकृति का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) आयोग, उन विशिष्ट शर्तों को, जिनके अध्याधीन आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी, विनिश्चित कर सकेगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन देता है, तकनीकी अपेक्षा, पूँजी पर्याप्ता अपेक्षा, तथा उधार पात्रता की शर्तें सम्यक् रूप में पूरी करेगा और अधिनियम की धारा 52 के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य के निर्वहन करने की भी सहमति देगा ।

(4) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों तथा अपेक्षाओं को सम्यक् रूप में पूरा करेगा ।

30. आवेदन की अभिस्वीकृति.—आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख लिख लेगा और प्राप्ति की तारीख वर्णित करते हुए आवेदक को अभिस्वीकृति भेजेगा ।

31. मानचित्रों और प्रोफार्मा की प्रतियाँ का लोक निरीक्षण.—आवेदक अपने कार्यालय तथा आयोग द्वारा यथाभिहित अन्य स्थान में विनियम 27 के उप-विनियम(5) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ रखेगा और उनके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को उक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ मूल्य पर, जो फोटो प्रतिलिपि सामान्य खर्च से अधिक न हो, उपलब्ध करेगा ।

32. अतिरिक्त सूचना मांगना.—आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा कोई अन्य पदाभिहित अधिकारी आवेदन की संवीक्षा करने पर आवेदक से अपेक्षित कर सकता है कि वह विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी अतिरिक्त सूचना या विशिष्टियाँ या दस्तावेज, जिन्हें आवेदन के निपटाने के प्रयोजन से आयोग आवश्यक समझे, दे ।

33. आवेदन के सम्यक् दाखिल करने को अधिसूचित करना.—यदि आयोग आवेदन को पूर्ण पाए और अपेक्षित सूचना, विशिष्टियाँ और दस्तावेज उसके साथ हों, आवेदक ने आवेदन करने की और सूचना, विशिष्टियाँ और दस्तावेजों को देने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो, तो आयोग या सचिव या इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन पर विधि में व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जा सकता है और आवेदक को इसके बारे में सूचित करेगा ।

34. आवेदन की विषय का प्रकाशन.—(1) आवेदक आवेदन के दाखिल तथा संख्याकित किए जाने की तारीख से 7 (सात) दिन के भीतर, प्ररूप सी.बी.-17 (उपाबन्ध-XV) में

विनिर्दिष्ट प्ररूप में उन विशिष्टियों सहित तथा उस रीति से जैसे आयोग द्वारा निर्दिष्ट करे, आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा ।

(2) विज्ञापन का प्रारम्भ संक्षिप्त शीर्ष से होगा जो आवेदन में दिये गये शीर्ष से मेल खाता हो और उसमें उन कार्यालयों के पते होंगे जिन में निर्दिष्ट मानचित्रों और दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सके और प्रतियों का क्रय किया जा सके और यह भी विवरण होगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, उपयोगिता या व्यक्ति, जो आवेदन के सन्दर्भ में आयोग को कोई प्रतिवेदन देने का इच्छुक हो, ऐसे अधिकारी को जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे, पत्र द्वारा प्रथम विज्ञापन के निर्गत होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसा कर सकता है ।

35. आवेदन के नोटस की तामील.—(1) आयोग निदेश दे सकता है कि आवेदन के नोटस की केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति या निकाय पर, जिसे आयोग ऐसी अन्य रीति से, जैसे आयोग समुचित समझे, तामील की जाए ।

(2) आवेदक, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन की आयोग द्वारा सुनवाई से पूर्व, अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा(2) के खण्ड (ii) के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करेगा तथा उसे प्राप्त करेगा ।

36. आपत्तियाँ.—(1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आपत्ति करने का इरादा करने वाला कोई भी व्यक्ति, आवेदक द्वारा नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, आपत्ति दाखिल करेगा । आपत्ति उत्तर के रूप में दाखिल की जायेगी और उत्तर के सम्बन्ध में अध्याय-2 के उपबन्ध ऐसी आपत्तियों के दाखिल करने पर लागू होंगे ।

(2) कोई व्यक्ति, जो प्रस्तावित अनुज्ञप्ति शर्तों में किसी संशोधन को करने की इच्छा करता है, आवेदक को अथवा ऐसे अधिकारी को, जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे, तथा आयोग द्वारा आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर, संशोधनों का विवरण देगा ।

37. स्थानीय जाँच और सुनवाई.—(1) यदि आवेदक ने प्रस्तावित आवेदन के नोटिस के प्रकाशन के लिए सम्यक् व्यवस्था कर ली है और आपत्ति दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है और यदि आवेदक ने केन्द्र सरकार से अपेक्षित आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो, आयोग को दे दिया है तो आयोग आवेदन की सुनवाई के लिए कार्यवाही कर सकता है ।

(2) आयोग आवेदन की सुनवाई का नोटिस आवेदक को, उन व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्तियाँ दाखिल की थी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरण, व्यक्ति या निकाय को, जिन्हें आयोग समुचित समझे, देगा ।

(3) आयोग, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में राज्य पारेषण उपयोगिता की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति आवेदित अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर आपत्ति करता है तो आयोग, यदि आवेदक या आपत्तिकर्ता ऐसी इच्छा करे, स्थानीय जाँच करवा सकता है जिसकी सूचना लिखित में आवेदक और आपत्तिकर्ता दोनों को दी जाएगी ।

(5) ऐसी स्थानीय जाँच की स्थिति में की गई स्थानीय जाँच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और आवेदक, इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी या व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे आयोग निर्देश दे, हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(6) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन की सुनवाई की कार्यवाही तत्पश्चात् यथासंभव अध्याय-2 में यथा-व्यवस्थित रीति से की जाएगी ।

38. अनुज्ञप्ति प्रदान करना.— (1) जाँच, यदि कोई हो, और सुनवाई के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या प्रदान न करने का विनिश्चय कर सकता है और यदि वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर और उपान्तरण सहित साधारण अथवा विशिष्ट शर्तों पर, ऐसा कर सकता है ।

(2) जब आयोग ने अनुज्ञप्ति प्रदान करना मन्जूर कर दिया हो तो सचिव, या इस निमित्त आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी, आवेदक को ऐसी मन्जूरी और उस रूप जिसमें अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है तथा आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें, जिनके अन्तर्गत आवेदक द्वारा आरंभिक तथा कालिक संदत की जाने वाली फीस भी है, के विषय में सूचित करेगा ।

(3) आयोग, दो दैनिक समाचार-पत्रों में जैसे आयोग उचित समझे, उस व्यक्ति का, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान करना प्रस्तावित है, नाम व पता देते हुए नोटिस प्रकाशित करेगा ।

(4) आवेदक से लिखित में सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग द्वारा मन्जूर रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकार करने के लिए तैयार है और अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिरोपित शर्तों को आवेदक द्वारा पूरा करने का समाधान हो जाने के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति या उसके भाग या सार को, जैसे आयोग उचित समझे, प्रकाशित करेगा ।

(5) आयोग, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के अव्याविहत पश्चात्, राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे आयोग आवश्यक समझे, को अनुज्ञप्ति की प्रति अग्रेषित करेगा ।

39. अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ की तारीख.—अनुज्ञप्ति उस तारीख से जिसे आयोग निर्दिष्ट करे, प्रारम्भ होगी और, तथापि विधि के अनुसार अनुज्ञप्ति के पूर्वतम प्रतिसंहरण की शर्त के अध्वधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

40. मानचित्रों का जमा किया जाना.—(1) जब अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में इन विनियमों के विनियम 28 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को प्रदर्शित करते हुए मानचित्रों की तीन प्रतियों को आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अधिसूचना के दिनांक से दिनांकित किया जायेगा ।

(2) ऐसे मानचित्रों की एक प्रति उक्त अधिकारी द्वारा जमा किये गये मानचित्रों के रूप में रख ली जायेगी और अन्य दो प्रतियाँ, आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दे दी जायेंगी ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, जब कभी आयोग अपेक्षा करे, मानचित्रों को इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करेगा ।

41. अनुज्ञप्ति की प्रतियों का जमा किया जाना.—(1) प्रत्येक, व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाए, उसके प्रदान किये जाने के तीस दिन के भीतर,—

(क) अनुज्ञप्ति की प्रतियाँ की पर्याप्त संख्या मुद्रित करायेगा ;

(ख) मानचित्रों की पर्याप्त संख्या तैयार करायेगा जिनसे अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रदाय क्षेत्र प्रदर्शित हो;

(ग) प्रदाय क्षेत्र में अपने मुख्यालय पर और अपने स्थानीय कार्यालयों पर (यदि कोई हो) सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी अनुज्ञप्ति और मानचित्रों की प्रति को लोक निरीक्षण के लिये प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति की एक प्रति प्रदाय क्षेत्र में (प्रत्येक स्थानीय निकाय को) निःशुल्क देगा और अनुज्ञप्ति की मुद्रित प्रतियों की उन व्यक्तियों के लिये जो उसके लिये आवेदन करें, ऐसे मूल्य पर, जो सामान्य फोटो प्रतिलिपि खर्च से अधिक न हो, बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था भी करेगा ।

42. लेखों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अपनी उपयोगिता के लेखों को प्रत्येक वर्ष मार्च के 31वें दिन तक तैयार करवायेगा ।

(2) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के निदेशानुसार अपने लेखों का वार्षिक विवरण उपर्युक्त तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी अवधि के भीतर जैसा आयोग का यह समाधान हो जाने पर कि अनुज्ञात समय अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर किसी कारण से अपर्याप्त है, तैयार करायेगा और देगा । विवरण की उतनी प्रतियाँ जितनी आयोग निर्दिष्ट करे, दी जाएगी ।

(3) लेखों को ऐसे प्ररूप में, जैसा आयोग समय समय पर निर्दिष्ट करे, तैयार किया जाएगा । सभी प्ररूपों पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या उसके सम्यक् प्राधिकृतकर्ता या प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(4) आयोग, विशेष या सामान्य आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि उप-विनियम (3) में विहित प्ररूप में लेखों के वार्षिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी आयोग को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे, ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी आयोग को इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो ।

43. विद्युत प्रदाय शर्तें.—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय कोड तथा प्रदाय शर्तों, जो आयोग समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, का अनुपानल करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, तथा अधिनियम की धारा 14 के अधीन समझें गए अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, इन विनियमों के लागू होने की तारीख से, छः मास के भीतर विद्यमान विद्युत प्रदाय शर्तों के उपान्तरण आयोग को देगा और आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् उपान्तरण सहित विद्युत प्रदाय की शर्तें, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लागू होंगी ।

(3) जब तक आयोग उप-विनियम(2) के अधीन विद्युत प्रदाय की शर्तों को अनुमोदित नहीं करता है, तब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान प्रदाय शर्तों, का आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट उपान्तरण सहित, अनुसरण करेगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय का संस्तुत कोड और प्रदाय शर्तों की मुद्रित प्रतियों की पर्याप्त संख्या हमेशा अपने कार्यालय में रखेगा और किसी आवेदक को, मांग करने पर, ऐसी प्रतियाँ मूल्य पर, जो सामान्य फोटो-प्रतिलिपि खर्च से अधिक न हो, विक्रय करेगा ।

44. अनुज्ञप्ति का उल्लंघन.—आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबन्धन एवं शर्तों के उल्लंघन या सम्भावित उल्लंघन के लिए अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उपयुक्त समझें ।

45. अनुज्ञप्ति का निलंबन.—(1) यदि अधिनियम की धारा 24 तथा तदधीन बनाये विनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन आयोग की किसी समय यह राय है कि —

- (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को विद्युत के क्वालिटी के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप विद्युत के अबाधित प्रदाय को बनाए रखने में लगातार असफल रहा है; या
- (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उसके अधीन पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या
- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है; या
- (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को तोड़ा है, यहां लोकहित में ऐसा करने के लिए परिस्थितियाँ विद्यमान हैं; जो उसे उसके लिए आवश्यक बनाती है तो अयोग एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम(1) के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन करने से पूर्व, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रस्तावित निलम्बन के आधार देते हुए लिखित 3(तीन) मास से अनाधिक का नोटिस देगा और उक्त नोटिस की अवधि के भीतर प्रस्तावित निलंबन के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताए कारण पर विचार करेगा ।

(3) आयोग, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का निलम्बन करते हुए, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगा तथा उक्त नियुक्ति होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता एक वर्ष से अनाधिक अवधि या उस तारीख तक के लिए जिसको ऐसी उपयोगिता का धारा 20 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विक्रय किया जाता है, या धारा 19 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया जाता है या अनुज्ञप्ति के निलम्बन का प्रतिसंहरण किया जाता है, जो भी बाद में हो, प्रशासक में निहित हो जाएगी ।

46. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण.—(1) अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिये या अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य आदेशों को पारित करने के लिए कार्यवाही का प्रारम्भ आयोग द्वारा पारित आदेश से किया जाएगा । आयोग स्व-प्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर या किसी शिकायत के प्राप्त होने पर या किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होने पर प्रारम्भ कर सकता है ।

(2) आयोग अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को और ऐसे अन्य व्यक्तियों, प्राधिकरण या निकाय को, जिन्हें वह आवश्यक समझें, कार्यवाही की सूचना दे सकता है ।

(3) अधिनियम के उपबन्धों और उसमें अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर आयोग द्वारा जाँच, जहाँ तक यह लागू हो, इन विनियमों के अध्याय-2 में यथाव्यवस्थित रीति से होंगी:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध कारण बताने के लिए लिखित में नोटिस, जो तीन मास से कम का न हो, दिया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी को निर्गत कारण बताओ नोटिस में आधारों को, जिन पर आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने के लिए प्रस्ताव करता है, स्पष्ट किया जाएगा।

(4) यदि आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने का विनिश्चय करता है तो आयोग उस प्रभावी तारीख को लिखते हुए जिस पर ऐसा प्रतिसंहरण प्रभावी होगा, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिसंहरण का आदेश भेजेगा।

(5) आयोग अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के बजाय अग्रतर निबन्धन और शर्तों को आरोपित करते हुए, जिनके अधीन अनुज्ञप्तिधारी को तत्पश्चात् संचालन की अनुमति दी जाए, कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है।

(6) यहां आयोग ने अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का नोटिस दिया हुआ है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, किसी व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित है, पर आरोपित की जा सकने वाली शास्ति अथवा उसके विरुद्ध लाई जा सकने वाली अभियोजन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने कारवार को किसी अन्य व्यक्ति को, जो आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के योग्य हो, विक्री कर सकेगा।

47. अनुज्ञप्ति का संशोधन.—(1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबन्धन और शर्तों में संशोधन हेतु आवेदन ऐसे प्ररूप में दिया जायेगा जैसे इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा निदेशित किया जाए। आवेदन के साथ इन विनियमों के अध्याय-2 में यथाव्यवस्थित प्रस्तावित संशोधन का विवरण तथा उसके समर्थन में हलफनामा होगा।

(2) संशोधन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस की रसीद, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, तथा जिसका भुगतान आयोग द्वारा निदेशित रीति में किया गया हो, संलग्न होगी।

(3) आवेदक, संशोधन के लिए आवेदन की प्राप्ति तथा संख्यांकित किए जाने की तारीख के सात (7) दिन के भीतर, प्रस्तावित संशोधन का संक्षिप्त ब्यौरा, प्रस्तावित संशोधन के कारण, प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव, ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए आनुकालिक प्रबन्ध तथा आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, संशोधन आवेदन का नोटिस प्रकाशित करेगा। उक्त प्रकाशन में कार्यालयों के पते, जिन में संशोधित आवेदन का निरीक्षण तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ खरीदी जा

सकेगी, दिए जाएंगे । प्रत्येक प्राधिकरण, उपयोगिता तथा व्यक्ति, जो आवेदन के संदर्भ में अभ्यावेदन देना चाहता है, आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी को, प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन के भीतर, पत्र लिखकर अभ्यावेदन दे सकता है ।

(4) यदि आयोग किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, तो आयोग प्रस्तावित संशोधन का संक्षिप्त ब्यौरा, प्रस्तावित संशोधन के कारण, प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव तथा ऐसे कृत्यों के निर्वहन के आनुकात्मिक प्रबन्ध तथा अन्य विशिष्टियों, जो आयोग समुचित समझें, का उल्लेख करते हुए संशोधन आवेदन का नोटिस प्रकाशित करेगा ।

(5) जब तक आयोग द्वारा लिखित में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का, जहां तक उसे लागू किया जा सके, अनुज्ञप्ति के संशोधन या परिवर्तन के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अनुसरण किया जायेगा ।

48. समझा गया वितरण अनुज्ञप्ति प्रदाय.—(1) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय में लगे व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों द्वारा वितरण अनुज्ञप्ति प्रवर्ग-II के लिए आवेदन किया हुआ तथा उन्हें इसमें अन्तर्विष्ट प्रयोजन के लिए तथा उप-विनियम (2) में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई समझी जाएगी,—

(क) वे व्यक्ति, जब विद्युत उनके अपनी पद्धति से वितरित की जाती है, जो अपने द्वारा उत्पादित, तथा/अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उन्हें प्रदाय की गई, विद्युत का किसी परिस्थिति में अथवा कृत्य के लिए दो मास से अनाधिक प्रदाय करते हैं;

(ख) वे व्यक्ति, यहाँ वे किसी अनुज्ञप्तिधारी से अथवा आयेग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से विद्युत उपाप्त करते हैं और आवासीय बस्तियों को, जिन्हें वे अपने क्रियाकलाप के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों के प्रयोग और अधिभोग के लिए और/अथवा कर्मचारियों को सुविधाएं व सेवा उपलब्ध करने वाले व्यक्तियों के प्रयोग और अधिभोग के लिए सम्पोषित करते हैं; बिना किसी लाभ के विद्युत प्रदाय करते हैं;

(ग) आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन अन्य वे व्यक्ति, जिन्हें आयोग समय-समय पर आदेश द्वारा अधिसूचित करे ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी —

(क) प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः, नहीं करेगा अथवा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर विद्युत में व्यापार वितरण या प्रदाय नहीं करेगा और विद्युत वितरण या प्रदाय उप-विनियम (1) में दिये गये उद्देश्य तक ही निर्बंधित होगा;

(ख) विद्युत लाइन अथवा संकर्म अपने कार्य क्षेत्र में ही स्थापित करेगा;

(ग) यदि अपेक्षा की जाए, आयोग को, आयोग द्वारा यथानिर्देशित ऐसी सूचना देगा जो आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो;

(घ) अधिनियम, आयोग के विनियमों, तकनीकी कोड जैसे कि ग्रिड कोड, प्रदाय कोड, निष्पादन के मानक तथा आयोग द्वारा निर्धारित समस्त निष्पादन मानक या दिये गए अन्य मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा ;

(ङ) उन सभी निदेशों का जो आयोग समय समय पर, उन प्रभारों के सम्बन्ध में जो ऐसे व्यक्ति उपभोक्ताओं से उद्ग्रहित कर सके, उस विद्युत प्रदाय क्षेत्र, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय करता है, के निकट के क्षेत्र में प्रचालित प्रभारों को ध्यान में रख कर दें, अनुपालन करेगा ।

(3) आयोग को, समय-समय पर ऐसे निदेश जैसे वह आवश्यक समझे, देने और इन विनियमों के भंग तथा अनुपालन के लिये अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध इन विनियमों के अधीन, अधिनियम तथा इन विनियमों के अनुसार कारवाई करने का अधिकार होगा ।

(4) आयोग, यदि वह आवश्यक समझे, अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी प्रक्रम में, इस विनियम के अधीन प्रवर्ग-I अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है और अनुज्ञप्ति को प्रदान करने अथवा अग्रहीत करने पर विचार कर सकता है तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को अंतरिम या अंतिम आदेश द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र या उसके भाग में विद्युत वितरण अथवा प्रदाय न करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है ।

(5) यदि कोई मतभेद या विवाद हो जाता है कि किसी व्यक्ति को इस विनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत प्रदाय करने का अधिकार है तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

अध्याय-5**उत्पादन कम्पनियाँ और आबद्ध उत्पादन केन्द्र**

49. उत्पादन कम्पनियाँ और आबद्ध उत्पादन केन्द्र.—उत्पादन कम्पनियाँ तथा अन्य व्यक्ति जिन्होंने राज्य में उत्पादन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत आबद्ध उत्पादन केन्द्र भी हैं; स्थापित कर लिए हैं तथा वे व्यक्ति जो ऐसे उत्पादन केन्द्र, जिसके अन्तर्गत आबद्ध उत्पादन केन्द्र भी हैं, स्थापित करना चाहते हैं, आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना से 30 दिन के भीतर अथवा केन्द्र में विद्युत उत्पादन चालू होने से 30 दिन के भीतर, जो भी पश्चात्तर्वती, हो प्ररूप सी.बी.-18 (उपाबन्ध-XVI) पर उत्पादन केन्द्र का तकनीकी ब्यौरा देंगे :

परन्तु यह कि निम्न विभव (Low Tension) वर्ग I तथा II उपमोक्ताओं को उपरोक्त विवरण आयोग को जब तक कि अन्यथा आयोग द्वारा विशेषतः निर्दिष्ट न किया जाए, देना अपेक्षित नहीं होगा ।

अध्याय-6

विद्युत उपापन तथा क्रय

50. विद्युत उपापन तथा क्रय.—(1) अधिनियम के उपबन्धों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के लिए अपेक्षित विद्युत का, मितव्ययी एवं दक्षतापूर्ण रीति से और पारदर्शी विद्युत क्रय तथा उपापन प्रक्रिया द्वारा तथा न्यूनतम लागत क्रय के सिद्धान्तों पर सामान्यतः आधारित क्रय अथवा उपापन करेगा ।

(2) आयोग उन निबन्धनों पर, जो वह समय-समय पर विनिश्चित करे, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय को लघुकालिक विद्युत क्रय अथवा दीर्घकालिक विद्युत क्रय में वर्गीकृत कर सकेगा ।

(3) लघुकालिक क्रय तथा दीर्घकालिक क्रय जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञापित कारबार के प्रयोजन के लिए करे, को विनियमित करने लिए आयोग, समय-समय पर, मार्गदर्शन, पद्धति-निर्देश तथा आदेश जारी कर सकेगा ।

(4) (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करेगा कि दीर्घकालिक अतिरिक्त विद्युत उपापन उन घटनाओं के कारणवश है जो उसके युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हैं तथा लघुकालिक विद्युत क्रय की दशा में, उक्त अतिरिक्त लघुकालिक क्रय किन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है ।

(ख) जब तक आयोग, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत उपापन मन्जूर नहीं कर देता है, तब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी आबद्धकर एवं प्रवर्तनीय संविदाजात प्रतिबद्धता के लिए कोई करार नहीं करेगा ।

(5) जब तक आयोग, साधारण विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा मन्जूर नहीं करता है, तब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घकालिक विद्युत क्रय अथवा उपापन आयोग द्वारा मन्जूर प्रतियोगी उपापन प्रक्रिया से ही करेगा ।

(6) (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करेगा कि प्रतियोगी बोली प्रक्रिया से अन्यथा दीर्घकालिक विद्युत क्रय द्वारा उपापन की गई विद्युत अथवा विद्युत का लघुकालिक क्रय विद्यमान परिस्थितियों में न्यूनतम मूल्य पर अथवा सस्ता है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने क्रय मूल्य को कम कराने के लिए सभी व्यवहार कुशल तथा सर्वोत्तम प्रयास किए हैं ।

(ख) यदि उक्त विद्युत उपापन की प्रस्तावित रीति न्यूनतम क्रय मूल्य के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है या किसी अन्य कारण से क्रय सस्ता अथवा दक्षतापूर्ण नहीं है, तो आयोग ऐसे लघुकालिक अथवा दीर्घकालिक क्रय को अनुज्ञात नहीं कर सकेगा ।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी लघुकालिक विद्युत क्रय, उसी रीति से, जैसे आयोग समय-समय पर साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रारम्भ कर सकेगा ।

(8) उत्पादन कम्पनियाँ, अनुज्ञप्तिधारी कम्पनियों अन्य अनुज्ञप्तिधारियों, प्राधिकारियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से समन्वय के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के लिए विद्युत मांग का पूर्वानुमान लगाएगा तथा प्रस्ताव तैयार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी उक्त मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उपापन योजना आयोग को, उस रीति से, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा ।

(9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने नियंत्रणाधीन वितरण तन्त्र तथा उपाप्त विद्युत के, राज्य के भीतर अथवा राज्य से बाहर, पारेषण के लिए उपलब्ध इंतजाम से सम्बन्धित विवरण आयोग को देगा तथा आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत उपापन योजना के अनुसार उसको वितरित करेगा ।

(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी संसाधन योजना, विद्युत क्रय तथा उपापन योजना, पारेषण तन्त्र और वितरण तन्त्र की योजना, प्रतियोगी उपापन प्रक्रिया के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उर्जा क्रय से सम्बन्धित सभी अन्य बातों का विवरण आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शन तथा प्रक्रिया निदेशों में यथाउपबन्धित के अनुसार दिया जाएगा ।

(11) इस विनियम तथा अधिनियम की धारा 61 के अधीन बनाए गए टैरिफ विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए टैरिफ अवधारित करते हुए आयोग, इस विनियम के अधीन उस द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय तथा उपापन प्रक्रिया को दी गई मन्जूरी तथा इस विनियम के निबन्धनों के अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से की गई कार्रवाई तथा बरती गई कुताही, पर विचार करेगा ।

अध्याय-7

विनिधान मन्जूरी

51. विनिधान मन्जूरी.—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जब तक आयोग अन्यथा विनिर्दिष्ट न करे, अपने अनुज्ञापित कारबार में विनिधान, यदि विनिधान आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों में अधिकथित सीमा से ऊपर है, आयोग की पूर्व मन्जूरी के नहीं करेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति की शर्तों में अन्तर्विष्ट सीमाएं आयोग द्वारा, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपान्तरित की जा सकेंगी ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, विनिधान मन्जूरी के लिए आवेदन में, निम्नलिखित सूचना अथवा विशिष्टियां देगा,—

- (क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें प्रारम्भ किए जाने वाले संकर्मों का खाका, विनिधान के प्रमुख तत्व तथा उसकी आवश्यकता प्रदर्शित करने वाली विशिष्टियों सहित विनिधान की आर्थिक, तकनीकी पद्धति और पर्यावरिक पहलुओं का परीक्षण अन्तर्विष्ट हो;
- (ख) लाभप्रद लागत विश्लेषण सहित परियोजना लागत;
- (ग) क्या विनिधान नई परियोजना अथवा किसी विद्यमान परियोजना के विस्तारण या उन्नति के लिए है?
- (घ) परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित मन्जूरियां व कानूनी अनापत्तियां और ऐसी मन्जूरियों व कानूनी अनापत्तियों की प्रास्थिति;
- (ङ) विनिधान का वित्तीय वर्षों पर फैलाव तथा उसकी निष्पादन अनुसूची;
- (च) अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व अपेक्षाओं में अन्तर्वेशन के प्रयोजन के लिए विनिधान को पूँजी में परिणत करने की रीति और समय सीमा;
- (छ) विनिधान करते हुए अथवा परियोजना के निष्पादन में अनुज्ञप्तिधारी के सम्मुख आने वाली मजबूरियां जिसमें उपलब्ध सूचना की मजबूरियां भी हैं;
- (ज) विनिधान पूरा करने के लिए संसाधन तथा वित्तीय योजना; तथा

(झ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो आयोग, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे ।

(4) (क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिधान की मन्जूरी हेतु किए गए आवेदन को निपटाते हुए, आयोग स्वविवेकाधिकार से, ऐसी जाँच तथा परामर्श, जैसे आयोग समुचित समझे, कर सकेगा ।

(ख) विनिधान मन्जूरी हेतु आवेदन पर आयोग, स्वविवेकाधिकार से, कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है या उस पर टैरिफ अवधारण कार्यवाहियों का भाग मानकर अथवा अन्य कार्यवाहियों के साथ, जैसे आयोग समुचित समझे, विचार कर सकता है ।

(5) (क) इससे पूर्व आयोग विनिधान मन्जूरी हेतु आवेदन पर विचार करे, आयोग को अधिकार होगा कि वह, परामर्शदाता, अन्वेषक, विशेषज्ञ और अन्यो को, जैसे आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सके तथा आयोग कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, अन्वेषकों तथा विशेषज्ञों को अनुज्ञप्तिधारियों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए प्राधिकृत कर सके ।

(ख) इस उप-विनियम के अधीन परामर्श, अन्वेषण तथा रिपोर्ट के लिए व्यय का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा ।

(6) (क) अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य आवेदक जो विनिधान की मन्जूरी के लिए, आवेदन देते हैं ऐसी सूचना विशिष्टियां तथा दस्तावेज, जो आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त आयोग के कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, अन्वेषकों तथा विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित हो, देंगे और उन अभिलेखों तथा दस्तावेजों, जो अनुज्ञप्तिधारी के शक्त्यधीन, कब्जे अथवा अभिरक्षा में हैं, को उन्हें देखने की अनुमति देंगे ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, अन्वेषकों तथा विशेषज्ञों को उनके कृत्यों के निर्वहन तथा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की रिपोर्ट आयोग को भेजने में सहयोग देगा ।

(7) इस विनियम तथा अधिनियम की धारा 61 के अधीन बनाए गए टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए टैरिफ अवधारित करते हुए आयोग इस विनियम के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को दी गई विनिधान मन्जूरी तथा इस विनियम के निबन्धनों के अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से की गई कार्रवाई तथा बरती गई कुताही, पर विचार करेगा ।

अध्याय-8

निष्पादन के मानक, विद्युत प्रदाय कोड, विनियम इत्यादि

52. निष्पादन के मानक, विद्युत प्रदाय कोड, विनियम इत्यादि.—(1) आयोग समय समय पर राज्य में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारियों और कम्पनियों को विद्युत क्षेत्र में उपयुक्त, दक्ष, मितव्ययी तथा प्रतियोगी संचालन हेतु तथा राज्य में विद्युत पद्धति प्रचालन के लिए कोड, जैसे आयोग समुचित समझें, बनाने अथवा अपनाने के लिए निर्देशित कर सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बनाए गए कोड विमर्शित करने के लिए, आयोग, जैसे उपयुक्त समझे, विचार-विमर्श तथा कार्यवाहियाँ, कर सकता है ।

(3) (क) अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियाँ द्वारा बनाए गए कोड के सम्बन्ध में आयोग को सलाह देने के लिए आयोग परामर्शदाता अथवा विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा ।

(ख) इस उप-विनियम के अधीन नियुक्त परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों पर व्यय का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जाएगा ।

(4) आयोग, यथासमुचित समझें, अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों द्वारा बनाए गए कोड में ऐसे उपान्तरण, जैसे आयोग समुचित समझें, निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(5) आयोग द्वारा मन्जूर किए गए कोड का अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनियाँ, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों तथा आदेशों के अनुकूल, पालन करेंगे ।

(6) विद्युत तन्त्र के परिचालन में निष्पादन के मानक के पालन के सम्बन्ध में आयोग की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बनाए गए तथा लागू किए कोड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे

(क) ग्रिड कोड;

(ख) वितरण कोड;

(ग) विद्युत प्रदाय कोड तथा प्रदाय की शर्तें;

(घ) उपभोक्ता सम्बन्धित कोड जिनमें बिल संदाय पद्धति; असंदाय पर लाइन काटने, सेवा मानक एवं क्वालिटी तथा विफल रहने पर जुर्माना तथा शास्ति, उपभोक्ता अधिकार तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया कोड भी है ;

(ङ) सुरक्षा तथा बचाव कोड;

(च) पारेषण प्रणाली योजना तथा सुरक्षा मानक;

(छ) वितरण प्रणाली योजना तथा सुरक्षा मानक;

- (ज) परिचालन मानक ; तथा
- (झ) विद्युत उपयोग और माँग प्रबन्धन।

♦ (7) जब तक उप-विनियम (6) के अधीन कोड, विद्युत प्रदाय शर्तों तथा मानक इन विनियमों के अनुसार बनाए तथा लागू नहीं किए जाते, तब तक अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनियाँ विद्यमान विद्युत प्रदाय के मानक, कोड तथा शर्तों का पालन करेंगे।

अध्याय—9

विवादों का माध्यस्थम्

53. माध्यस्थम्.—(1) उन विवादों के माध्यस्थम् को, जो अधिनियम के अधीन आयोग की अधिकारिता के भीतर आते हैं; विवाद के किसी भी पक्षधर के आवेदन पर, शुरू किया जा सकता है।

(2) आयोग, सम्बन्धित पक्षधरों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि पक्षधरों के मध्य विवादों को क्यों न माध्यस्थम् से न्यायनिर्णित तथा निपटा दिया जाए।

54. मध्यस्थ का नामांकन.—(1) यदि आयोग विनिश्चय करे कि आयोग से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यस्थम् के लिए विवाद निर्देशित किया जाए, तो —

(क) यदि विवाद के पक्षधर मध्यस्थ के नाम पर सहमत हों तो विवाद एकमात्र मध्यस्थ को निर्देशित किया जाएगा; या

(ख) यदि पक्षधर आयोग द्वारा पदाभिहित किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के नाम पर सहमत न हों तो विवाद तीन व्यक्तियों, जैसा कि आयोग विवाद की प्रकृति और अंतर्निहित मूल्य का विचार कर के निर्देश दे, को निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि तीन मध्यस्थों को नामांकित करने का निर्णय हो तो विवाद के प्रत्येक पक्षधर द्वारा एक मध्यस्थ नामांकित किया जाएगा और तीसरा आयोग द्वारा :

परन्तु यह कि यदि कोई पक्ष मध्यस्थ को नामांकित करने में विफल रहे और यदि पक्षों या आयोग द्वारा नामांकित कोई मध्यस्थ कार्य करने की उपेक्षा करता है या मध्यस्थ के रूप में बने रहने में विफल रहता है तो आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने का हकदार होगा।

(2) आयोग ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसके बारे में कोई पक्ष सम्भावित पक्षपात या इसी प्रकार के कारणों के आधार पर युक्तियुक्त आपत्ति करें और आयोग आपत्ति को न्यायसंगत समझें।

(3) आयोग पक्षधरों जिन्हें नोटिस दिए गए हैं की सुनवाई के पश्चात् और यदि समाधान हो जाए कि माध्यस्थम् अनुरोध के विरुद्ध कोई तर्क या कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है, निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकता है कि विवादों को आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की माध्यस्थम् से न्यायनिर्णयन अथवा निपटाने हेतु निर्देशित किया जाए।

55. न्याय निर्णयन, निपटारे तथा पंचाट करने की प्रक्रिया.—(1) यदि आयोग मध्यस्थ के रूप में कार्य करे तो निपटारे के लिए अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जो अध्याय-2 में आयोग के समक्ष सुनवाई के मामले में व्यवस्थित है ।

(2) यदि आयोग न्याय-निर्णयन और विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ या मध्यस्थों को नाम निर्दिष्ट करे, तो ऐसा मध्यस्थ ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन कर सकते हैं जो वे समुचित समझें और जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल हो और माध्यस्थम् के पक्षों को समुचित अवसर दे और आयोग द्वारा जारी किए गए विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार हो ।

(3) मध्यस्थ, पक्षधरों की सुनवाई के उपरान्त न्यायनिर्णयन हेतु उद्भूत सभी विवादों पर अपने निर्णय के लिए कारण देते हुए, अधिनिर्णय देगा तथा अधिनिर्णय को सुसंगत दस्तावेजों सहित, ऐसे समय के भीतर जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, आयोग को अग्रेषित करेगा ।

(4) आयोग अथवा यथास्थिति मध्यस्थों द्वारा किया गया अधिनिर्णय, मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के अधीन किया गया अधिनिर्णय समझा जाएगा ।

56. माध्यस्थम् कार्यवाहियों के खर्चे.—आयोग के समक्ष माध्यस्थम् तथा कार्यवाहियों के खर्चे, ऐसे पक्षों द्वारा और ऐसी धन राशि में, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, धारित किए जाएंगे ।

अध्याय-10**भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबन्धों का लागू होना**

57. भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का लागू होना.—(1) आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ, अधिनियम की धारा 95 के उपबन्धों के अनुसार, न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएंगी और आयोग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के सहित पठित उक्तधारा में विनिर्दिष्ट सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(2) भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के सुसंगत उद्धरण इन विनियमों के उपाबन्ध—XVII में अंतर्विष्ट है ।

अध्याय-11

फीस और दंड

58. फीसें.—(1) आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली प्रत्येक याचिका, आवेदन अथवा शिकायत, इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उपयुक्त फीस का भुगतान करके की जाएगी। तथापि, अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस जो सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अधीन विहित की जाए, के साथ दिया जाएगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क अदा करेगा।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत आयोग को भुगतान किए जाने वाली फीस की अदायगी, सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियमक आयोग के पक्ष में शिमला में देय बैंक ड्राफ्ट या भुगतान-आदेश (पे-ऑर्डर) से की जाएगी। आयोग 1000 रुपये तक की राशि नकद में ले सकेगा।

(4) आयोग, आदेश द्वारा, इन विनियमों में उपबंधित देय फीस राशि को माफ कर सकेगा।

(5) इन विनियमों के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्राप्त की गई फीस को, समय समय पर आयोग द्वारा निदेशित, बैंक तथा बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं में खोले गए बैंक खाते में जमा कराया जाएगा तथा इन विनियमों के अध्याय-2 में इस निमित्त प्ररूप सी.बी.-4 (उपाबन्ध-II) में विहित रजिस्टर में उसको दर्ज करेगा।

(6) अधिनियम की धारा 103 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, आयोग, जब आवश्यक समझें, उप-विनियम (5) में बैंक खाते में जमा फीस अधिनियम के अधीन आयोग के खर्च के लिए उपयोजित कर सकेगा।

59. आवेदन/याचिका प्रवर्ग.— आयोग के समक्ष किये गए आवेदन/याचिकाएँ निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जाएंगी:—

- (1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने/अनुज्ञप्ति प्रदान करने से छूट के लिए आवेदन;
- (2) टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन;
- (3) विद्युत उपापन तथा क्रय की मन्जूरी के लिए याचिका;
- (4) आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन;
- (5) अन्य आवेदन/याचिकाएँ।

60. राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय शुल्क.— विद्युत के अंतःराज्य में लगी उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञापिधारियों द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम की धारा 32 (3) के अधीन देय शुल्क वे होंगे जो आयोग विनिर्दिष्ट करे ।

61. अधिनियम की धारा 127 (1) के अधीन अपील पर देय फीस.—अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील याचिका पर देय शुल्क वे होंगे जो आयोग विनिर्दिष्ट करे ।

62. उल्लंघन या अपालन करने का दंड और प्रभार.—(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश-निर्देश के अनुपालन न करने की दशा में अधिनियम की धारा 142 तथा 146 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अथवा आयोग द्वारा किसी अनियमित या नियम या विनियम के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए, आयोग कथित अधिनियम के अधीन दंड और/या प्रभार लगाने के लिए कार्यवाई कर सकता है ।

(2) कार्यवाहियों पर लागू होने वाले अध्याय-2 के उपबन्ध, यथावश्यक, परिवर्तनों सहित दंड और/या प्रभार लगाने की किसी कार्यवाही पर लागू होंगे ।

(3) आयोग लगाए जाने वाले दंड और/या प्रभारों की मात्रा या सीमा तय करते समय अन्य संगत विंदुओं समेत निम्नलिखित पर विचार करेगा :—

(क) अपालन या उल्लंघन की प्रकृति और सीमा;

(ख) अपालन या उल्लंघन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, जिसमें आयोग भी आता है, से प्राप्त किए गए अनुचित लाभ या अन्यायसंगत बढ़त कारित प्रतिहानि अथवा अहित;

(ग) अपालन या उल्लंघन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, जिसमें आयोग भी आता है, को हुई हानि या उत्पीड़न की मात्रा अथवा विद्युत आयोग के दक्ष, मितव्ययी, अथवा प्रतियोगी संपादन पर हानिप्रद प्रभाव;

(घ) अपालन या उल्लंघन के फलस्वरूप अधिनियम के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों को कारित हानि अथवा ह्रास की प्रकृति व मात्रा ;

(ङ) अपालन या उल्लंघन का उद्देश्य; तथा

(च) अपालन या उल्लंघन की आवृत्तीय प्रकृति ।

(4) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने/दंड और प्रभार के भुगतान आयोग द्वारा दंड अथवा प्रभार आरोपित करने वाले आदेश के 30 दिन के अंदर करने होंगे ।

◆ (5) विनियम 58 में विनिर्दिष्ट रीति से दंड/जुर्माने और प्रभारों का भुगतान और राशि जमा होंगी ।

(6) यदि आयोग द्वारा लगाए गए दंड या जुर्माने उप-विनियम (4) के अनुसार 30 दिन के भीतर अदा नहीं किए जाते; तो उनकी वसूली उसी प्रकार से की जाएगी मानो वे भू-राजस्व बकाया हो ।

अध्याय-12

प्रकीर्ण

63. निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों का पुनर्विलोकन.—(1) किसी निदेश, निर्णय या आदेश—

- (क) जिसकी अपील नहीं की गई है; या
- (ख) जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है;

से व्यथित व्यक्ति ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय, जब निदेश, निर्णय या आदेश दिया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध दिए गये निदेश, निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, वह आयोग से, यथास्थिति, उक्त निदेश, निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उसी रीति से दिया जाएगा जिस रीति से इन विनियमों के अधीन याचिका दी जाती है ।

(3) जहां आयोग को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वहाँ वह आवेदन नामंजूर कर देगा ।

(4) जहां आयोग की राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए वहाँ वह उसे मंजूर करेगा, परन्तु ऐसा कोई भी आवेदन विरोधी पक्षकार को ऐसी पूर्वर्ती सूचनाएं दिए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा जिससे वह उपसंजात होने और उस निर्णय या आदेश के जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, समर्थन में सुने जाने के लिए समर्थ हो जाए ।

64. मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही जारी रखना.—(1) जहाँ किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए अथवा वह दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णित हो जाए या कोई कम्पनी के मामलों में वह कम्पनी बन्द/परिसमापन होने की प्रक्रिया में हो जाए, तो कार्यवाहियाँ सम्बन्धित पक्षकार के हित उत्तराधिकारी के साथ जारी रहेगी ।

(2) आयोग अभिलेखित कारणों के आधार पर कार्यवाही को उपशमनित समझ सकता है यदि वह ऐसे आदेश जारी करे तथा अगले हित उत्तराधिकारी को मामले के अभिलेख में सम्मिलित न करने की कार्यवाही न करें ।

(3) यदि कोई हित उत्तराधिकारी को मामलों के अभिलेख में सम्मिलित करना चाहता है तो इस आशय का आवेदन पत्र उस घटना के 90 दिवस के अन्दर दाखित होगा जिसके कारण हित उत्तराधिकारी को अभिलेख में दर्ज करने की आवश्यकता हुई :

परन्तु आयोग, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञात कालावधि में आवेदन-पत्र न देने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, उन निबन्धनों और शर्तों, जो आयोग समुचित समझें, के अध्याधीन विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, उप-विनियम (3) में अनुज्ञात कालावधि में, हित उत्तराधिकारी को मामलों के अभिलेख में सम्मिलित कराने में विफल रहता है और यदि उप-विनियम (3) के परन्तुक के अधीन हित उत्तराधिकारी को सम्मिलित कराने में विलम्ब माफी नहीं की जाती है तो मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का उपशमन हो जाएगा ।

65. कार्यवाहियों की जन पारदर्शिता.—(1) आयोग के समक्ष की जा रही कार्यवाहियाँ, बैठने की जगह उपलब्ध होने पर, जनता के लिए खुली होंगी :

परन्तु आयोग, यदि उचित समझें, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी विशिष्ट मामले की कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश कर सकता है कि जनसाधारण अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह का आयोग द्वारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रयोग किए जा रहे न्यायालय-कक्ष, अथवा भवन अथवा परिसर में उपागमन, प्रवेश अथवा उपस्थिति नहीं होगी ।

66. याचिका का प्रकाशन.—(1) जहां कोई आवेदन, याचिका अथवा अन्य सामग्री इस अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो तो जब तक कि आयोग अन्यथा रूप से आदेश न दे या अधिनियम अथवा विनियम में अन्यथा रूप में व्यवस्था न की गई हो, ऐसे समय के भीतर जैसे आयोग निर्दिष्ट करे तथा प्रतिकूल विनिर्दिष्ट निदेश की अनुपस्थिति में सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम 5 दिन से पूर्व प्रकाशित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित किया जाता है, उक्त प्रकाशन सम्बन्धित क्षेत्र में परिचालित दो समाचार-पत्रों, जिनमें से एक अंग्रेजी तथा दूसरा हिन्दी का हो, में किया जाएगा ।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऐसे प्रकाशनों का शीर्षक ऐसा होगा जिनमें सामग्री का विषय संक्षेप में वर्णित होगा ।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ आयोग के पदामिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे :

परन्तु प्रकाशन सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व किया जाएगा ।

67. गोपनीयता.—(1) आयोग के अभिलेख, उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त है, फीस के संदाय और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आयोग निर्देशित करे, सभी के द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

(2) आयोग उन निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियों की किसी व्यक्ति को प्रदाय की व्यवस्था कर सकता है ।

(3) आयोग, आदेशानुसार, यह निर्देश दे सकता है कि कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्री, जो आयोग अथवा उसके किन्हीं अधिकारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं या अन्यथा रूप से उनके कब्जे में या अभिरक्षा में आ जाएं, वह गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध नहीं होंगे और आयोग यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात अथवा सामग्री का प्रयोग सिवाय आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अवस्था के किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा ।

68. आदेशों और प्रक्रिया पर निदेशों का जारी करना .— आयोग इस अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर विनियमों के कार्यान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विविध मामलों के सम्बन्ध में, जिसके लिए इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निदेशित करने के लिए आयोग को सशक्त किया गया है, आदेश और कार्य निदेश जारी कर सकता है ।

69. आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्याप्ति.— (1) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो आयोग कि ऐसी अंतर्निहित शक्ति को न्यायिक दृष्टि से आवश्यक आदेश देने या आयोग, की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए है, सीमित करता हो या अन्यथा प्रभावित करता हो ।

(2) उन विनियमों में, अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया अपनाने से आयोग पर कोई वर्जन नहीं होगा जो इन विनियमों के किसी उपबन्ध से मतभेद रखते हो, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत और लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करना आवश्यक या समीचीन समझता है ।

(3) इन विनियमों में, स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से आयोग पर इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी मामले पर कार्यवाई करने या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई वर्जन नहीं होगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के संदर्भ में वह कार्यवाई कर सकता है, जो वह उचित समझे ।

70. संशोधन करने की सामान्य शक्ति:—आयोग, किसी भी समय उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या गल्ती के संबन्ध में संशोधन कर सकता है ।

71. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति:—यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकता है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप असंगत नहीं है, जो ऐसी कठिनाइयों के दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है ।

72. विनियमों की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने की शक्ति:—आयोग को, किसी विनिर्दिष्ट मामले अथवा मामलों में, उन निबन्धनों तथा शर्तों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यक्षीन रहते हुए, अभिलिखित कारणों पर तथा प्रभावित पक्षकारों को सूचना दे करके, किसी भी विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने की शक्ति होगी ।

73. विहित समय का विस्तारण या संक्षेपण:—अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को बढ़ाया जा सकता है (भले ही वह पहले समाप्त हो गया हो या नही) या उस समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से कम किया जा सकता है ।

74. अनुपालन न करने का प्रभाव:—इस विनियमों की किसी अपेक्षा के अनुपालन में चूक तब तक केवल ऐसी चूक के कारण किसी कार्यवाही को अवधिमान्य नहीं करेगी जब तक कि आयोग इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि ऐसी चूक के कारण न्याय की अवहेलना हुई है ।

75. लागतें:—(1) ऐसी शर्तों और सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित की जाएं, सभी कार्यवाहियों की लागत आयोग के विवेकानुसार निर्धारित की जाएंगी और आयोग को यह अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि किसको या किस निधि से और कितनी मात्रा तक लागतों का संदाय करना है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने का पूरा अधिकार है ।

(2) लागतों का संदाय आदेश करने की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जिसे आयोग आदेश के द्वारा निदेशित करे। आयोग के लागतों के अधिनिर्णयन के आदेश का पालन सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा ।

76. आयोग द्वारा पारित आदेशों के प्रवर्तन:—सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन और अनुपालन, इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किया जाए और यदि आवश्यक हो तो निदेशों के लिए आयोग का आदेश

प्राप्त किया जा सकता है। इस में असफलता की दशा में, उसके विरुद्ध आयोग के निदेशों तथा आदेशों का अनुपालन न करने या उनका उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

77. निरसन और व्यावृत्ति.—(1) इस विनियमों के लागू होने पर, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2001 निरासीत हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए आशायित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत जारी किया गया आदेश, या नोटिस या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज़ या दिया गया निदेश भी है, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव

अनुसूचि
(विनियम 58 सी0बी0आर0 देखें)

फीस संरचना

क्रम संख्या 1	आवेदन/ याचिका स्वरूप 2	कानूनी उगबन्ध 3	फीस (रुपयों में) 4	टिप्पणियां 5
1.	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (i) पारेषण अनुज्ञप्ति (ii) वितरण अनुज्ञप्ति (iii) व्यापार अनुज्ञप्ति	सी.बी.आर. 38 (2) सी.बी.आर. 27(1) " "	100 लाख प्रति वर्ष 25 लाख प्रति वर्ष 25 लाख प्रति वर्ष	
2.	उत्पादन कम्पनियों के सम्बन्ध में टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन	विद्युत अधिनियम 86 (1) (a) और सी. बी. आर. 12, 13, 14	25 लाख	
3.	पारेषण टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन	"	5 लाख	
4.	विद्युत थोक, प्रपुंज या फुटकर प्रदाय के लिए टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन	"	1 पैसा प्रति kwh (वितरण पद्धति में डाली गई)	
5.	विद्युत चक्रण के लिए टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन	"	1 लाख	
6.	विद्युत उपापन तथा क्रय करारों की मंजूरी प्रक्रिया के लिए फीस	विद्युत अधिनियम 86 (1) (b) तथा सी.बी. आर. 50	15,000 प्रति मैगावाट अथवा उसका भाग (संविदाकारी पक्षकारों में बराबर धारित की जाएगी)	
7.	आयोग के आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए याचिका पर— (i) टैरिफ आदेश— (क) मूल टैरिफ याचिकाकर्ता की प्रार्थना (ख) संगम/समूह की प्रार्थना (ग) व्यक्तिक उपभोक्ता संगम (ii) विद्युत क्रय करार (क) 5 मैगावाट तक (ख) 5 मैगावाट से अधिक (ग) अन्य	सी.बी.आर. 63	50,000/- रुपये 25,000/- रुपये 20,000/- रुपये 10,000/- रुपये 50,000/- रुपये —	

1	2	3	4	5
8.	आयोग के न्यायक-अभिलिखों का निरीक्षण	सी.बी.आर. 23(3)	200 रुपये प्रति दिन	
9.	आयोग के न्यायक-दस्तावेजों/अभिलिखों की सत्यापित प्रतियों के प्रदाय के लिए	सी.बी.आर. 24(9)	5 रुपये प्रति पृष्ठ	
10.	अनुज्ञापितधारियों और उपयोगिताओं के बीच विवाद व मतभेद के दाखले व अधिनिर्णयन; और इस सम्बन्ध में पुनर्विलोकन हेतु आवेदन/याचिकाएं	सी.बी.आर. 12	10,000 रुपये	
11.	अन्तर्वर्ती आवेदन (i) अनुज्ञापितधारी द्वारा (ii) अन्य द्वारा	सी.बी.आर. 12	5000 रुपये 1000 रुपये	
12.	स्थगन हेतु आवेदन	सी.बी.आर. 12	1000 रुपये	
13.	समय वृद्धि हेतु आवेदन	सी.बी.आर. 12	1000 रुपये	
14.	आयोग के आदेश, जो उपर्युक्त नहीं है, के लिए अन्य आवेदन/याचिकाएं	सी.बी.आर. 12	2000 रुपये	
15.	अनुज्ञापितधारियों, उत्पादन, कम्पनियों इत्यादि के कामकाज के बारे में उपभोक्ता/उपभोक्ताओं की शिकायत/आवेदन— (i) उपभोक्ता संगम/समूह द्वारा (ii) व्यक्ति	सी.बी.आर. 12	1000/- रुपये शून्य	

प्ररूप सी०बी०-१

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियमों से सम्बन्धित विवरण का रजिस्ट्र

[illegible]

[विनियम 7 (2) (छ) (ii) - सी०बी०आर० देखें]

भाग-1 केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन जारी की गई वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों तथा निर्देशों का विवरण

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[विनियम 7 (2) (छ) (iii) – सी०बी०आर० देखें]

भाग-I विनियम

[illegible]

[illegible]

[विनियम 12 (6) सी०बी०आर० देखें]

शुल्क रजिस्टर

[illegible]

उपाबन्ध—III
प्ररूप सी0बी0-5
(विनियम 13 सी0बी0आर0 देखें)

कार्यक्रम सम्बन्धित सामान्य अभिलेख
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

फाईल सं०
केस सं.
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

_____ के मामले में

और

_____ के मामले में

(याचिकर्ता/आवेदक/प्रत्यार्थी का नाम तथा पूरा पता)

उपाबन्ध-IV
प्ररूप सी0बी0-6
(विनियम 13 सी0बी0आर0 देखें)

कार्यक्रम सम्बन्धित सामान्य अभिलेख
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

फाईल सं0
केस सं0
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

_____ के मामले में
(आवेदन/याचिका से सम्बन्धी मुख्य तत्व)

और

_____ के मामले में
(आवेदन/याचिकर्ता/प्रत्यार्थी का नाम व पूरा पता)

शपथ-पत्र/आवेदन/याचिका/उत्तर पत्र को प्रमाणित करने के लिए

1. मैं,..... पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र
का निवासी शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ जो
निम्नवत है : -

मैं स्वयं आवेदक/याचिकर्ता/प्रत्यार्थी हूँ या

..... निदेशक/सचिव/साझीदार हूँ इस सम्बन्ध
में आवेदन करने/याचिकाकर्ता/प्रत्यार्थी के लिए अधिकृत हूँ और उक्त सम्बन्ध में
आवेदन/अभ्यर्थना/जवाबदेही कर सकता/सकती हूँ तथा शपथ पत्र दे सकता है/सकती हूँ।

2. जो उपरोक्त बयान प्रथमोत्तर प्रखंड में
आवेदनकर्ता/प्रत्यार्थी तथा उत्तर में प्रस्तुत किया गया है तथा जो मुझे दिखाया गया है और अक्षर
'अ' के अन्तर्गत उल्लिखित है वह मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है और उक्त प्रखंड
में उद्भूत है, वह से प्राप्त जानकारी पर आधारित है

और कह गया है, मेरी जानकारी में सत्य है ।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

मैं, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक
..... में दिया गया मेरा बयान पूर्णतः सत्य है तथा इसमें कोई भी तथ्य मेरी जानकारी में छुपाया नहीं गया है ।

गवाह

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

उपाबन्ध-V

प्ररूप सी0बी0-7

[विनियम 15 (3) सी0बी0आर0 देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

याचिका सं०

के मामले में अर्जीदार

बनाम

प्रत्यार्थी

उपसंजात होने का ज्ञापन

मैं, के रूप में व्यवसाय/कार्यरत
को की ओर से उपस्थित होने के लिये द्वारा
प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति का विवरण दें) किया जा रहा है और पूर्वावत
के सभी मामले में उसके लिये और कार्य करने के लिए बचनबद्ध होता हूँ ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

पत्राचार के लिये पता

[विनियम 15(4) सी०बी०आर० देखें]

याचिका/आवेदन पत्र - रजिस्टर

[illegible]

उपाबन्ध—VII

प्ररूप सी0बी0-9

[विनियम 15 (6)सी0बी0आर0 देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

संख्या.....

विषय: — हिमाचल प्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा के अन्तर्गत आवेदन पत्र
..... हेतु

महोदय,

आपके आवेदन/याचिका दिनांक जो दिनांक
को प्रेषित किया गया था, के संदर्भ में आपको सूचित करने हेतु मुझे निर्देशित किया गया है कि
उक्त आवेदन/याचिका में निम्नलिखित त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं.....

1. याचिका हि0प्र0 वि0वि0आ0 के विस्तृत करोबार संचालन विनियम के अध्याय-2 में मान्य प्रारूप में नहीं है ।
2. पक्षकारों के नाम, विवरण और पता, वाद-शीर्षक में नहीं दिया गया है ।
3. निम्नलिखित आवश्यक पक्षकार अभियोजित नहीं किये गये हैं :-
अ.
ब.
स.
4. याचिका पत्र सम्यक रूप से हस्ताक्षरित नहीं है ।
5. याचिका पत्र के माध्यम से संपुष्टित नहीं है ।
6. शपथ-पत्र हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संव्यवहार) विनियम के द्वितीय अध्याय-2 के मान्य प्ररूप में नहीं है ।
7. शपथ-पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष नहीं लिखा गया तथा उनके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है ।
8. याचिका की दस प्रतियाँ दाखिल नहीं की गई हैं ।
9. याचिका की प्रतियाँ सभी तरह से पूरी तथा अभिप्रमाणित नहीं हैं ।
10. दस्तावेज प्रमाणित तथा पढ़ने योग्य नहीं है ।
11. दस्तावेजों का अनुवाद हिन्दी/अंग्रेजी/आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य भाषा में दाखिल नहीं किया गया है ।
12. दस्तावेजों के अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की अधिप्रमाणिकता नहीं की गई है ।

13. वकालतनामा/प्राधिकार पत्र दाखिल नहीं किया गया है ।
14. वकालतनामा उचित तौर पर निष्पादन नहीं किया गया और आवश्यक न्यायालय फीस संदत नहीं की गई है ।
15. याचिका/आवेदन के लिये विहित फीस संदत नहीं की गई है ।
16. दस्तावेजों की अनुक्रमणिका दाखिल नहीं की गई ।
17. दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या उचित तौर पर नहीं डाली गई हैं ।

आपसे इस पत्र के जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है ऐसा न करने पर याचिका रद्द समझी जाएगी ।

भवदीय

सचिव

उपाबन्ध-VIII

प्ररूप सी0बी0-10

[विनियम 23 (3) सी0बी0आर0 देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

..... प्रार्थी

याचिका सं.

बनाम

..... प्रत्यार्थी/प्रत्यार्थियों

दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन

मैं, उपर्युक्त मामले में दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ, ब्यौरे निम्नत् हैं :-

1. अनुज्ञा चाहने वाले व्यक्ति का नाम व पूरा पता
2. क्या वह मामले का पक्षकार है या किसी पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि है (आवश्यक विवरण दें) ।
3. निरीक्षण किये जाने वाले दस्तावेजों/प्रपत्रों के ब्यौरे
4. निरीक्षण करने का प्रयोजन
5. निरीक्षण करने की तारीख और अवधि
6. संदेय फीस की रकम तथा संदाय का ढंग

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

कार्यालय उपयोग के लिये

..... को निरीक्षण स्वीकृति/अस्वीकृत किया गया

सचिव

प्ररूप सी०बी०-११

[विनियम 23(7) सी०बी०आर० देखें]

अभिलेखों के निरीक्षण के लिये रजिस्टर

[illegible]

उपाबन्ध—X

प्ररूप सी0बी0-12

[विनियम 24 (3) सी0बी0आर0 देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

..... प्रार्थी

याचिका संख्या

बनाम

.....

याचिका बनाम प्रत्यार्थी

प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम व पता
2. क्या आवेदक पक्षकार है
3. क्या मामला लम्बित है या निपटा दिया गया है
4. तारीख सहित दस्तावेजों की प्रति का विवरण
5. प्रतियों की संख्या
6. जमा की गई रकम उसका माध्यम

हस्ताक्षर

.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

स्वीकृत/अस्वीकृत

संदाय/संदन्त अतिरिक्त प्रतियों की फीस तथा उसका ब्यौरा

.....

सचिव

3. प्रमुख शेयर-धारक/भागीदार/सदस्य

4. वितरण क्षेत्र, प्रदाय तथा कार्यक्षेत्र जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, का विवरण :

(क) प्रस्तावित वितरण/प्रदाय/कार्य क्षेत्र की सीमाएं ;

(ख) वितरण तन्त्र व्याप्ति ;

(ग) विद्युत पारेक्षण, वितरण अथवा व्यापार के लिए प्रदत्त अन्य विद्युत विज्ञप्ति/प्राधिकार, यदि कोई हो, की प्रकृति ;

(घ) विद्युत उद्गम के लिए प्रस्तावित व्यवस्था

(i) वोल्टता

(ii) विद्युत प्रदाय का उद्गम (प्रदायकर्ता का नाम)

(iii) संचालित की जाने वाली विद्युत की प्रस्तावित मात्रा

(माँग ————— मैगावाट में तथा विद्युत उर्जा ————— मिलियन युन्टस में)

(iv) क्रय मूल्य, जिस पर विद्युत उपापन प्रस्तावित है ;

(ङ) विद्युत प्रदाय —

(i) वोल्टता

(ii) विद्युत वितरण/प्रदाय के प्रवर्ग

(च) उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु फोरम प्रस्थापित करने की पद्धति

(छ) प्रदाय बाध्यताएं पूरी करने के लिए निधिकरण व्यवस्था (उद्गम तथा उपयोजन सहित)।

5. विद्युत वितरण अथवा प्रदाय क्षेत्र के विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो;

6. पारेक्षण अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के साथ की गई निष्क्रमण व्यवस्था, यदि कोई हो ;

7. निम्न विवरण देते हुए संगठन का संक्षेप —

(क) प्रबन्ध क्षमता

(ख) वित्तीय सामर्थ्य

(ग) पोषणीय रीति से विद्युत वितरण तथा प्रदाय के क्रियाकलापों के करने की क्षमता ।

8. पूर्व अनुभव (सम्बन्धित कारवार का पिछले 3 वर्ष का)

(यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी हित-साधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा) :

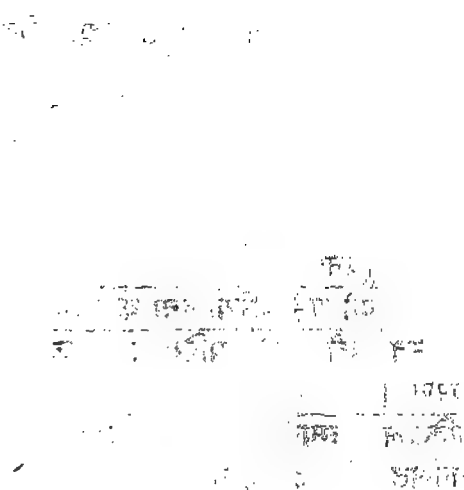

सामान्य सूचना	
विकसित की गई परियोजना के नाम तथा पते	
विकसित की गई परियोजना का संक्षिप्त विवरण ।	
मुविकल कम्पनी, जिसके लिए परियोजना विकसित की गई हो, का नाम व पता ।	
मुविकल कम्पनी के सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता ।	

9. कारवार में अपेक्षित अस्तियों तथा सुविधाओं का विवरण :

(क) क्या आवेदक विद्यमान अस्तियों को अर्जित कर रहा है अथवा नई अस्तियाँ सृजित कर रहा है ?

(ख) विद्यमान अस्तियों को अर्जित करते हुए/नई अस्तियाँ सृजित करते हुए -

निधिकरण	
<p><u>प्रस्तावित वित्तीय संसाधन :</u></p> <p>अेक्विटि (लाखों रूपयों में)</p> <p>आवेदक</p> <p>सह-संप्रवर्तक</p> <p>अन्य</p> <p><u>ऋण :</u></p> <p>घरेलू (लाखों रूपयों में)</p> <p>भारतीय वित्तीय संस्थाएं से</p>	

<p>वाणिज्यिक बैंकों से अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p><u>अन्तर्राष्ट्रीय (विदेशी मुद्रा लाखों में) :</u></p> <p>प्रदायकर्ता की जमा रकम प्रत्यक्ष उधार अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p><u>समतुल्य प्रवासी भारतीय (आई0एन0आर0)</u></p> <p>(प्रयुक्त विनियम दर)</p> <p>अन्य</p>	
<p>उस दशा में जब प्रस्तावित आस्ति उपापन/ परियोजना संयुक्ततः किसी बाह्य अभिकरण द्वारा निधिकृत हो -</p> <p>अभिकरण का नाम तथा पता, और अभिकरण के सम्पर्क व्यक्ति का सम्पर्क विवरण (नाम, पता, दूरभाष/फैक्स नम्बर, ई.मेल. इत्यादि)</p> <p>अभिकरण की प्रस्तावित अेक्विटि से अभिकरण अेक्विटि की प्रतिशतता (%)</p> <p>आवेदक तथा अन्य अभिकरण के बीच प्रस्तावित प्रतिबद्धता की प्रकृति</p>	

<p><u>आस्ति पर प्रस्तावित ऋण का विवरण</u></p> <p>उपापन/ परियोजना</p> <p>उधारदाताओं का विवरण (नाम तथा पता)</p> <p>ऋण राशि, करेंसी, ऋण अवधि, ब्याज दर, अॅप फ्रन्ट फीसैं, बचनबद्धता प्रभार</p> <p>क्या अभिकरण से ऋणों के लिए प्रत्याभूति माँगी जा रही है ?</p> <p>यदि हां तो विवरण दें ?</p>	<p>हाँ/नहीं</p>
---	-----------------

(ग) नई अस्तियाँ सृजित करने वाले आवेदकों के लिए :-

<p>निर्माण, उपापन तथा प्रचालन</p> <p>क्या आवेदक किसी निर्माण, उपापन तथा प्रचालन ठेकेदार को नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर रहा है ?</p> <p>यदि हाँ, तो उसका नाम पता तथा सम्पर्क विवरण दें</p> <p>प्रस्तावित संविदा मूल्य</p> <p>विदेशी मुद्रा</p> <p>समतुल्य प्रवासी भारतीय (आई0एन0आर0) (प्रयुक्त विनिमय दर सहित)</p>	<p>हाँ/नहीं</p>
---	-----------------

(घ) अन्य ठेकेदारों को नियोजित करने वाले आवेदनों के लिए -

<p>अन्य संविदाएं</p>	
----------------------	--

क्या आवेदक संकर्म, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए किसी ठेकेदार को नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर रहा है ? यदि हां, तो उसका नाम पता तथा सम्पर्क विवरण दें । संविदा की अवधि समान कारवार में संकर्म प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के अनुभव का विवरण ।	हां/नहीं
--	----------

(ड) टिप्पण :

- उपरोक्त परियोजना के लिए आवेदक के साथ सहयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए दूसरे अभिकरण तथा ठेकेदारों के सहमति-पत्र ;
- समुचित समय पर आवश्यक मन्जूरियाँ तथा अनापतियाँ समय पर ली जाएंगी और आयोग को अग्रेषित की जाएंगी ।

10. समुचित कार्मिक विशेषज्ञता

व्यक्ति का नाम	अर्हताएं	विशेषज्ञता	कितने वर्ष का अनुभव	फर्म में औहदा
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी/हितसाधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा)

समान्य सूचना					
समनुषंगी कारवार इकाई का नाम		विनिर्मित उत्पाद/सेवा			
1		1			
2		2			
3		3			
4		4			
5		5			
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
<u>स्थिर अस्तियाँ</u>					
सकल स्थिर अस्तियाँ					
संचित अवक्षयण					---
शुद्ध स्थिर अस्तियाँ					
<u>अेक्विटि</u>					
अभिवृद्धि					
सरकारी/ वित्तीय					
—संस्थाएँ					
सार्वजनिक					
अन्य					
<u>दायित्व</u>					
दीर्घकालिक					

लघुकालिक					
<u>आय</u> विद्युत विक्रय अन्य					
<u>व्यय</u> प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय मुरम्मत एवं अनुरक्षण कर्मचारी लागत <u>व्याज एवं वित्तीय प्रभार</u> दीर्घकालिक लघुकालिक अन्य					
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
संपूर्ण व्यापारावर्त (लाखों में)					
<u>लाभ और प्रत्यागम</u> (लाखों में) शुद्ध लाभ संदत लाभांश					
<u>प्रचालन अनुपात</u> अेक्विटि प्रत्यागम नियोजित पूंजी प्रत्यागम शुद्ध स्थिर आस्ति प्रत्यागम					

परिमाप्ति अनुपात ऋण सेवा विस्तार अनुपात चालू अनुपात तत्काल अनुपात					
पूँजी पर्याप्ता एवं उधार पात्रता ऋण/शुद्ध मुल्य ऋण/अेक्विटि					
व्यापारावर्त अनुपात कुल आस्ति व्यापारावर्त स्थिर आस्ति व्यापारावर्त					

12. आधार-रेखा सूचना (कारवार जिसके लिए अनुज्ञप्ति माँगी गई है)

सामान्य सूचना	
आस्ति आधार	
ट्रांसफार्मर (संख्या)	
500 के.वी.ए	-
250 के.वी.ए	
100 के.वी.ए	
63 के.वी.ए	
25 के.वी.ए	
10 के.वी.ए	

उच्च विभव (एटी) सर्किट किलोमीटर	
220 के.वी.	
110 के.वी.	
66 के.वी.	
33 के.वी.	
11 के.वी.	
निम्न विभव (एल.टी.) सर्किट किलोमीटर 440 वोल्ट	
वाणिज्य सूचना	
मीटरिंग प्रास्थिति मीटरिड उपभोक्ता (कुल उपभोक्ताओं से प्रतिशतता)	
बिलिंग प्रास्थिति बिलिंग (कुल निविष्ट से प्रतिशतता)	
राजस्व वसूली (प्रति युनिट विक्रय वसूली) एकगण क्षमता (%)	
हानि तकनीकी हानि (%) वाणिज्य हानि (%)	

भाग-ख अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अनुज्ञप्ति/अनुमति की प्रति सहित पूर्ववर्त अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) सम्बन्धित सूचना ;
2. कम्पनी के संगम - अनुच्छेद, संगम-ज्ञापन, भागीदारी विलेख तथा समरूप सांविधानिक दस्तावेजों की प्रतियाँ ;
3. निगमन/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण;
4. कारवार प्रारम्भ प्रमाणन;
5. हस्ताक्षरी का मूल मुख्तारनामा जिससे आवेदक अथवा इसके प्रवर्तक वचनबद्ध हो;
6. आयकर रजिस्ट्रीकरण का विवरण;
7. आयात अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) का विवरण;
8. प्रबन्धकार्य तथा वित्तीय सामर्थ्य का ब्यौरा ।

(क) प्रबन्धकीय :

(i) ज्येष्ठ प्रबन्धन का पाठ्य विवरण

(ii) कर्मचारियों के (तकनीकी और गैरतकनीकी) विभिन्न प्रवर्गों की काडर सदस्य संख्या ।

(ख) वित्तीय :

(i) बैंक प्रमाणपत्र जिसमें आवेदक के वित्तीय रूप में ऋण शोधक्षम होने का उल्लेख हो;

(ii) अति नई वार्षिक वित्तीय विवरण (तुलन-पत्र)

(iii) आवेदक तथा कोई नियंत्री कम्पनी, समनुषंगी या सहवद्ध कम्पनी के पिछले 3 वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित लेखे ;

(iv) उपरोक्त कथनों से संलग्न विख्यात चार्टर्ड एंकाउंटेंट की टिप्पणी तथा प्रमाणन ।

(ग) अन्य दस्तावेज जिससे वित्तीय सामर्थ्य, तकनीकी क्षमता तथा अन्य तथ्य साक्षित हो ।

9. आवेदक के कारवार प्रस्ताव सम्बन्धी आंकड़े :-

- (i) प्रस्तावित कारवार, जिससे आवेदन सम्बद्ध है, की पाँच वर्षीय कारवार योजना (प्रक्षेपज सहित) ;
- (ii) पाँच वर्षीय पूर्वानुमानित लागत, राजस्व, परियोजना वित्त प्रबन्ध तथा निधीयन व्यवस्था (अवेष्टित पूर्वानुमान को सपष्टतः विनिर्दिष्ट करते हुए) ।

10. विस्तृत मानचित्र -

- (i) प्रस्तावित वितरण क्षेत्र का विस्तृत विद्युत मानचित्र (जिसमें उप-केन्द्रों तथा पद्धति सांस्थिति से सम्बन्धित सूचना भी हो) तथा भूगोलिक मानचित्र, 1 किलोमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर के मापदण्ड पर अथवा आयोग द्वारा यथा अनुमोदित अन्य मापदण्ड पर बनाया जाएगा ;
- (ii) मानचित्र में विद्यमान और नई सुविधाएँ, जो विद्युत प्रदाय की बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों, को स्पष्टतौर पर चिह्नित किया जाए ;
- (iii) मानचित्र, में वे गलियाँ तथा सड़कें, जिन्हें विद्युत वितरित की जाती है, दिखाई जाएँ ;
- (iv) वितरण क्षेत्र या उसके भाग का प्रबन्धन करने वाली सभी स्थानीय प्राधिकरणों निकायों की सूची ;
- (v) भूमि जिसका आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव करता है और उसके अर्जन के साधनों का उल्लेख करते हुए, अनुमानित विवरणी ;

11. क्षेत्र में विद्युत अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खण्ड (ii) के अनुसार केन्द्रीय सरकार की ओर से विद्युत वितरण अथवा प्रदाय पर कोई आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र या उक्त मन्जूरी हेतु केन्द्रीय सरकार को दिये गये आवेदन की पावती ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबन्ध—XIII

प्ररूप सी.बी.—15

[विनियम 27 (4) तथा 28(1) सी0बी0आर0देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

प्ररूप—1 हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत पारेषण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

आवेदक, रु (शब्दों में) के आवेदन शुल्क का मांग देय
ड्राफ्ट, सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में शिमला में देय, सहित अपने
संपूरित आवेदन की प्रतियाँ सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
को भेजेगा ।

भाग क—आवेदक के बारे में सामान्य सूचना

1 आवेदन का ब्यौरा :

- (क) आवेदक का पूरा नाम
- (ख) आवेदक का पूरा पता
- (ग) सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता
- (घ) सम्पर्क दूरभाष नम्बर

फैक्स (नम्बर)

ई.—मेल आई.डी.

स्वामित्व की प्रकृति तथा विवरण :

- (क) कम्पनी/फर्म/सहकारी सोसाईटी/व्यष्टिक स्वामी/अन्य
- (ख) कम्पनी कब और कहाँ निगमित/रजिस्ट्रीकृत की गई ?

निगमन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान

निगमन वर्ष

रजिस्ट्रीकरण संख्या

फर्म/सहकारी सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण का स्थान

- (ग) निदेशकों के नाम व पते

3. प्रमुख शेयर-धारक/भागीदार/सदस्य

4. पारेषण क्षेत्र, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, का विवरण:

(क) प्रस्तावित पारेषण क्षेत्र की सीमाएँ

(ख) पारेषण तन्त्र व्याप्ति

(ग) विद्युत पारेषण, वितरण अथवा व्यापार के लिए प्रदत्त अन्य विद्युत विज्ञप्ति/प्राधिकार, यदि कोई हो, की प्रकृति :

5. राज्य पारेषण उपयोगिता के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो;

6. अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था यदि कोई हो;

7. उत्पादन कम्पनियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो;

8. निम्न विवरण देते हुए संगठन का संक्षेप —

(क) प्रबन्ध क्षमता

(ख) वित्तीय सामर्थ्य

(ग) पोषणीय रीति से क्रियाकलापों की देखभाल करने की क्षमता ।

9. पूर्व अनुभव (सम्बन्धित कारवार का पिछले 5 वर्ष का)

(यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी हित-साधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा) ।

सामान्य सूचना	
विकसित की गई परियोजना के नाम तथा पते	
विकसित की गई परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
मुवक्किल कम्पनी, जिसके लिए परियोजना विकसित की गई हो, का नाम व पता	
मुवक्किल कम्पनी के सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता	

10. कारबार में अपेक्षित अस्तियों तथा सुविधाओं का विवरण

(क) क्या आवेदक विद्यमान अस्तियों को अर्जित कर रहा है अथवा नई अस्तियां सृजित कर रहा है ?

(ख) विद्यमान अस्तियों को अर्जित करते हुए / नई अस्तियां सृजित करते हुए

निधिकरण	
<p><u>प्रस्तावित वित्तीय संसाधन</u></p> <p>अेक्विटि (लाखों रूपयों में)</p> <p>आवेदक</p> <p>सह-संप्रवर्तक</p> <p>अन्य</p> <p><u>ऋण</u></p> <p>घरेलू (लाखों रूपयों में)</p> <p>भारतीय वित्तीय संस्थाओं से</p> <p>वाणिज्यिक बैंकों से</p> <p>अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p><u>अन्तर्राष्ट्रीय (विदेशी मुद्रा लाखों में)</u></p> <p>प्रदायकर्ता की जमा रकम</p> <p>प्रत्यक्ष उधार</p> <p>अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p><u>समतुल्य प्रवासी भारतीय (आई.एन.आर)</u></p> <p>(प्रयुक्त विनियम दर)</p> <p>अन्य</p>	

<p>उस दशा में जब प्रस्तावित आस्तिय उपापन/परियोजना संयुक्ततः किसी बाह्य अभिकरण द्वारा निधिकृत हो -</p> <p>अभिकरण का नाम तथा पता, और अभिकरण के सम्पर्क व्यक्ति का सम्पर्क विवरण (नाम, पता, दूरभाष/फैक्स नम्बर, ई. मेल. इत्यादि)</p> <p>अभिकरण की प्रस्तावित अेक्विटि से अभिकरण अेक्विटि की प्रतिशतता (%)</p> <p>आवेदक तथा अन्य अभिकरण के बीच प्रस्तावित प्रतिबद्धता की प्रकृति</p>	
<p><u>आस्ति पर प्रस्तावित ऋण का विवरण</u></p> <p>उपापन/ परियोजना</p> <p>उधारदाताओं का विवरण (नाम तथा पता)</p> <p>ऋण राशि, करैसी, ऋण अवधि, ब्याज दर, अॅप फ्रन्ट फीसैं, वचनबद्धता प्रभार</p> <p>क्या अभिकरण से ऋणों के लिए प्रत्याभूति मांगी जा रही है ?</p> <p>यदि हां तो विवरण दें</p>	<p>हां/ नहीं</p>

(ग) नई अस्तियां सृजित करने वाले आवेदकों के लिए -

निर्माण, उपापन तथा प्रचालन	
क्या आवेदक किसी निर्माण, उपापन तथा प्रचालन ठेकेदार को नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर रहा है? यदि हां, तो उसका नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण दें प्रस्तावित संविदा मूल्य विदेशी मुद्रा समतुल्य प्रवासी भारतीय (आई.एन.आर) (प्रयुक्त विनिमय दर सहित)	हां/नहीं

(घ) अन्य ठेकेदारों को नियोजित करने वाले आवेदनों के लिए -

अन्य संविदाएं	
क्या आवेदक संकर्म, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए किसी ठेकेदार को नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर रहा है? यदि हां, तो उसका नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण दें । संविदा की अवधि समान कारबार में संकर्म प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार के अनुभव का विवरण ।	हां/नहीं

(ङ) टिप्पण :

1. उपरोक्त परियोजना के लिए आवेदक के साथ सहयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए दूसरे अभिकरण तथा ठेकेदारों के सहमति पत्र;

2. समुचित समय पर आवश्यक मन्जूरियाँ तथा अनापत्तियाँ समय पर ली जाएंगी और आयोग को अग्रेषित की जाएगी ।

11. समुचित कार्मिक विशेषज्ञता

व्यक्ति का नाम	अर्हताएं	विशेषज्ञता	कितने वर्ष का अनुभव	फर्म में औहदा
1				
2				
3				
4				
5				

12. आवेदक के अन्य कारबार उद्यम का वित्तीय विवरण (यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी/हितसाधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा)

सामान्य सूचना					
समनुषंगी कारबार इकाई का नाम		विनिर्मित उत्पाद/सेवा -			
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
स्थिर अस्तियाँ					
सकल स्थिर अस्तियाँ संचित अवक्षयण					
शुद्ध स्थिर अस्थियाँ					

<u>अेक्विति</u> अभिवृद्धि सरकारी / वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक अन्य					
<u>दायित्व</u> दीर्घकालिक लघु कालिक					
<u>आय</u> विद्युत विक्रय अन्य					
<u>व्यय</u> प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय मुरम्मत एवं अनुरक्षण कर्मचारी लागत <u>ब्याज एवं वित्तीय प्रभार</u> दीर्घकालिक लघुकालिक अन्य					
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
संपूर्ण व्यापारावर्त (लाखों में)					

<u>लाभ और प्रत्यागम</u> (लाखों में) शुद्ध लाभ सदेत लाभांश					
<u>प्रचालन अनुपात</u> अक्विटि प्रत्यागम नियोजित पूंजी प्रत्यागम शुद्ध स्थिर आस्ति प्रत्यागम					
<u>परिमापित अनुपात</u> ऋण सेवा- विस्तार अनुपात चालू अनुपात तत्काल अनुपात					1078 1715/16
<u>पूंजी पर्याप्ता एवं</u> <u>उधार</u> <u>पात्रता</u> ऋण / शुद्ध मुल्य ऋण / अक्विटि					1078 1715/16 1078 1715/16

व्यापारावर्त अनुपात				
कुल आस्ति				
व्यापारावर्त				
स्थिर आस्ति				
व्यापारावर्त				

13. आधार-रेखा सूचना (कारबार जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है)

सामान्य सूचना	

भाग-ख—अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अनुज्ञप्ति/अनुमति को प्रति सहित पूर्ववर्त अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) सम्बन्धित सूचना ;
2. कम्पनी के संगम - अनुच्छेद, संगम-ज्ञापन, भागीदारी विलेख तथा समरूप सांविधानिक दस्तावेजों की प्रतियां ;
3. निगमन/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण;
4. कारबार प्रारम्भ प्रमाणन;
5. हस्ताक्षरी का मूल मुख्तारनामा जिससे आवेदक अथवा इसके प्रवर्तक वचनबद्ध हो;
6. आयकर रजिस्ट्रीकरण का विवरण;
7. आयात अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) विवरण;

8. प्रबन्धकार्य तथा वित्तीय सामर्थ्य का ब्यौरा;

(क) प्रबन्धकीय

(i) ज्येष्ठ प्रबन्धन का पाठ्य विवरण

(ii) कर्मचारियों के (तकनीकी और गैर-तकनीकी) विभिन्न प्रवर्गों की काडर सदस्य संख्या;

(ख) वित्तीय

(i) बैंक प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक के वित्तीय रूप में ऋणशोधक्षम होने का उल्लेख हो;

(ii) अति नई वार्षिक वित्तीय विवरण (तुलन-पत्र)

(iii) आवेदक तथा कोई नियंत्री कम्पनी, समनुषंगी या सहबद्ध कम्पनी के पिछले 3 वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित लेखे ;

(iv) उपरोक्त कथनों से संलग्न विख्यात चार्टर्ड एंकाउंटेंट की टिप्पणी तथा प्रमाणन;

(ग) अन्य दस्तावेज़ जिससे वित्तीय सामर्थ्य, तकनीकी क्षमता तथा अन्य तथ्य साक्षित हो।

9. आवेदक के कारबार प्रस्ताव सम्बन्धी आंकड़े -

(i) प्रस्तावित कारबार, जिससे आवेदन सम्बद्ध है, की पांच वर्षीय कारबार योजना (प्रक्षेपज सहित) ;

(ii) पांच वर्षीय पूर्वानुमाणित लागत, राजस्व, परियोजना वित्त प्रबन्ध तथा निधीयन व्यवस्था (अवेटित पूर्वानुमान को स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करते हुए) ।

10. भूमि जिसे आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव करता है और उसके अर्जन के साधनों का उल्लेख करते हुए, अनुमाणित विवरणी ;

11. राज्य पारेषण उपयोगिता के द्वारा संलको एवं दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रति की तामील की पावती ।

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबन्ध—XIV

प्ररूप सी.बी.—16

[विनियम 27 (4) तथा 28(1) सी.बी.आर.देखें]

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

प्ररूप-1 हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का प्ररूप

आवेदक, रु (शब्दों में) के आवेदन शुल्क का मांग-देय ड्राफ्ट, सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में शिमला में देय, सहित अपने संपूरित आवेदन की प्रतियां सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को भेजेगा ।

भाग-क—आवेदक के बारे में सामान्य सूचना

1 आवेदन का ब्यौरा :

- (क) आवेदक का पूरा नाम
- (ख) आवेदक का पूरा पता
- (ग) सम्पर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता
- (घ) सम्पर्क दूरभाष नम्बर

फैक्स (नम्बर)
ई.—मेल आई.डी.

2. स्वामित्व की प्रकृति तथा विवरण :

- (क) कम्पनी/फर्म/सहकारी सोसाईटी/व्यष्टिक स्वामी/अन्य;
- (ख) कम्पनी कब और कहां निगमित/रजिस्ट्रीकृत की गई ?

निगमन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान
निगमन वर्ष
रजिस्ट्रीकरण संख्या
फर्म/सहकारी सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण का स्थान

- (ग) निदेशकों के नाम व पते

3. प्रमुख शेयर-धारक/भागीदार/सदस्य

4. कार्य क्षेत्र का विवरण:

विद्युत पारेषण, वितरण अथवा व्यापार के लिए प्रदत्त अन्य विद्युत विज्ञप्ति/प्राधिकार, यदि कोई हो, की प्रकृति ।

5. प्रचालन विवरण :

आवेदक द्वारा पहले तीन वर्षों में मासिक आधार पर किया जाने वाला प्रस्तावित अधिकतम व्यापार मात्रा

6. बाध्यताएं पूरी करने के लिए निधिकरण व्यवस्था (उद्गम तथा उपयोजन सहित)

7. विद्युत क्रय की व्यवस्था

8. विद्यमान विद्युत में व्यापार तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो;

9. निम्न विवरण देते हुए संगठन का संक्षेप —

(क) प्रबन्ध क्षमता

(ख) वित्तीय सामर्थ्य

(ग) पोषणीय रीति से क्रियाकलापों की देखभाल करने की क्षमता ।

10. पूर्व अनुभव (सम्बन्धित कारबार का पिछले 5 वर्ष का)

(यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी हित-साधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा) ।

सामान्य सूचना	
विकसित की गई परियोजना के नाम तथा पते	
विकसित की गई परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
मुविकल कम्पनी, जिसके लिए परियोजना विकसित की गई हो, का नाम व पता	

मुवकिल कम्पनी के सम्पर्क व्यक्ति का नाम,
पदनाम तथा पता

11. आवेदक के अन्य कारबार उद्यम का वित्तीय विवरण

(यथा लागू हो, आवेदक या सहउद्यम कम्पनी/हितसाधन की दशा में प्रत्येक भागीदार के द्वारा पृथकतः भरा जाएगा) ।

सामान्य सूचना					
समनुषंगी कारबार इकाई का नाम		विनिर्मित उत्पाद/सेवा			
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
<u>स्थिर अस्तियाँ</u> सकल स्थिर अस्तियां संचित अवक्षयण भुद्ध स्थिर अस्तियां					
<u>अेक्विटि</u> अभिवृद्धि सरकारी/वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक अन्य					
<u>दायित्व</u> दीर्घकालिक लघुकालिक					

<u>आय</u> विद्युत विक्रय अन्य					
<u>व्यय</u> प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय मुरम्मत एवं अनुरक्षण कर्मचारी लागत <u>ब्याज एवं वित्तीय प्रभार</u> दीर्घकालिक लघुकालिक अन्य					
वित्तीय सूचक	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
संपूर्ण व्यापारावर्त (लाखों में)					
<u>लाभ और प्रत्यागम</u> (लाखों में) शुद्ध लाभ सदत्त लाभांश					
<u>प्रचालन अनुपात</u> अेक्विटि प्रत्यागम नियोजित पूंजी प्रत्यागम					

शुद्धि स्थिर आस्ति प्रत्यागम					
<u>परिमाप्ति अनुपात</u> ऋण सेवा विस्तार अनुपात चालू अनुपात तत्काल अनुपात					
<u>पूंजी पर्याप्ता एवं</u> <u>उधार पात्रता</u> ऋण / शुद्ध मुल्य ऋण / अेक्विटि					
<u>व्यापारावर्त अनुपात</u> कुल आस्ति व्यापारावर्त स्थिर आस्ति व्यापारावर्त					

12. आधार-रेखा सूचना (कारबार जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है)

[illegible]

भाग-ख—अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अनुज्ञप्ति/अनुमति की प्रति सहित पूर्ववर्त अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) सम्बन्धित सूचना ;
2. कम्पनी के संगम – अनुच्छेद, संगम-ज्ञापन, भागीदारी विलेख तथा समरूप सांविधानिक दस्तावेजों की प्रतियां ;
3. निगमन/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण;
4. कारबार प्रारम्भ प्रमाणन;
5. हस्ताक्षरी का मूल मुख्तारनामा जिससे आवेदक अथवा इसके प्रवर्तक वचनबद्ध हो;
6. आयकर रजिस्ट्रीकरण का विवरण;
7. प्रबन्धकार्य तथा वित्तीय सामर्थ्य का ब्यौरा;

(क) प्रबन्धकीय

(i) ज्येष्ठ प्रबन्धन का पाठ्य विवरण ;

(ii) कर्मचारियों के (तकनीकी और गैरतकनीकी) विभिन्न प्रवर्गों की काडर सदस्य संख्या;

(ख) वित्तीय

(i) बैंक प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक के वित्तीय रूप में ऋणशोधक्षम होने का उल्लेख हो;

(ii) अति नई वार्षिक वित्तीय विवरण (तुलन-पत्र);

(iii) आवेदक तथा कोई नियंत्री कम्पनी, समनुषंगी या सहवद्ध कम्पनी के पिछले 3 वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित लेखे ;

(iv) उपरोक्त कथनों से संलग्न विख्यात चार्टर्ड एंकाउंटेंट की टिप्पणी तथा प्रमाणन;

(ग) अन्य दस्तावेज जिससे वित्तीय सामर्थ्य, तकनीकी क्षमता तथा अन्य तथ्य साक्षित हो।

8. आवेदक के कारबार प्रस्ताव सम्बन्धी आंकड़े ;
9. प्रस्तावित कारबार, जिससे आवेदन सम्बद्ध है, की पाँच वर्षीय कारबार योजना (प्रक्षेपज सहित)
10. पाँच वर्षीय पूर्वानुमानित लागत, राजस्व, परियोजना वित्त प्रबन्ध तथा निधीयन व्यवस्था (अवेष्टित पूर्वानुमान को स्पष्टतः विनिर्दिष्ट करते हुए)
11. भूमि जिसका आवेदक अपनी अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का प्रस्ताव करता है और उसके अर्जन के साधनों का उल्लेख करते हुए, अनुमानित विवरणी ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबन्ध—XV
प्ररूप सी.बी.—17
(विनियम 34 सी0बी0आर0देखें)

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

सूचना

सभी हितबद्ध व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

..... (आवेदन का नाम व पता) ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग को (कार्यक्षेत्र विनिर्दिष्ट करे) के क्षेत्र में (अनुज्ञप्ति की प्रकृति) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदित किया हो दाखिल किये आवेदन तथा दस्तावेज आवेदिक के कार्यालय में निरीक्षित किए जा सकते हैं तथा उनकी प्रतियां, मूल्य पर, जो फोटो प्रतिलिपि सामान्य खर्च से अधिक न हो, आवेदक के पास क्रय के लिए उपलब्ध होंगी।

कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में आक्षेप देना या अन्यथा अभ्यावेदन देना चाहता हो, वह अपने आक्षेप/अभ्यावेदन की प्रतियां दस्ती अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा, अग्रेषित कर सकता है और आक्षेप/अभ्यावेदन की एक प्रति उपरोक्त पते पर को भेजेगा।

आक्षेप/अभ्यावेदन भेजने वाले व्यक्तियों को निम्न विशिष्टियां भी देनी होंगी:—

1. नाम तथा पूरा पता
2. दस्तावेज अथवा साक्ष्य सहित (यदि कोई हो) आक्षेप/अभ्यावेदन को समर्थन में आधार/कारण।
3. क्या सुनवाई के समय उसे अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुना जाए।

उपाबन्ध—XVI

प्ररूप सी.बी.18

(विनियम 49 सी0बी0आर0 देखें)

उत्पादन कम्पनियों द्वारा तकनीकी विवरण प्रस्तुत करने के लिए रूपविधान

1. साधारण:

- (क) कम्पनी का नाम;
- (ख) रजिष्ट्रीकृत कार्यालय का पता;
- (ग) पत्र-व्यवहार के लिए पोस्टल पता;
- (घ) प्रस्तावित उत्पादन केन्द्र अवस्थिति;

- ... (क) जिला
- (ख) तहसील

2. प्रस्तावित उत्पादन इकाई विशिष्टियां:

- (क) संयंत्र की के.वी.ए. में क्षमता;
- (ख) इकाईयों की संख्या;
- (ग) प्रत्येक इकाई की क्षमता;
- (घ) फेज संख्या;
- (ङ) शक्तिगुण;
- (च) आवृत्ति (एच.जेड.);
- (छ) अन्य उपस्कर की तकनीकी विनिर्देश;
- (ज) उत्पादन वोल्टता

3. प्रस्तावित उर्जा संयंत्र ईंधन व्यवस्था:

- (क) कोयला/गैस/नाफ्ता;
- (ख) अन्य (ईंधन का नाम);
- (जो लागू नहीं उसे काट दें)

4. ईंधन प्रदाय के लिए टाई-अप व्यवस्था:

- (बड़ी इकाईयों के लिए — एम.वी.ए. और इससे अधिक)
- (क) क्या ईंधन/कोयला सम्पर्क व्यवस्था सुनिश्चित होगी? यदि हां तो विवरण दें;
- (ख) क्या ईंधन परिवहन करार कर लिया गया है? यदि हां तो विवरण दें;

5. अन्य तकनीकी विशिष्टियां:

- (क) उत्पादन के प्रारम्भ की प्रस्तावित तारीख;

-
- (ख) जनरेटर, प्राईम मूवर, एक्साईटर; स्विचगियर संरक्षण; अनुज्ञप्तिधारी की अन्तर सम्पर्क सुविधाओं से सम्बन्धित परियोजना के प्रमुख लक्षण ;
(पृथकया संलग्न किए जाएं)
- (ग) एम.डब्ल्यू में योजनाबद्ध पीक उत्पादन;
- (घ) संयंत्र का भारकारक;
- (ङ) एम. डब्ल्यू में उद्योग की वार्षिक विद्युत अपेक्षाओं का योग;
- (च) एम.डब्ल्यू में उद्योग की पीक अपेक्षाएँ;
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से अन्तरीय सम्पर्क के लिए अपेक्षित वोल्टता;
- (ज) अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय हेतु समीपतम अन्तरीय सम्पर्क स्थल;
- (झ) यदि उत्पादन इकाईयां समानान्तर रूप से संचालित की जानी प्रस्तावित हैं,
तो उनके ताल मेल की व्यवस्था;
- (ञ) प्रस्तावित अन्तरीय सम्पर्क की प्राक्कलित लागत;

तारीख :

हस्ताक्षर

उपाबन्ध—XVII
(विनियम 57 देखें)

भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू उपबन्ध

भारतीय दण्ड संहिता

धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड.—जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ;

और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण 1 — सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है ।

स्पष्टीकरण 2 — न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो ।

धारा 219 — न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक लेखक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना.—जो कोई लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेशपूर्वक देगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा 228 — न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न.— जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जब कि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता

धारा 345— अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया.— (1) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, या धारा 228 में वर्णित है, किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है तब न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है और उसी दिन न्यायालय के उठने के पूर्व किसी समय, अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दण्डित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराधी को दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर एक मास तक की अवधि के लिए जब तक की ऐसा जुर्माना उससे पूर्वतर न दे दिया जाए, सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है, अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित, तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित करेगा ।

(3) यदि अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 288 के अधीन है तो अभिलेख में यह दर्शित हो कि जिस न्यायालय के कार्य में विघ्न डाला गया था या जिसका अपमान किया गया था, उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के सम्बन्ध में और उसके किस प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार का विघ्न डाला गया या अपमान किया गया था ।

धारा 346— जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया.— (1) यदि किसी मामले में न्यायालय का यह विचार है कि धारा 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए, अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए या उस पर दो सौ रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की यह राय है कि मामला धारा 345 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए तो वह न्यायालय उन तथ्यों को जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबन्धित प्रकार से अभिलिखित करने, के पश्चात् मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक हो सके इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT***HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(CONDUCT OF BUSINESS) REGULATIONS, 2004****NOTIFICATION**

Shimla, the 17th November, 2004

No. HPERC/Secy/151/2004.—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (g), (zg) and (zl) of sub-section (2) of section 181, read with clause (g) of sub-section (1) of section 86 and sub-section (1) of section 92 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published, as required under sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration, after the expiry of the thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with the objections/suggestions which may be received in respect thereto within the aforesaid period.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS**CHAPTER-I****PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004.

(2) These regulations extend to the whole of the State of Himachal Pradesh;

(3) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission;
- (c) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (d) “Member” means a Member of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (e) “Officer” means an officer of the Commission;
- (f) “petitions” shall mean and include all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinder and supplemental pleadings;
- (g) “proceedings” shall mean proceedings of all nature that the Commission may decide to initiate or hold in the discharge of its functions under the Act but any preliminary meeting or any action taken by the Commission before such initiation shall not be a proceeding for the purposes of these regulations;
- (h) “Receiving Officer” shall mean the officer designated by the Commission for receiving the petition;
- (i) “regulations” means these regulations;
- (j) “Secretary” means the Secretary of the Commission;
- (k) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh; and
- (l) Other words or expressions occurring in these regulations, but not defined herein, shall have the same meaning as are assigned to them in the Act.

3. Commission’s offices, office hours and sittings.—(1) The place(s) of the office(s) of the Commission may from time to time be decided by the Commission, by an order made in that behalf.

(2) Unless otherwise directed by the Commission, the headquarters and other offices of the Commission shall remain open on all days except on Second Saturday of every month, Sundays and holidays notified by the State Government.

(3) The headquarters and other offices of the Commission shall be open at such times as the Commission may direct.

(4) Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason thereof, the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

(5) The Commission may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be decided by the Commission.

(6) The Commission may hold formal or informal interactions with the various consumer interest groups, non-governmental organizations, or other stakeholders in the discharge of its duties, at the headquarters or at any other place on days and time to be decided by the Commission.

4. Language of the Commission.—(1) The proceedings of the Commission shall be conducted in English.

(2) No petition, documents or other matters contained in any language other than English shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a translation thereof in English.

(3) Any translation which is agreed to by the parties to the proceedings or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person, who had translated into English, may be accepted by the Commission in appropriate cases as a true translation.

(4) The Commission may in appropriate cases direct translation of the petitions, pleadings, documents and other material to English by an officer or person designated by the Commission for the purpose.

5. Seal, emblem and flag of the Commission.—(1) There shall be a separate seal, emblem and distinctive flag, indicating that these are the official seal, emblem and flag of the Commission.

(2) The seal of the Commission shall be circular in shape having inscription “H. P. Electricity Regulatory Commission” in its outer ring and the word “SHIMLA” in the inner ring, as under:—



(3) Every order, decision or communication made, notice issued or certified copy granted by the Commission shall be stamped with the seal of the Commission and shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission designated for the purpose and duly authorized by the Chairperson in that behalf.

(4) The emblem of the Commission shall be circular in the shape having the mountainous background of the Pradesh with a projection of a balance rested on transmission tower and the tower connected to a generating station, with the scales on either side representing the Consumers and the Utility. The Emblem shall have the inscription "H. P. Electricity Regulatory Commission" in the upper outer ring and "TRUTH TRIUMPHS" in the bottom outer ring, as under:—



(5) The flag to be displayed on the mount of the staff car of the Chairperson and of the Members shall be of rectangular shape of 250 x 150 mm, with the yellow background and the emblem of the Commission in indigo colour on both sides, as under:—





6. Appointment of Secretary, officers and Employees of the Commission.—

(1) The Commission may have Secretary, and officers and other employees for discharging various duties. It may also prescribe qualifications, experience and other terms and conditions for appointment of such Secretary, officers and other employees in conformity with the provisions of the Act.

(2) The appointment of the Secretary, officers and employees of the Commission shall, unless otherwise directed by the Commission, be made by the Chairperson.

(3) The Chairperson may appoint Consultants to assist the Commission in the discharge of its functions.

7. Functions and duties of the Secretary.—(1) The Secretary shall exercise such functions as are assigned to him by these Regulations or otherwise by the Chairperson.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of the sub-regulation (1), the Secretary shall perform the following functions, namely:—

- (a) he shall receive or cause to receive all petitions, applications, other filings or references pertaining to the Commission;
- (b) he shall prepare or cause to prepare the briefs and summaries of all such filings presented before the Commission;
- (c) he shall assist the Commission in proceedings conducted by the Commission;
- (d) he shall authenticate the orders passed by the Commission;
- (e) he shall ensure compliance of the orders passed by the Commission;
- (f) he shall have the right to collect from the State Government, the Central Government and their agencies, the State Electricity Boards or other offices,

companies and firms or any other person as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act;

(g) he shall—

- (i) maintain and cause to be maintained the updated master copy of the Electricity Act, 2003 and subsequent amending enactments and keep a register containing their particulars and details in Form CB-I in Annexure-I;
- (ii) maintain or cause to be maintained in the chronological order the collection of the statutory notifications, rules, orders and directions, regulations made by—
 - (a) the Central Government;
 - (b) the Central Electricity Authority;
 - (c) the State Government;

and keep the register containing their particulars and details given in Form CB-2 in Annexure-I;

- (iii) maintain or cause to be maintained in the chronological order the collection of authentic copies of regulations, statutory notifications and orders issued by the Commission; and keep the register containing their particulars and details given in Form CB-3 in Annexure-I;
- (iv) provide or cause to be provided all orders, directions and regulations made by the Commission, immediately after these are made, on the website of the Commission; and

(h) he shall, on behalf of the Commission,—

- (i) in suits against the Commission, accept the service of the summon ; and
- (ii) in source by or against the Commission, sign and verify the complaints and pleadings.

(3) The Secretary shall have the custody of the seal and records of the Commission.

(4) The Secretary may, with the approval of the Chairperson, delegate to any other officer of the Commission any function required by these regulations or otherwise, to be exercised by the Secretary.

(5) The Commission shall always have the authority, either on an application made by any interested or affected party, or *suo motu*, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or other officers of the Commission, if the Commission considers it to be appropriate.

(6) Where the Secretary fails or neglects to perform any or all the functions, or to discharge any or all the duties, assigned to him under the Act or the Regulations framed thereunder, the Chairperson shall, after affording him reasonable opportunity of being heard or if appointed otherwise than on deputation, remove him or, if appointed on deputation, repatriate him after due notice, to his parent organization.

8. Delegation of Powers.—(1) Save and except the powers exercisable under sections 14, 18, 86, 91, 94 and 181 of the Act, the Commission may, by a general or special order in writing, delegate to any (Member or) officer of the Commission such of powers and functions under the Act as it may deem necessary, subject to such terms and conditions, if any, as may be stated in such order.

(2) The Chairperson may delegate to the officers of the Commission such functions, which may be required by these regulations to be exercised by the Secretary, on such terms and conditions as the Chairperson may direct for the purpose.

(3) In the absence of the Secretary, such other officers of the Commission, as may be designated by the Chairperson, may perform all or any of the functions of the Secretary.

CHAPTER – II

**GENERAL PROVISIONS CONCERNING THE PROCEEDINGS
BEFORE THE COMMISSION**

9. Proceedings before the Commission.—(1) The Commission may from time to time hold such proceedings as it may consider to be appropriate in the discharge of its functions under the Act.

(2) The Commission may appoint an officer or any other person whom the Commission considers it to be appropriate to participate and assist the Commission in the proceedings.

(3) All matters which the Commission is required under the Act to undertake and discharge through hearings shall be done through hearings in the manner specified under the Act and in these regulations.

(4) Except where the Commission may provide otherwise for reasons to be recorded in writing, all matters affecting the rights or interests of the licensee or any other person or class of persons shall be undertaken and discharged through hearings in the manner specified in these regulations.

(5) The Commission may hold hearings in matters, other than those specified in sub-regulations (3) and (4), if the Commission considers it to be appropriate.

(6) The Commission may hold consultations with the parties or any one or more of them before deciding on the initiation of a proceedings in any matter.

10. Authorized representative to appear before Commission.—(1) A person may appear himself or may authorize any of his employees to appear before the Commission and to act and plead on his behalf.

(2) A person may authorize an advocate or a member of any statutory professional body holding a certificate of practice as the Commission may from time to time direct to represent him and to act and plead on his behalf before the Commission.

(3) The Commission may from time to time decide the terms and conditions subject to which a person may authorize any other person to represent him and to act and plead on his behalf and the type of authorization to be provided to the Commission for the purpose.

(4) Notwithstanding the above, the Commission may allow any consumer group or association or any persons duly authorized by such consumer group or association to appear in any proceeding before the Commission or in any meeting before the initiation of the proceedings on such terms and conditions, in regard to the nature and extent of participation as the Commission may consider it to be appropriate.

(5) It shall be open to the Commission for the sake of timely completion of proceedings to direct grouping of associations/groups/fora referred to above for submission of respective petitions/affidavits collectively.

(6) The Commission may as and when considered appropriate notify a procedure for recognition of associations, groups, fora or bodies corporate as registered consumer association for purposes of representation before the Commission.

(7) The Chairperson may appoint or authorise any officer or any other person to represent the interest of consumers, and may direct payment to the officer or person appointed or so authorised to represent the Consumer's interest such fees, costs and expenses by such of the parties to the proceedings as the Chairperson may consider appropriate.

11. Initiation of proceedings.—(1) The Commission may initiate any proceedings *suo motu* or on a petition filed by any affected or interested person.

(2) When the Commission initiates the proceedings, it shall be by a notice issued by the office of the Commission and the Commission may give such orders and directions as may be deemed necessary, for service of notice to the affected or interested parties and for the filing of replies and rejoinders in opposition or in support of the petition in such form as the Commission may direct.

(3) The Commission may, if it considers it to be appropriate, issue orders for advertisement of the petition inviting comments on the issues involved in the proceedings in such form as the Commission may direct.

(4) While issuing the notice, the Commission may, in *suo motu* proceedings and in other appropriate cases, designate an officer of the Commission or any other person whom the Commission considers it to be appropriate to present the matter in the capacity of a petitioner in the case.

12. Petitions before the Commission.—(1) All petitions shall contain a clear and concise statement of the facts with material particulars, the relief sought, the applicable provisions of law and the basis for such relief.

(2) All petitions to be filed before the Commission shall be type written, cyclostyled or printed neatly and legibly on white paper and every page shall be consecutively numbered. The petition shall be filed in 10 copies or such other number of copies if the Commission so directs and all such copies shall be complete in all respects. The Commission may, in addition, seek copies of the petition to be filed in an electronic form, on such terms and conditions, as the Commission may direct.

(3) The contents of the petition shall be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially.

(4) The petition shall be accompanied by a paper book containing such documents, supporting data and statements, as are relevant to the matters in issue in the petition together with index of documents.

(5) The fee specified by the Commission shall be paid at the time of or before the presentation of the petition.

(6) The fees received shall be entered into the register prescribed for the purpose in the Form CB-4 (Annexure-II).

13. General headings.—The general heading in all petitions before the Commission and in all advertisements and notices shall be in the Form CB-5 (Annexure-III).

14. Affidavit in support.—(1) The petitions filed shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in the Form CB-6 (Annexure-IV):

Provided that the Commission may, at its discretion, waive the requirement of affidavit in any particular case.

(2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavits.

(3) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements which are true to the,—

- (i) knowledge of the deponent;
- (ii) information received by the deponent; and
- (iii) belief of the deponent.

(4) Where any statement in affidavit is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.

15. Presentation and scrutiny of the pleadings, etc.—(1) All petitions shall be filed with ten copies and each set of the petition shall be complete in all respects.

(2) All petitions shall be presented in person or by any duly authorized agent to an officer designated for the purpose by the Commission (the Receiving Officer) at the headquarters of the Commission or at such other place or places as may be notified by the Commission from time to time and during the time notified. The petitions may also be sent by registered post with acknowledgement due to the Commission at the aforementioned places.

(3) The vakaltnama in favour of the Advocate and, in the event the petitions are presented by the authorized agent or representative, the document authorizing the agent or representative shall be filed alongwith the petition. Any person other than a legal practitioner representing a party before the Commission shall file a Memorandum of Appearance in Form CB-7 (Annexure-V) duly signed by him.

(4) The presentation and the receipt of the petition shall be duly entered in the register maintained, for the purpose by the office of the Commission in form CB-8 (Annexure-VI).

(5) Upon the receipt of the petition, the Receiving Officer shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the petition has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date to the person filing the petition. In case the petition is received by registered post the date on which the petition is actually received at the office of the Commission shall be taken as date of the presentation of the petition.

(6) The Receiving Officer may decline to accept any petition which is not in conformity with the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the

Commission or is otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with these regulations or directions of the Commission:

Provided however, that no petition shall be refused for defects in the pleadings or in the presentation, without giving an opportunity to the person filing the petition to rectify the defect within the time, which may be allowed for the purpose. The Receiving Officer shall advise in writing, in Form CB-9 (Annexure-VII) the person filing the petition of the defects in the petition filed and the time within which the defects be rectified.

(7) A party aggrieved by any order of the Receiving Officer in regard to the presentation of the petition may request the matter to be placed before the Secretary of the Commission for appropriate orders.

(8) The Chairperson or any Member as the Chairperson may designate for the purpose, shall be entitled at any time to call for the petition presented by the party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petition, as he considers appropriate.

(9) If on scrutiny, the petition is not refused or any order of refusal is modified by the Secretary or by the Chairperson or the Member of the Commission designated for the purpose, the petition shall be duly registered and given a number in the manner directed by the Commission.

(10) As soon as the petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed and the petition has been scrutinized and numbered, the petition shall be placed before the Commission for admission:

Provided, however, that in the case of complaints of individual consumers, class of consumers or any consumer organizations, the Secretary of the Commission may refer the matter to the Forum for redressal of the grievances of the Consumers established for the purpose in terms of sub-section (5) of section 42 of the Act and the regulations framed by the Commission under the said provisions.

(11) The Commission may admit the petition for hearing without requiring the attendance of the party filing the petition. The Commission shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity of being heard. The Commission may, if it considers appropriate, issue notice to such person or persons, as it may desire to hear on the petition for admission.

(12) If the Commission admits the petition, it may give such orders and directions as may be considered necessary, for service of notices to the respondent and other affected or interested parties and for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition in such form as the Commission may direct and for the petition to be placed for hearing before the Commission.

16. Service of notices and processes issued by the Commission.—(1) Any notice or process to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes, as may be directed by the Commission,—

- (i) service by any of the parties to the proceedings as may be directed by the Commission;
- (ii) by hand delivery through a messenger;
- (iii) by registered post with acknowledgement due;
- (iv) by publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above;
- (v) in any other manner as may be considered appropriate by the Commission.

(2) Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(3) In the event any matter is pending before the Commission and the person to be served has authorized an agent or representative to appear for or represent him in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served. It shall be the duty of such agent or representative to duly inform the person, whom he represents, of the service of the notices and processes.

(4) Where a notice or process is served by a party to the proceedings either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by such party with the Commission giving details of the date, manner and proof of service of the notice or the process as the case may be.

(5) Where any petition is required to be published in newspapers it shall be done within such time as the Commission may direct and, unless otherwise directed by the Commission, such publication shall be made in one issue each of a daily newspaper in

English language and in Hindi language having wide circulation in the area specified by the Commission:

Provided that the publication shall be made not less than seven days before the date fixed for hearing.

(6) The Commission may also effect service or give directions for effecting service in any other manner it considers appropriate.

(7) The Commission shall be entitled to decide in each case the person(s) who shall bear the cost of such service and publication.

(8) Save as otherwise provided in the Act or in this Regulation and subject to any direction which the Commission or the Secretary or the Officer of the Commission designated for the purpose may issue, the petitioner, the applicant or any other person whom the Commission may make responsible, shall arrange for service of notices, summons, processes and for publication of notices and processes required to be served or published.

(9) In default of compliance with the requirements of the regulations or directions of the Commission as regards the service of notices, summons or processes or the advertisement and publication thereof, the Commission may either dismiss the petition or give such other or further directions, as it thinks fit.

(10) No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of person provided that the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient.

(11) No proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity in the service or publication unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity in publication or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

17. Filing of reply, opposition, objections, etc.—(1) Each person to whom the notice of inquiry or the petition is issued (hereinafter called the respondent) who intends to oppose or support the petition shall file the reply and the documents relied upon within such period with ten copies and in such number of copies as may be directed by the Commission.

(2) In the reply filed, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the petition and may also state such additional facts as he considers necessary for a just decision of the case.

(3) The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the petition. The respondent shall also indicate whether he wishes to participate in the proceedings and be orally heard.

(4) The respondent shall serve a copy of the reply alongwith the documents duly attested to be true copies on the petitioner or his authorized representative and file proof of such service with the office of the Commission at the time of filing the reply.

(5) Where the respondent states additional facts, the Commission may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondent. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.

(6) Every person who intends to file objections or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the publication issued for the purpose (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) shall deliver to the Receiving Officer the statement of the objections or comments with copies of the documents and evidence in support thereof within the time fixed for the purpose.

(7) The Commission may permit such person or persons as it may consider to be appropriate to participate in the proceedings before the Commission, if on the report received from the Officer, the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the proceedings and the decision in the matter.

(8) Unless permitted by the Commission, the person filing objections or comments shall not be entitled to participate in the proceedings. However, the Commission shall take into account the objections and comments filed.

18. Hearing of the matter.—(1) The Commission may determine the stage, the manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter as it may consider to be appropriate, consistent with such specific timing requirements as are set forth in the Act or otherwise needed to expeditiously decide the matter.

(2) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

(3) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of affidavit, the Commission may, as and when the Commission considers it to be necessary, grant an opportunity to the other party to cross examine the deponent of the affidavit.

(4) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an officer or person designated for the purpose by the Commission.

(5) The Commission may direct the parties to file written note of arguments or submissions in any proceeding before the Commission as the Commission considers to be appropriate.

19. Power of the Commission to call for information etc.—(1) The Commission may, at any time before passing orders on any matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documentary or other material objects as evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.

(2) The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition any public record from any office, examination by an officer of the Commission the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant for the matter.

(3) The Commission may, if it considers appropriate, allow any of the parties or others specified in sub-regulations (1) or (2) to adduce such further documentary or other evidence in regard to evidence made available by any of the parties or other persons under the said sub-regulation.

(4) The Commission may, at any time, summon and enforce the attendance of any person and examine him on oath.

(5) The Commission may receive evidence by way of affidavit.

20. Reference of issues to others.—(1) At any stage of the proceedings, the Commission shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including, but not limited to, the officers and consultants of the Commission whom the Commission considers as qualified to give expert or specialized advice or opinion.

(2) The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.

(3) The Commission, if it thinks fit, may direct the parties to appear before the persons, designated in sub-regulation (1) or (2) to present their respective views on the issues or matters referred to.

(4) The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person designated by the Commission. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion.

(5) The Commission shall duly take into account the report or the opinion given by the person and the replies filed by the parties while deciding the matter and if considered necessary, examine the person giving the report or the opinion:

Provided that the Commission shall not be bound by the report or the opinion given and shall be entitled to take such decision as it may consider to be appropriate.

21. Procedure to be followed where any party does not appear.—(1) If, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, if any party or his authorized agent or representative does not appear when the matter is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the petition for default when the petitioner or the person who moves the Commission for hearing is absent or proceed *ex parte* to hear and decide the petition if the other party is absent.

(2) Where a petition is dismissed in default or decided *ex parte*, the person aggrieved may file an application within 30 days from the date of such dismissal or being proceeded *ex parte*, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission is satisfied that there was sufficient cause for the non-appearance of the person when the petition was called for hearing.

22. Orders of the Commission.—(1) The Commission shall pass orders on the petition and the Chairperson and the Members of the Commission, who heard the matter shall sign the orders.

(2) The order shall be dated and signed by the Commission at the time of pronouncing it. Such orders shall not be, afterwards, altered or added unless and except

there in the case of any clerical or mathematical errors arising there from any oversight or omission.

(3) The order shall contain a statement and counter statement of the facts in brief, the points or issues for determination, the decision thereon and the reason for such decision.

(4) The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting member, if any, shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with these regulations.

(5) The Commission shall have the powers to pass such interim orders or give directions in any proceeding, hearing or matter before the Commission, as it may consider it to be appropriate.

(6) All orders, directions and decisions issued or communicated by the Commission shall be certified by the signature of the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairperson and bear the official seal of the Commission.

(7) All final orders of the Commission shall be communicated to the parties in the proceeding under the signature of the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairperson or the Secretary.

23. Inspection of records and supply of certified copies.—(1) The records of every proceedings shall be open, as of right, to the inspection of the parties or their authorized representatives at any time either during the proceedings or after the orders are passed, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct.

(2) The records of every proceeding, except those parts which for reasons directed by the Commission to be confidential or privileged, shall be open to inspection by any person other than the parties to the petition either during the proceedings or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time including in regard to time, place and manner of inspection and payment of fees.

(3) The application for inspection of documents shall be in the Form CB-10 (Annexure-VIII) and shall be accompanied by the fee as specified in the Schedule to these regulations for each inspection for one day in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Shimla.

(4) The inspection of records shall be allowed on any working day ordinarily during 14.30 hours to 16.30 hours in the presence of an officer authorized for that purpose.

(5) The person inspecting the records shall not in any manner cause dislocation, mutilation, tampering or damage to records in the course of inspection.

(6) The officer supervising the inspection may at any time prohibit further inspection, if in his opinion, any of the records are likely to be damaged in the process of inspection and shall immediately, make a report about the matter to the Secretary and seek further orders on the matter.

(7) A register for inspection of records in the format as per Form CB-11 (Annexure-IX) shall be maintained.

24. Supply of certified copies of documents.—(1) Any person shall be entitled to obtain copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Commission as well as the pleadings, papers and other parts of the records of the Commission to which he is entitled to inspect on payment of fee and complying with other terms which the Commission may direct.

(2) Every order granting, refusing or modifying interim relief and final order shall be communicated to the parties to the petition free of cost:

Provided that unless ordered otherwise by the Commission, a copy of the final order, may not be sent to any party who has not entered appearance.

(3) Any person desirous of obtaining a certified copy of any order of the Commission or any document forming part of the record of proceedings before the Commission, may submit an application in the prescribed Form CB-12 (Annexure-X).

(4) A Register of Copy Applications shall be maintained in the form as prescribed in Form CB-13 (Annexure-XI).

(5) As far as practicable, the certified copies shall be prepared in the order in which the applications are entered in Register of Copy Applications.

(6) The certified copies shall be prepared by photocopying process or by typing and when the copy is so made, it shall be compared by the person preparing the copy, to

satisfy himself that the copy prepared faithfully and legibly reproduces the document desired.

(7) An endorsement as under shall be affixed on the reverse of the last page of the document:—

- (a) Sl. No. of the application;
- (b) Name of the applicant;
- (c) Date of presentation of the application;
- (d) No. of pages;
- (e) Copying fee charged;
- (f) Date on which copy is ready;
- (g) Date of delivery.

(8) The endorsement shall be made with the help of a rubber stamp got prepared for the purpose. The entries shall be made in ink.

(9) The copying fee payable for obtaining a certified copy shall be as specified in the Schedule to these regulations per page irrespective of number of words/lines in each page.

CHAPTER -III

INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION AND ENFORCEMENT OF ORDERS ETC.

25. Collection of Information.—(1) The Commission may make such order or orders as it thinks fit in terms of the provisions of the Act for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following,—

- (a) the Commission may specially authorize any officer, not below the rank of a Gazetted Officer, on behalf of the Commission, to enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry or adjudication under the Act, may be found and may seize any such document or take extracts or copies therefrom;
- (b) in the exercise of powers conferred on it by section 128 of the Act, the Commission may, on being satisfied that a licensee or a generating company has failed to comply with any of the conditions of the licence or the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder, at any time, by order in writing, direct an Investigating Authority specified in the order to investigate the affairs of the licensee or generating company and report to the Commission. For this, the Commission may direct the minimum information to be maintained by the licensees and generating companies in their books and also direct the manner in which such information shall be maintained and the checks and verifications to be adopted;
- (c) the Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or Consultants or any other person as the Commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission;
- (d) the Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and direct the time within which the report is to be submitted or information furnished;
- (e) the Commission may issue or authorize the Secretary or an officer on its behalf to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an officer of the Commission specified in this behalf the books of accounts as provided in the Act to furnish information to the specified officer;
- (f) the Commission may, for the purpose of collecting any information particulars or documents which the Commission considers necessary in connection with the discharge of its functions, issue such directions and

follow any one or more of the methods provided for in the Act as the Commission considers it to be appropriate;

- (g) if any such report or information obtained as specified in the Act or in these regulations appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an officer authorized for the purpose may give directions for inquiry, report and furnishing of information;
- (h) the Commission may direct that such incidental, consequential and supplemental matters which may be considered relevant in connection with the above, be attended to;

(2) In the discharge of the functions and powers under the Act and the regulations, the Commission may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter-II of these regulations.

(3) On receipt of the report from the appointed Investigating Authority, and after giving an opportunity to the licensee or generating company, as the case may be, to make a representation in connection with the report, the Commission may make an order to require the licensee or the generating company to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Commission may think fit.

(4) The Commission may, after giving reasonable notice to the licensee or the generating company, as the case may be, publish the report submitted by the Investigating Authority or such portion(s) thereof as may appear to the Commission to be necessary.

26. Assistance of experts.—(1) The Commission may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts, engineers, chartered accountants, advocates, surveyors and such other technical and professional persons, as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.

(2) If the report or information obtained in terms of the regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission in forming its opinion or view in any proceedings, the parties in the proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report or information.

(3) The Commission may, if it considers necessary, direct payment to the institution, consultant, expert, engineer, chartered accountant, advocate, surveyor and other technical and professional person, engaged under sub-regulation (1), of such fees, costs, expenses by such of the parties to the proceedings as the Commission may consider appropriate.

CHAPTER- IV

LICENCE

27. Application for licence.—(1) Any person intending to engage in the business of transmission, distribution or trading in electricity in the State of Himachal Pradesh, shall apply to the Commission for the grant of appropriate license in the form and manner directed by the Commission and accompanied by such fees as may be prescribed for this purpose.

(2) The distribution licence to be issued by the Commission shall broadly be of two categories, namely:—

- (a) Category I – Licence where the distribution licensee will apply for and obtain from the Commission a licence;
- (b) Category II – Licence, where the person is deemed to have applied for and been granted a distribution licence by the Commission under regulation 48 herein by virtue of the having complied with conditions contained in these regulations.

(3) The Commission may, if considers appropriate, advertise in newspapers or otherwise notify in such other appropriate manner as the Commission may decide, inviting applications for grant of licence.

(4) The applications for licence shall be made in accordance with the provision of the Act and these regulations and in the applicable form contained in Form CB-14-15 and 16 (in Annexure XII to XIV) to these regulations and shall be supported by affidavit of the authorised person.

(5) Every application for a licence shall be signed by or on behalf of the applicant and addressed to such officer as the Commission may designate in this behalf and it shall be accompanied by—

- (a) ten copies or such number of copies as the Commission may direct of the proforma containing the specific terms and conditions which the applicant desires to be included in the licence and the statement stating the exclusion desired of the general conditions specified by the Commission and justification thereof, with the name and address of the applicant and of his agent (if any) printed on the cover page of the proforma;

- (b) ten copies or such number of copies as the Commission may direct each signed by the applicant, of maps of the proposed area of transmission or distribution on such scale as may be laid down by the Commission;
- (c) a statement describing any lands or assets, which the applicant proposes to acquire for the purpose of the licence and the means of such acquisition;
- (d) a copy of the business plan, with an approximate statements of the capital proposed to be expended in connection with the utility, the means of financing of such capital expenditure, the resultant efficiency improvements and such other particulars as the Commission may require;
- (e) a copy of Memorandum and Articles of Association in the case of a company or the incorporation or registration documents in the case of other legal entities;
- (f) annual accounts or other similar documents as may be required; and
- (g) a receipt in acknowledgement of payment of the fee specified in that regard.

(6) Any person intending to act as the transmission licensee shall, immediately on making the application, forward a copy of such application to the State Transmission Utility. The State Transmission Utility shall acknowledge the receipt of the application and within thirty days of the receipt of the said application send its recommendations, if any, to the Commission.

28. Contents of proforma.—The proforma referred to in regulation 27 shall contain the particulars contained in the application form in Form CB-14-15-16 (Annexure XII, XIII and XIV) and specifically the following:—

- (a) a short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant, and if the applicant is a company, the names of all the directors of the company;
- (b) type of licence applied for;
- (c) location of the proposed area of operation;
- (d) the general conditions and also the specific conditions, if any, which the Commission has laid down for inclusion in the licences of the nature applied with justification for any deviation sought for; and
- (e) such other particulars as the Commission may direct.

29. Conditions of licence.—(1) The general conditions subject to which each of the categories of licence shall be issued are contained in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution Licence) Regulations, 2004; or in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Transmission Licence) Regulations, 2004 or in the Himachal Pradesh Electricity

Regulatory Commission (General Conditions of Trading Licence) Regulations, 2004 and the application for licence shall incorporate the acceptance of such general conditions.

(2) The Commission may decide on the special conditions subject to which licence shall be issued to the applicant.

(3) Any person applying for licence to undertake trading in electricity in the State of Himachal Pradesh shall duly fulfill the conditions of technical requirement, capital adequacy requirement and credit worthiness and further shall agree to discharge such duties as may be specified by the Commission under section 52 of the Act.

(4) Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

30. Acknowledgement of application.—On receipt of the application, the receiving officer shall note thereon the date of its receipt and shall send to the applicant an acknowledgement stating the date of receipt.

31. Copies of maps and proforma for public inspection.—The applicant shall maintain at his own office and at such other place as may be designated by the Commission the copies of the documents referred to in sub-regulation (5) of regulation 27 for public inspection and furnish to persons applying for them the copies of such documents at a price not exceeding the normal photocopying charges.

32. Calling for additional information.—The Commission or the Secretary or any officer designated for the purpose by the Commission may upon scrutiny of the application, require the applicant to furnish within a period to be specified, such additional information or particulars or documents as the Commission may consider to be necessary for the purpose of dealing with the application.

33. Notifying the due filing of the application.—If the Commission finds the application to be complete and accompanied by the requisite information, particulars and documents and the applicant has complied with all the requirements for making the application and furnishing of information, particulars and documents, the Commission or the Secretary or the officer designated of the purpose shall certify that the application is ready for being considered for grant of licence in accordance with applicable laws and communicate the same to the applicant.

34. Publication of notice of application.—(1) The applicant shall, within seven days from the date of admission and numbering of the application, publish a notice of the

application in the form specified in Form CB-17 (Annexure-XV) with such particulars and in such manner as the Commission may direct.

(2) The publication shall be headed by a short title corresponding to that given in the application and shall give the addresses of the offices at which the documents copies of maps therein referred to may be inspected and the copies of documents be purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by a letter addressed to such officer as the Commission may designate in this behalf, within thirty days from the date of publication.

35. Service of notice of the application.—(1) The Commission may direct that notice of the application be served on the Central Government, the State Government, the local authority or any other authority or person or body as the Commission may direct in such form with such particulars and in such manner as the Commission may consider appropriate.

(2) The applicant shall apply for and obtain the no objection certificate required from the Central Government in terms of clause (ii) of sub-section (2) of section 15 of the Act before the application is placed for hearing by the Commission for grant of the licence.

36. Objections.—(1) Any person intending to object to the grant of the licence shall file objection within thirty days from the date of publication of the notice by the applicant. The objection shall be filed in the form of reply and the provisions of this Chapter II dealing with reply shall apply to the filing of such objections.

(2) Any person who desires to have any amendment made in proposed conditions of licence shall deliver a statement of the amendment to the applicant and to such officer as the Commission may designate in this behalf and within the time allowed by the Commission for filing objection.

37. Hearings and local inquiries.—(1) If the applicant has duly arranged for the publication of the notice of the intended application and the time for filing of the objection is over and after the applicant has furnished to the Commission the no objection certificate, if any, required from the Central Government, the Commission may proceed with the hearing of the application.

(2) The Commission shall give the notice of hearing to the applicant, the persons who had filed objections, the Central Government, the State Government, the local

authority and such other authority, person or body as the Commission may consider appropriate.

(3) The Commission shall consider the recommendations, if any, from the State Transmission Utility in regard to the grant of licence.

(4) If any person objects to the grant of a licence applied for, the Commission may if either the applicant or the objector so desires, cause a local inquiry to be held of which the notice in writing shall be given to both the applicant and the objector.

(5) In case of such local inquiry a memorandum of the results of the inquiry made shall be prepared and shall be signed by the applicant, the officer or person designated for the purpose and such other person as the Commission may direct.

(6) The hearing on the application for grant of licence shall thereafter proceed as far as possible in the same manner as provided in Chapter-II.

38. Grant of licence.—(1) After inquiry, if any, and the hearing, the Commission may decide to grant or refuse the licence and if it decides to grant the licence it may do so on such terms and conditions and with such modifications to the general or specific conditions as the Commission may decide.

(2) When the Commission has approved the grant of licence, the Secretary or such other officer as the Commission may designate in this behalf, shall inform the applicant of such approval and of the form in which it is proposed to grant the licence and the conditions to be satisfied by the applicant including the initial and periodical licence fees to be paid by the applicant for the grant of the licence.

(3) The Commission may publish a notice in two daily newspapers, as the Commission may consider necessary, stating the name and address of the person to whom it proposes to issue the licence.

(4) On receiving an intimation in writing from the applicant that he is willing to accept a licence in the form approved by the Commission and after the applicant satisfies the conditions imposed for the grant of the licence, the Commission may direct the applicant to publish the licence or such part or gist thereof as the Commission considers it to be appropriate.

(5) The Commission shall immediately after issue of a licence, forward a copy of the licence to the State Government, the Central Electricity Authority, Local Authority and to such other persons as the Commission considers necessary.

39. Date of commencement of licence.—The licence shall commence from the date the Commission may direct as the date of commencement of licence, and the licence shall be in force for the period specified in the licence, subject however to earlier revocation in accordance with law.

40. Deposit of maps.—(1) When a licence has been granted, three sets of maps showing, as regards such licence, the particulars specified in regulation 28 of these regulations shall be signed and dated to correspond with the date of the notification of the grant of the licence by such officers as the Commission may designate in this behalf.

(2) One set of such maps shall be retained as the deposited maps by the said officer and the other two sets shall be given to the licensee after due attestation by the Commission.

(3) The licensee shall, whenever required by Commission, furnish the maps in an electronic form.

41. Deposit of licence copies.—(1) Every person, who is granted a licence, shall within thirty days of the grant thereof,—

- (a) have adequate number of copies of the licence printed;
- (b) have adequate number of maps prepared showing the area of supply specified in the licence; and
- (c) arrange to exhibit a copy each of such licence and maps for public inspection at all reasonable times at his head office and at his local offices (if any) within the area of supply.

(2) Every such licensee shall, within the aforesaid period of thirty days, supply free of charge one copy of the licence (to every local authority) within the area of supply and shall also make necessary arrangements for the sale of printed copies of the licence to all persons applying for the same during the period of the licence, at a price not exceeding normal photocopying charges.

42. Preparation and submission of accounts.—(1) Every licensee shall cause the accounts of his utility to be made up to the 31st day of March each year.

(2) Such licensee shall prepare and render an annual statement of his accounts in accordance with the directions given by the Commission, within a period of six months from the aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the licensee. The statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission may direct.

(3) The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. The forms shall be signed by the licensee or the duly authorized agent or manager of the licensee.

(4) The Commission may, by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts under sub-regulation (3), the licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose.

43. Conditions of electricity supply.—(1) The distribution licensee shall comply with the electricity supply code and conditions of supply as the Commission may specify from time to time.

(2) The distribution licensee shall within six months from the grant of the licence, and in the case of deemed licensee under section 14 of the Act from the commencement of these regulations, file with the Commission the modifications to the existing conditions of supply and on the approval being granted by the Commission the conditions of supply with such modifications approved by the Commission, shall apply to the distribution licensee.

(3) Until the Commission approves the conditions of supply under sub-regulation (2), the distribution licensee shall follow the existing conditions of supply with such specific modification as the Commission may direct.

(4) The distribution licensee shall always keep in his office adequate number of copies of the updated electricity supply code and conditions of supply and he shall, on demand, sell such copies to any applicant at a price not exceeding normal photocopying charges.

44. Contravention by licensee.—The Commission may pass such orders as it thinks fit in accordance with the provisions of the Act and these regulations for the contravention or the likely contravention of the terms and conditions of licence by the licensee.

45. Suspension of licence .—(1) Subject to the provisions of section 24 of the Act and the regulations framed thereunder, where the circumstances exist which render it necessary for it in the public interest, the Commission may suspend, for a period not exceeding one year, the distribution licence, if in the opinion of the Commission the distribution licensee—

- (a) persistently fails to maintain uninterrupted supply of electricity conforming to the standards regarding quality of electricity to the consumers; or
- (b) is unable to discharge the functions or perform the duties imposed on it by or under the provisions of the Act;
- (c) persistently defaults in complying with the directions given by the Commission under the Act; or
- (d) breaches the terms and conditions of the licence.

(2) Before suspending a licence under sub-regulation (1), the Commission shall give the licensee not less than 3 month's notice, in writing, stating the grounds on which it is proposed to revoke the licence, and has considered any cause shown by the licensee within the period of that notice, against the proposed suspension.

(3) While suspending the licence under these regulations, the Commission shall appoint an Administrator to discharge the functions of the distribution licensee in accordance with the terms and conditions of the licence and on such appointment the utilities of the distribution licensee shall vest in the Administrator for a period not exceeding one year or upto the date on which such utility is sold in accordance with the provisions of section 20; or till the licence is revoked under section 19, or the suspension of the licence is revoked, whichever is earlier.

46. Revocation of the licence.—(1) The proceedings for revocation of the licence or for passing of any other orders specified in section 19 of the Act shall be initiated by an order passed by the Commission. The Commission may initiate such proceedings *suo motu* or on application of the licensee or on receiving any complaint or information from any person.

(2) The Commission shall give notice of the proceedings for the revocation of the licence to the licensee and to such other persons, authority or body as the Commission may consider necessary.

(3) Subject to the provisions of the Act, and the procedure contained therein, the inquiry by the Commission for revocation of the licence, in so far it is applicable, shall be in the same manner as provided in Chapter- II of these regulations :

Provided that the licensee shall be given not less than three months notice in writing to show cause against the proposed revocation and the notice to show cause issued to the licensee shall clearly state the grounds on which the Commission proposes to revoke the licence.

(4) If the Commission decides to revoke the licence, the Commission shall communicate the order of revocation to the licensee stating the effective date from which such revocation shall take effect.

(5) The Commission may instead of revoking the licence pass any other order imposing further terms and conditions subject to which the licensee is permitted to operate thereafter.

(6) Where the Commission has given notice for revocation of licence, the licensee may, after prior approval of the Commission, sell the undertakings of the licensee to any person who is found eligible by the Commission for grant of licence, without prejudice to any penalty which may be imposed or prosecution proceeding which may be initiated against the person whose license is revoked.

47. Amendment of the licence.—(1) The application for amendment to the terms and conditions of the licence may be made by the licensee in such form as may be directed for the purpose by the Commission. The application shall be accompanied with a statement of the proposed amendment and shall be supported by affidavit as provided in Chapter-II of these regulations.

(2) The application for amendment shall be accompanied by a receipt of such fee as the Commission may specify and paid in the manner directed by the Commission.

(3) The applicant shall, within seven days from the date of admission and numbering of the application for amendment, publish a notice of the amendment application filed giving a brief statement of the amendment proposed, the reason for the proposed amendment, the effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the licensee under the licence granted, the alternate arrangement proposed for such discharge of the functions and such other particulars as the Commission may direct. The publication shall give the addresses of the offices at which the application for amendment may be inspected and the copies of documents be purchased and shall

state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by a letter addressed to such officer as the Commission may designate in this behalf, within thirty days from the date of publication.

(4) In the event the Commission proposes to amend the terms and conditions of the licence granted to a licensee the Commission shall publish a notice of the proposed amendment giving a brief statement of the amendment proposed, the reason for the proposed amendment, the effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the licensee under the licence granted, the alternate arrangement proposed for such discharge of the functions and such other particulars as the Commission may consider appropriate.

(5) Unless otherwise specified in writing by the Commission, the procedure specified in these regulations for grant of licence, in so far it can be applied, shall be followed while dealing with an application for amendment of the licence.

48. Deemed grant of the distribution licence.—(1) Until otherwise directed by the Commission, the following classes of persons engaged in the supply of electricity in the State of Himachal Pradesh shall be deemed to have applied for and granted the distribution Category-II Licence for the purpose contained herein and subject to the fulfillment of the conditions contained in sub-regulation (2)—

- (a) persons who supply electricity generated by themselves and/or supplied to them by an authorized person, for the purposes of an event or function not exceeding two months, and when the electricity is distributed through a system owned by them;
- (b) persons who supply electricity to the residential colonies as a part of their activity of maintaining such colonies for use and occupation of their employees and/or for use and occupation of persons providing facilities and services to the employees, where such person procures electricity from any licensee or from any other source approved by the Commission and distributes the electricity within the residential colonies on no-profit motive basis;
- (c) such other persons as the Commission may from time to time by order notify, subject to such terms and conditions as the Commission may direct.

(2) The licensee under sub-regulation (1) shall—

- (a) not directly or indirectly undertake trading in electricity or distribution or supply of electricity outside its area of operation and the distribution or supply

of electricity shall be strictly restricted to the purpose mentioned in sub-regulation (1);

- (b) establish the electric line or works only within the area of operation;
- (c) if so required furnish to the Commission such information required for the purposes of the discharge of the functions of the Commissions as the Commission may from time to time direct;
- (d) comply with the provisions of the Act, the regulations of the Commission, technical codes such as grid code, supply code, standards of performance and overall standards of performance or any other guidelines issued by the Commission;
- (e) comply with any directions which the Commission may issue from time to time in regard to the charges which such persons may levy on the consumers taking into account the charges prevailing in the nearly area of supply of electricity supplied by a licensee.

(3) The Commission shall be entitled to issue appropriate directions from time to time as it may consider to be necessary and take appropriate action against a licensee under these regulations in accordance with the provisions of the Act and these regulations for any breach or non-compliance thereof.

(4) The Commission may, at any stage, if it considers to be necessary, direct the licensee under this regulation to apply for Category -I Licence and consider the grant or refusal of licence and may by an interim or final order direct such licensee to cease to distribute or supply electricity in the area of operation or any part thereof.

(5) If any difference or dispute arises as to whether the person is entitled to undertake supply of electricity as a licensee under this regulation, the decision thereon of the Commission shall be final.

CHAPTER –V

GENERATING COMPANIES AND CAPTIVE GENERATING STATIONS

49. Generating companies and captive generating stations.—The generating companies and other persons who have established generating stations including captive generating stations in the State and the persons who desire to establish such generating stations including captive generating stations shall furnish to the Commission the technical details of the generating stations as per Form CB-18 Annexure-XVI within 30 days of notification of these regulations or within 30 days of the commencement of generation of electricity at the station, whichever is later:

Provided that the Captive Generating Stations of Low Tension Consumers of Categories I and II shall not be required to furnish the aforesaid details to the Commission, unless otherwise specifically directed by the Commission.

CHAPTER -VI

POWER PROCUREMENT AND PURCHASE

50. Power procurement and purchase.—(1) In accordance with the provisions of the Act and the licence conditions every distribution licensee shall purchase or procure electricity required for the business of the distribution licensee in an economical and efficient manner and under a transparent power purchase and procurement process and generally based on the principles of least cost purchase.

(2) The power purchase by a distribution licensee may be classified by the Commission as short-term power purchase or long term power purchase on terms as may be decided by the Commission from time to time.

(3) The Commission may from time to time issue guidelines, practice directions and orders governing the short term purchases and long term purchases which the distribution licensee can undertake for the purpose of the licensed business.

(4) (a) The distribution licensee shall satisfy the Commission that the need for additional power procurement is on account of events beyond the reasonable control of the licensee on a long term basis and in the case of short term power purchase, the circumstances where such additional short term power purchase will become necessary.

(b) The distribution licensee shall not enter into a binding or enforceable contractual commitment till the Commission by a general or special order approves the procurement of electricity by the distribution licensee.

(5) Unless otherwise approved by the Commission by a general or special order, a long term power purchase or procurement by the distribution licensee shall be done through a structured competitive procurement process approved by the Commission.

(6) (a) The distribution licensee shall satisfy the Commission that the electricity procured under long term power purchase otherwise than through a competitive bidding process or any short term power purchase is of least cost or economical in the prevalent circumstances and that the distribution licensee has made prudent and best efforts to minimize the cost of purchase.

(b) The Commission may not permit any such short term or long term purchase if the manner or method proposed for such procurement of electricity is not conducive to the objective of least cost purchase or for any other reasons, the purchase is not economical or efficient.

(7) The short term power purchase by the distribution licensee may be undertaken in such a manner as the Commission may from time to time direct by a general or special order.

(8) The distribution licensee shall forecast the demand for electricity for his business and formulate proposals in coordination with the generating companies, licensee companies, other licensee, authorities and other concerned persons. The distribution licensee shall file with the Commission power procurement plan to meet the demand in such a manner as the Commission may direct.

(9) The distribution licensee shall file, with the Commission, the details in regard to the distribution system under his control and arrangement available for the transmission in the State or outside the State to evacuate the electricity procured and to distribute the same in accordance with the power procurement plans approved by the Commission.

(10) The details required to be given by the distribution licensee in regard to resource planning, power purchase and procurement planning, planning for transmission system and distribution system, competitive procurement process as well as other matters relating to purchase of energy by the licensee shall be as provided in the guidelines and practice directions that may be issued by the Commission from time to time.

(11) The Commission shall take into consideration, while determining the tariffs of the distribution licensees as per this regulation and as per the Tariff Regulations framed by the Commission under section 61 of the Act, the approval granted by the Commission to the distribution licensees for the power purchase and procurement process under this regulation and the action and inaction on the part of the distribution licensees in complying with the terms contained in this regulation.

CHAPTER - VII

INVESTMENT APPROVALS

51. Investment approvals.—(1) Unless otherwise specified by the Commission, every licensee shall obtain prior approval of the Commission for making investment in the licensed business if such investment is above the limits laid down by the Commission in the licence conditions.

(2) The limits in the licence conditions may be modified by the Commission from time to time by a general or special order.

(3) In the application for investment approval, the licensee shall furnish the following information or particulars:—

- (a) a detailed project report containing examination of an economic, technical system and environmental aspects of the investment together with the outline of the works to be undertaken, the salient features and particulars demonstrating the need for investment;
- (b) the project cost together with the cost benefit analysis;
- (c) whether the investment is in a new project or for expansion or up-gradation of an existing system;
- (d) sanctions and statutory clearances required for execution of the project and status of such sanctions and statutory clearances;
- (e) phasing of investment over the financial years and commissioning schedule;
- (f) the manner and the timeframe in which investments will be capitalized for the purposes of inclusion in the revenue requirement of the licensee;
- (g) constraints which the licensee may face in making the investments or in implementing the project including constraints on the information available;
- (h) resource mobilization and financial plans for meeting the investment; and
- (i) such other particulars as the Commission may from time to time direct.

(4) (a) The Commission may at its discretion hold such inquiries and consultations as the Commission may consider appropriate while dealing with the application for approval of the investment to be made by the licensee.

(b) The Commission may, at its discretion, initiate a proceeding or consider the application for investment approval as a part of the proceedings for determination of tariff or alongwith any other proceedings as the Commission may consider appropriate.

(5) (a) The Commission shall be entitled to appoint consultants, investigators, experts and others as the Commission may consider appropriate and authorize the Commission's staff, consultants, investigators and experts to hold discussions and deliberations with the licensees before the Commission considers the application for investment approval.

(b) The cost of consultancies, investigations and reports as per this sub-regulation shall be borne by the licensee.

(6) (a) The licensee and other applicants seeking investment approval shall furnish information, particulars and documents as may be required by the Commission staff, consultants, investigators and experts appointed by the Commission for the purpose and allow them access to the records and documents in the power, possession or custody of the licensee.

(b) The licensee shall cooperate with the Commission's staff, consultants, investigators and experts to enable them to discharge their functions and to submit a report to the Commission on the outcome of their findings.

(7) The Commission shall take into consideration, while determining the tariffs of the licensees as per this regulation and as per the Tariff Regulations framed by the Commission under section 61 of the Act, the approval granted by the Commission to the licensees for the investments under this regulation and the action and inaction on the part of the licensees in complying with the terms contained in this regulation.

CHAPTER –VIII

PERFORMANCE STANDARDS, SUPPLY CODES REGULATIONS ETC.

52. Performance standards, supply codes, regulations etc.—(1) The Commission may from time to time direct the licensees and generating companies operating in the State to formulate or adopt such codes as the Commission considers appropriate for the proper, efficient, economical and competitive conduct of the electricity sector and operation of the power systems in the State.

(2) The Commission may hold such consultations and proceedings, as the Commission considers appropriate to deliberate on the codes formulated by the licensee.

(3) (a) The Commission may appoint consultants or experts to advise the Commission on the codes formulated by the licensees and generating companies.

(b) The cost of consultancies and reports as per this sub-regulation shall be borne by the appropriate licensee.

(4) The Commission may direct such modifications, as it considers appropriate to the codes formulated by the licensees and generating companies.

(5) The licensees and generating companies shall implement codes approved by the Commission consistent with the directions and orders made by the Commission from time to time.

(6) Without prejudice to the generality of the powers of the Commission in regard to the enforcement of standards of performance in operation of the power system, the codes to be formulated and implemented may include,—

- (a) grid code;
- (b) distribution code;
- (c) electricity supply code and conditions of supply;
- (d) consumer related codes including code of practice on payment of bills, code on disconnection for non-payment, standards and quality of service and fines and penalties for failure, consumer rights and consumer complaint handling procedures;
- (e) safety and security codes;

- (f) transmission system planning and security standards;
- (g) distribution system planning and security standards;
- (h) operating standards; and
- (i) codes on utilization of electricity and demand side management.

(7) The licensees and generating companies shall follow the existing standards codes and conditions of supply till the codes, standards and conditions of supply as per sub-regulation (6) are formulated and implemented in accordance with this regulation.

CHAPTER - IX

ARBITRATION OF DISPUTES

53. Arbitration.—(1) The arbitration of disputes which under the Act are within the scope of the jurisdiction of the Commission may be commenced on an application accompanied by fees specified in the Schedule made by any of the parties to the dispute.

(2) The Commission shall issue notice to the concerned parties to show cause as to why the disputes between the parties should not be adjudicated and settled through arbitration.

(3) The Commission may, after hearing the parties to whom notices have been issued and if satisfied that no reason or cause has been shown against the arbitration request, pass an order directing that the disputes be referred for adjudication and settlement through arbitration either by the Commission or by a person or persons to be nominated by the Commission.

54. Nomination of arbitrators.—(1) If the Commission decides to refer the matter to arbitration by a person or persons other than the Commission, the reference shall be—

- (a) to a sole arbitrator if the parties to the dispute agree on the name of the sole arbitrator;
- (b) if the parties are unable to agree on the name of the arbitrator, to a sole arbitrator to be designated by the Commission or to three persons as the Commission may direct taking into account the nature of the dispute and the value involved and, if the decision is to refer to three arbitrators, one to be nominated by each of the parties to the dispute and the third by the Commission:

Provided that if any of the parties fails to nominate the arbitrator or if any arbitrator, nominated by the parties or the Commission, fails or neglects to act or continue as arbitrator, the Commission shall be entitled to nominate any other person in his place.

(2) The Commission shall not nominate a person as arbitrator to whom any of the parties to the arbitration has a reasonable objection on grounds of possible bias or similar such reasons and the Commission considers the apprehension to be justified.

55. Procedure for adjudication, settlement and passing of award.—(1) In case the Commission acts as the arbitrator, the procedure to be followed shall be as far as

possible the same as in the case of hearing before the Commission provided in Chapter-II.

(2) In case the Commission nominates an arbitrator or arbitrators to adjudicate and settle the disputes, such arbitrator or arbitrators may follow such procedure as they may consider appropriate, consistent with the principles of natural justice and fair opportunity to be given to the parties to arbitration and shall follow specific directions issued by the Commission.

(3) The arbitrator shall, after hearing the parties pass an award giving reasons for the decision on all issues arising for adjudication and forward the award with relevant documents to the Commission within such time as the Commission may direct.

(4) The award made by the Commission or the arbitrators, as the case may be, shall be an award under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

56. Cost of arbitration and proceedings.—The cost of the arbitration and proceedings before the Commission shall be borne by such parties and in such sums as the Commission may direct.

CHAPTER -X

APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF INDIAN PENAL CODE AND
CRIMINAL PROCEDURE CODE

57. Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code.—(1) In terms of section 95 of the Act, the proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings and Commission shall be deemed to be a civil court as specified in the said section read with applicable provisions of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)

(2) The extracts of the relevant provisions of the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code are contained in Annexure-XVII to this regulation.

CHAPTER-XI

FEES AND FINES

58. Fees.—(1) Every petition, application or grievance made to the Commission shall be made alongwith payment of the appropriate fees specified in the Schedule to these regulations. However, every application made for the grant of a licence, under section 14 of the Act shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the State Government under section 15 of the Act.

(2) Every licensee shall pay the Annual Licence fee as specified in these regulations.

(3) The fee payable to the Commission as prescribed under these regulations shall be paid by means of Bank draft or Banker's cheque, drawn in favour of the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, payable at Shimla. For amounts not exceeding Rs. 1000/- the Commission may accept cash payments.

(4) The Commission may, by order, waive the amounts of fees payable provided in these Regulations.

(5) The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such Bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time and shall be entered in the register prescribed in Chapter-II of these regulations for the purpose in the Form-CB-4 (Annexure-III).

(6) Unless there is anything repugnant in the rules framed by the State Govt. under sub-section (3) of section 103, the Commission shall whenever it considers necessary, utilise the fees deposited in the Bank account under sub-regulation (5) for meeting the expenses of the State Commission under the Act.

59. Categories of applications/petitions.—The applications/petitions presented before the Commission shall be categorised as follows:—

- (1) applications for grant of licence/grant of exemption from licence;
- (2) applications for determination of tariff;
- (3) Petitions for approval of Power Purchase and Procurement Processes;
- (4) applications/petitions for review of Commission's orders;
- (5) other applications/petitions.

60. Fees payable to State Load Dispatch Centre.—The fees payable to State Load Dispatch Centre by the generating companies and licensees engaged in intra-State Transmission of electricity under section 32(3) of the Act shall be as specified by the Commission.

61. Fees payable for appeal petition under section 127 (1) of the Act.— Fees payable in respect of an appeal petition against the orders of the Assessing Officer under sub-section (1) of section 127 of the Act shall be as specified by the Commission.

62. Fines and charges for non-compliance or violation.—(1) Subject to the provisions of the Act, the Commission may initiate a proceeding for imposition of fines and/or charges in the event of non-compliance of orders or directions given under the Act as provided in section 142 and 146 of the Act for any contravention of any directions issued by the Commission under the Act or rules or regulations made thereunder.

(2) The provisions of Chapter II, applicable to the proceedings, shall apply mutatis mutandis to a proceeding for imposition of fines and/or charges.

(3) While determining the quantum or extent of the fines and/or charges to be imposed, the Commission shall consider, amongst other relevant things, the following:—

- (a) the nature and extent of non-compliance or violation;
- (b) the amount of wrongful gain or unfair advantage derived or contra loss or disadvantage caused to any person(s), including Commission, as a result of the non-compliance or violation;
- (c) the amount of loss or degree of harassment caused to any person(s), including the Commission, or harmful effect on the efficient, economical and competitive performance of the electricity industry as a result of the non-compliance or violation; and
- (d) the nature and extent of harm or impairment caused to the objects and purposes of the Act as a result of non-compliance or violation;
- (e) motive for non-compliance or violation; and
- (f) the repetitive nature of the non-compliance or violation.

(4) The fines or charges imposed by the Commission shall be paid, unless otherwise specified by the Commission, within 30 days of the date of the order of the Commission imposing the fines or charges.

(5) The fines and charges shall be payable and the amount deposited in the same manner as specified in Regulation 58.

(6) If the fines or charges imposed by the Commission are not paid within 30 days as per sub-regulation (4), the same shall be recoverable as arrears of land revenue.

CHAPTER-XII

MISCELLANEOUS

63. Review of the decision, directions and order.—(1) Any person aggrieved by a direction, decision or order of the Commission, from which —

- (a) no appeal has been preferred; or
- (b) from which no appeal is allowed,

may, upon the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the direction, decision or order was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, or for any other sufficient reasons desires to obtain a review of the directions, decision or order made against him, may apply for a review of such direction, decision or order, as the case may be, to the Commission.

(2) An application for such review shall be filed in the same manner as a petition under these regulations.

(3) When it appears to the Commission that there is no sufficient ground for review, the Commission shall reject such review application.

(4) When the Commission is of the opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the decision or order, the review of which is applied for.

64. Continuance of proceedings after death etc.—(1) Where in any proceedings, any of the parties to the proceedings dies or is adjudicated as an insolvent or in the case of a company under liquidation/winding up, the proceedings shall continue with the successor-in-interest of the party concerned.

(2) The Commission may, for reasons to be recorded, treat the proceedings as abated in case the Commission so directs and dispense with the need to bring the successors-in-interest to come on record.

(3) In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record:

Provided that the Commission may, if it is satisfied that there is sufficient cause for not filing the application within the time allowed, condone the delay subject to such terms and conditions, as the Commission may consider appropriate.

(4) If the person fails to bring on record the successors-in-interest within the time allowed under sub-regulation (3) and in the event the application for condoning the delay in bringing on record the successor-in-interest is not condoned under the proviso to sub-regulation (3) the proceedings against the deceased person shall abate.

65. Proceedings to be open to public.—The proceedings before the Commission shall be open to the public subject to availability of sitting accommodation:

Provided that the Commission may, if it thinks fit, and for reasons to be recorded in writing, order at any stage of the proceedings of any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall not have access to or be or remain in, the court-room, building or premises used by the Commission for the purpose of conduct of the proceedings.

66. Publication of petition.—(1) Where any application, petition, or other matter is required to be published under the Act or these regulations or as per the directions of the Commission, it shall, unless the Commission otherwise orders or the Act or regulations otherwise provide, be advertised within such time as the Commission may direct and in the absence of any specific directions to the contrary, not less than 5 days before the date fixed for hearing and further unless otherwise directed by the Commission, such publication shall be done in two newspapers one in English language and one in Hindi language having circulation in the area concerned.

(2) Except as otherwise provided, such advertisement shall give a heading describing the subject matter in brief.

(3) Such advertisement to be published shall be approved by the officer of the Commission designated for the purpose:

Provided that the publication shall be made not less than seven days before the date fixed for hearing.

67. Confidentiality.—(1) The records of the Commission, except those parts, which for reasons specified by the Commission are confidential or privileged, shall be open to inspection by all, subject to the payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct.

(2) The Commission may, on such terms and conditions as it considers appropriate, provide for the supply of the certified copies of the documents and papers available with the Commission to any person.

(3) The Commission may, by order, direct that any information, documents and other papers and materials produced before it or any of its officers, consultants, representatives or otherwise which may otherwise come into their possession or custody, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of copies, and the Commission may also direct that such document, papers or materials shall not be used in any manner except as specifically authorized by the Commission.

68. Issue of orders and practice directions.—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed in various matters which the Commission has been empowered by these regulations to lay down.

69. Saving of inherent power of the Commission.—(1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.

(2) Nothing in these regulations shall bar the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient.

(3) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

70. General power to amend.—The Commission may, at any time amend any defect or error in any proceeding before it.

71. Power to remove difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

72. Power to dispense with the requirement of the Regulations.—The Commission shall have the power, for reasons to be recorded in writing and with notice to the affected parties, dispense with the requirements of any of the regulations in a specific case or cases subject to such terms and conditions as may be specified.

73. Extension or abridgement of time allowed.—Subject to the provisions of the Act, the time allowed by these regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by order of the Commission.

74. Effect of non-compliance.—The failure to comply with any requirement of these regulations shall not invalidate any proceeding merely by reasons of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

75. Costs.—(1) Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Commission, the cost of all proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.

(2) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as the decree/order of a civil court.

76. Enforcement of orders passed by the Commission.—The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned in accordance with the provisions of the Act and regulations and if necessary, may seek the orders of the Commission for directions. Failure to do so shall render him liable to proceedings as for non-compliance or violation of directions and orders of the Commission.

77. Repeal and Savings.—(1) The provisions of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2001, shall stand repealed with the coming into force of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any order or notice made or issued or any instrument executed or direction given under the repealed regulations shall be valid and shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.

By order of the Commission

Secretary.

Schedule

(see regulations 58 CBR

Fee Structure

Sl. No. 1	Nature of application/ petition 2	Statutory Provisions 3	Fees (in rupees) 4	Remarks 5
1	Annual licence fee:	CBR 58(2)		
	(i) Transmission licence	CBR 27 (1)	100 lakh per annum	
	(ii) Distribution licence	CBR 27 (1)	25 lakh per annum	
	(iii) Trading licence	CBR 27 (1)	25 lakh per annum	
2	Application for determination of tariff in respect of generating companies	EA 86 (1) (a) CBR 12, 13,14	25 lakh	
3	Application for determination of transmission tariff	EA 86 (1) (a) CBR 12, 13,14	5 lakh	
4	Application for determination of tariff for wholesale bulk, or retail supply of electricity	EA 86 (1) (a) CBR 12, 13,14	Paise 1 for every 10 kwh sent out in the distribution system	
5	Application for determination of tariff for wheeling of electricity	EA 86 (1) (a) CBR 12, 13,14	Rs. 1 lakh	
6	Application for approval of power purchase or procurement process	EA 86 (1) (b) CBR 50	15000 per MW or a part thereof to be shared equally between the contracting parties	
7	Petition for review of Commission's orders: Tariff order: (a) on the request of original tariff petitioner (b) on the request of Association/ group (c) on the request of individual consumer (ii) Power Purchase Agreement : (a) upto 5 MW (b) greater than 5 MW (c) others	CBR-63	 Rs.50,000/- Rs.25,000/- Rs.20,000/- Rs.10,000 Rs.50,000	

1	2	3	4	5
8	Inspection of judicial records of the Commission	CBR 23(3)	Rs. 200/- per day	
9	Supply of certified copies of documents/ judicial orders of the Commission	CBR 24(9)	Rs.5/- per page	
10	Applications for entertaining and adjudicating disputes and differences between the licensees and utilities and review petitions/applications in this regard	CBR 12	Rs. 10,000/-	
11	Interlocutory application by: (i) licensee (ii) others	CBR 12	Rs.5000/- Rs,1000/-	
12	Applications seeking adjournment	CBR 12	Rs.1000/-	
13	Applications seeking extension in time	CBR 12	Rs.1000/-	
14	Other applications/petitions not covered above seeking orders of the Commission	CBR 12	Rs.2000/-	
15	Other complaints/ applications / grievances against the working of the licensees, generating companies, etc. by the end-user/consumer—	CBR 52		
(i)	Consumer Association/group		Rs.1000/-	
(ii)	Individuals		Nil	

ANNEXURE-1

FORM CB-I

[See regulation – 7(2) (g)(i)CBR]

Register containing Electricity Acts enacted by the Central or State Government

[illegible]

FORM CB-2

[See regulation 7(2)(g)(ii) CBR]

**Register containing details of the statutory notifications, rules, orders & directions
and regulations framed under the Act**

**Part-I.—Statutory notification, rules, orders and directions issued by the Central
Government**

Sr. No.	Subject matter	Provisions under which issued	No. & date of notification	Details & date of the Official Gazette in which published	Whether Hindi text is available, if so, give the details of the Official Gazette in which published	Date of commence- ment	Effect on existing provision	How amended ,modified and repealed subsequent
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PART-II—STATUTORY NOTIFICATIONS, RULES, ORDERS, DIRECTIONS AND REGULATIONS FRAMED BY THE CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

Sr. No.	Subject matter	Provisions under which issued	No. and date of notification	Details and date of the Official Gazette in which published	Whether Hindi text is available, if so, give the details of the Official Gazette in which published	Date of commencement	Effect on existing provisions	How amended, modified and repealed subsequently
1	2	3	4	5	6		8	9

**PART-III—STATUTORY NOTIFICATIONS, RULES, ORDERS AND DIRECTIONS
ISSUED BY THE STATE GOVERNMENT**

Sl. No.	Subject matter	Provisions under which issued	No & date of notification	Details & date of the Official Gazette in which published	Whether Hindi text is available, if so, give the details of the Official Gazette, in which published	Date of commencement	Effect on existing provisions	How amended, modified and repealed subsequently
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[See regulation 7(2) (g) (iii) CBR]

Part-I Regulations.

[illegible]

[illegible]

ANNEXURE-III

FORM-CB-5

[See Regulation 13 CBR]

GENERAL HEADING FOR PROCEEDINGS**Before the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission,**

Filing No.

Case No.

(to be filled by the office)

IN THE MATTER OF:

(Gist of the purpose of the petition or application

And

IN THE MATTER OF:

(Names and full addresses of the petitioners/applicants and names and full addresses of the respondents).

ANNEXURE-IV

FORM-CB-6

[See Regulation 14(1) CBR]

**BEFORE THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION, SHIMLA**

FILE NO.:

CASE NO.

(To be filled by the Office)

IN THE MATTER OF : (Gist of the purpose of the petition or application)

AND

IN THE MATTER OF:

(Names and full addresses of the petitioner/applicants and names and full addresses of the respondents)

Affidavit verifying the petition/reply/application.

I, AB, son of aged residing at do solemnly affirm and say as follows:-

1. I am a Director/Secretary/ ofLtd., the petitioner in the above matter and am duly authorized by the said petitioner to make this affidavit on its behalf.

Note: This paragraph is to be included in cases where the petitioner is the Company.

2. The statements made in paragraphs of the petition herein now shown to me and marked with the letter 'A' are true to my knowledge and the statements made in paragraphs..... are based on information and I believe them to be true.

Verification:

I, the deponent above named do hereby verify that the contents of my above affidavit are true to my knowledge; no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at on the day of

Deponent.

ANNEXURE-V

FORM -CB-7

[See regulation 15 (3) CBR]

**MEMORANDUM OF APPEARANCE BEFORE THE HIMACHAL PRADESH
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA**

Petition No. _____

In the matter of:

----- Petitioners

Versus

----- Respondents

MEMORANDUM OF APPEARANCE

I _____ practising/working as _____
having been authorized by _____ (further the particulars of the
person authorizing) _____ hereby enter appearance on behalf of
the _____ and undertake to plead and act for him/ it in all
matters in the aforesaid case.

Place : _____

Signature and Designation

Date : _____

Address for correspondence

ANNEXURE-VII

FORM-CB-9

[See Regulations 15 (6) CBR]

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
SHIMLA -171002**

No. _____ 200

Subject:- Petition under section _____ of the Electricity Regulatory Commissions Act, 2003

- In the matter of

Dear Sir, .

I am directed to refer to your petition/application dated filed on on the above named subject and to inform you that on scrutiny, the following defects have been pointed:-

1. The petition is not in the form prescribed in Chapter-II of the HPER, Conduct of Business Regulations.
2. The names, descriptions and addresses of the parties have not been furnished in the clause title.
3. The following necessary parties have not been impleaded:
 - a)
 - b)
 - c)
4. The petition has not been duly signed.
5. The petition has not been verified through an affidavit.
6. The affidavit is not on the form prescribed in Chapter II of the HPERC CBR.
7. The affidavit has not been signed and sworn before the competent authority.
8. Ten copies of the petition have not been filed.
9. The copies of the petitions are not complete in all respects.
10. The copies of the documents are not legible and duly attested.
11. Translation in English/Hindi/any other language recognized by the Commission, has not filed.
12. Authenticity of the translation of the documents in English/Hindi/any other language recognized by the Commission, has not been furnished.
13. The Vakalatnama/letter of authorization has not been filed.

14. The Vakalatnama is not properly executed and necessary court fee has not been paid.
15. The prescribed fee for the petition/application has not been paid.
16. The index of documents has not been filed.
17. The pagination of the documents has not been done properly.

You are requested to rectify the defects within three weeks of issue of this letter failing which the petition shall be deemed to have been rejected.

Yours faithfully,

Secretary.

ANNEXURE-VIII

FORM-CB-10

[See regulations 23 (3) CBR]

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
SHIMLA-171002**

Petition No.

..... Petitioner

V/s

..... Respondent(s)

Application for inspection of documents/records

I hereby apply for grant of permission to inspect the documents/records in the above case.
The details are as under:—

1. Name and address of the person seeking permission
2. Whether he is party to the case or he is the authorised representative of any party? (Furnish necessary particulars):
3. Details of papers/documents sought to be inspected
4. Purpose for seeking inspection
5. Date and duration of the inspection sought
6. The amount of fee payable and the mode of payment

Place:

Date:

Signature

Office use

Granted inspection on/Rejected

Secretary.

ANNEXURE-IX

FORM-CB-11

[See Regulations 23 (7) CBR]

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
SHIMLA -171002**

REGISTER FOR INSPECTION OF RECORDS

[illegible]

ANNEXURE -X

FORM-CB-12

[See regulation 24 (3) CBR]

**HIMACHAL PRADESHH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA -171002**

Petition No.

..... Petitioner

V/s

..... Respondent(s)

Application for grant of certified copy

1. Name and address of Applicant
2. Whether the applicant is party to the case
3. Whether the case is pending or disposed of
4. Description with date of the documents of which copy is applied for
5. No. of copies required
6. Amount of fee remitted and mode of payment

Signature

For office use

Granted/Rejected
Additional copying fee
Payable/paid and details thereof

Secretary.

ANNEXURE-XI

FORM-CB-13

[See Regulation 24 (4) CBR]

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
SHIMLA -171002**

REGISTER OF COPY APPLICATIONS

[illegible]

ANNEXURE-XII

FORM-CB-14

[See regulations 27 (4) and 28(1) CBR]

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FORM-1: Application Form for grant of a distribution licence in the State of Himachal Pradesh.

The applicant must submit the completed application in xxx copies to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, (address), alongwith application fee of Rs. xxxx (Rupees in words) in form of a DD drawn in favour of Secretary Electricity Regulatory Commission, payable at Shimla.

PART-A: GENERAL INFORMATION OF APPLICANT**1. Details of Applicant**

(a) Full name of the applicant :

(b) Full address of the applicant :

(c) Name, designation and address of the Contact Person :

(d) Contact Telephone Numbers :

Fax Number(s) :

Email ID :

2. Nature and details of ownership:

(a) Company/Firm/Co-op Society/Individual/Others :

(b) When and where Company Incorporation/Registration

Place of Incorporation/Registration :

Year of Incorporation :

Registration Number :

Place of Registration of the firm, co-op society :

- (c) Name and addresses of Directors/partners/governing body members/trustees

3. Principal Shareholders/Partners/Members

4. Details of the area of distribution, of the area of supply and of the area of operation for which distribution licence has been sought:

- (a) Boundaries of the proposed area of distribution/supply/operation :
- (b) Coverage of distribution network:
- (c) Nature of other electricity licenses/authorization, if any, for electricity transmission, distribution or trading already granted :
- (d) Arrangement proposed for sourcing of power
 - (i) Voltages :
 - (ii) Source of supply (Name of Supplier) :
 - (iii) Quantum of electricity proposed to be handled (Demand in MW and Energy in MU):
 - (iv) Purchase price at which electricity is proposed to be procured :
- (e) Supply of power:
 - (i) Voltages :
 - (ii) Categories of distribution and supply) :
- (f) Method and manner of establishing a forum for redressal of consumer grievances:
- (g) Funding arrangements (source and application) to meet supply obligations

5. Arrangement, if any, proposed with the existing distribution licensee in the area of distribution or supply:

6. Arrangement with the transmission licensees and other distribution licensees for evacuation of electricity:

7. Resume of the Organisation giving details of :

- (a) Management capability
- (b) Financial strength
- (c) Ability of discharge distribution and supply activities in a sustainable manner

8. Prior Experience (Past 3 years details for Related Business)

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/Consortium (As applicable)]

General Information	
Name and address of the project(s) developed	
Brief description of project(s) developed	
Cost of the project(s) developed – Rs. Lakhs	
Name and address of the Client company(s) for whom the project(s) were developed	
Name, designation and address of Reference person of Client Co (s)	

9. Details of the assets and facilities required for the Business

(a) Is the applicant acquiring, existing assets or creating new assets?

(b) Acquiring of existing assets/construction of new assets -

Funding	
Proposed means of Finance	
Equity (Rs. Lakhs)	
Applicant	
Co-promoters	
Others	
Debt	
Domestic (Rs. Lakhs)	
Indian Financial Institutions	
Commercial Banks	
Others (specify)	
International (FC Million)	
Supplier's Credit	
Direct Borrowing	
Others (specify)	

<p>Equivalent INR (with Exchange Rate used)</p> <p>Others</p>	
<p>In case asset procurement/ project is proposed to be jointly funded by an external agency</p> <p>Name and address of the agency, and contact details of the reference person of the agency (name, address, telephone/fax numbers, email, etc.)</p> <p>Proposed equity from the agency (Rs. Lakhs)</p> <p>Agency's equity as a percentage of total equity (%)</p> <p>Nature of proposed tie-up between Applicant and the other agency.</p>	
<p>Details of debt proposed for the asset</p> <p>Procurement/Project</p> <p>Details of lenders (name and address)</p> <p>Details of loan packages indicating the loan amount, currency, term of loan, interest rate, up-front fees, commitment charges etc.</p> <p>Whether any guarantee is being sought for the loans from any agency.</p> <p>If Yes, provide details</p>	<p>Yes/No</p>

(c) For applicants creating new assets—

Erection, Procurement and Commissioning	
Whether the applicant is proposing to employ an Erection, Procurement and Commissioning Contractor.	Yes/No
If Yes, name, address and contract details of the same.	
Proposed contract value	
Foreign currency	
Equivalent INR (with exchange rate used)	

(d) For applicants employing other contractors—

Other Contracts	
Whether the Applicant is proposing to employ any Contactor(s) for O&M work?	Yes/ No
If yes, name, address and contact details of the same.	
Period of the contract	
Details of the experience of the O&M contractor in similar business (es)	

Note:

1. Consent letters of the other agency and contractors to associate with the applicant for the above project to be enclosed.
2. Necessary approvals and no objections to be obtained at appropriate time and forwarded to the Commission.

10. Appropriate expertise (Personnel)

Name of Personnel	Qualification	Specialization	Years of experience	Status in the Firm
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

11. Financial details of other business ventures of the applicant.

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/consortium (As applicable)]

General Information						
Names of Subsidiary Business Units		Products manufactured/services				
1.		1.				
2.		2.				
3.		3.				
4.		4.				
5.		5.				
Financial Indicators		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Fixed assets						
Gross fixed assets						
Accumulated depreciation						
Net fixed assets						
Equity						
Promotions'						
Government/Financial						
Institutions						
Public						
Others						

Liabilities					
Long Term					
Short Term					
Income					
Sale of Power					
Others					
Expenses					
Admn. and General Expense					
Repairs and Maintenance					
Employee cost					
Interest and Financial Charges					
Long Term					
Short Term					
Others					
Financial Indicators	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Overall turnover (Rs. Lakhs)					
Profits and returns (Rs. Lakhs)					
Net profits					
Dividends paid					
Operating ratios					
Return on equity					
Return on capital employed					
Return on net fixed assets					
Liquidity ratio					
Debt service coverage ratio					
Current ratio					
Quick ratio					
Capital adequacy and credit worthiness					
Debt/Net worth					
Debt/equity					
Turnover ratio					
Total asset turnover					
Fixed asset turnover					

12. Baseline Information (Business for which Licence is sought)

General Information	
Asset Base	
Transformers (Nos.)	
500 kVA	
250 kVA	
100 kVA	
63 kVA	
25 kVA	
10 kVA	
HT Line (Ckt. Kms)	
220 kV	
110 kV	
66 kV	
33 kV	
11 kV	
LT Line (Ckt.Kms)	
440 Volts	
Commercial Information	
Metering status	
Metered consumers (as a % of total consumers)	
Billing status	
Billing (as a % of total input)	
Revenue realization	
Revenue realization per Unit Sale (Rs./ Unit)	
Collection efficiency (%)	
Loss	
Technical loss (%)	
Commercial loss (%)	

PART B LIST OF DOCUMENTS TO ACCOMPANY LICENCE APPLICATION

1. Information relating to pre-existing licence (if any), with copy of licence/sanction
2. Copies of Company's Articles of Association, Memorandum of Association, Partnership deeds and similar constitutional documents.
3. Certification of incorporation/registration
4. Certification for commencement of business.
5. Original Power of Attorney of the Signatory to commit the Applicant or its Promoter.
6. Details of Income tax registration.
7. Details of import license, if any.
8. Data relating to management and financial capability:
 - (a) Managerial :
 - (i) Senior management's curriculum vitae
 - (ii) Cadre strength for different categories (technical and non-technical)
 - (b) Financial:
 - (i) Bank references asserting that the applicant is financially solvent
 - (ii) Most recent Annual Financial Statements (Balance Sheet)
 - (iii) Annual Audited Accounts for the past 3 years for the applicant and any holding Company, subsidiary or affiliated company
 - (iv) Any accompanying notes and certifications on the above statements from reputable Chartered Accountant.
 - (c) Any other document evidence to substantiate the financial capabilities, technical competence and others.
9. Data relating to the applicant's business proposals:
 - (a) Five year Business Plan (with projection) for the proposed business for which the application relates.
 - (b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues, project financing and funding arrangements (clearly specifying the assumptions involved)
10. Detailed Map(s):
 - (i) Detailed electrical distribution map (including information on substations and configuration of the system) and geographical map for the proposed area of distribution, drawn to scale (scale not less than 10 Cms to a Km or any other scale as may be approved by the Commission)
 - (ii) The map shall clearly distinguish between the existing system and new facilities that shall be required for meeting the obligation to supply.

- (iii) The map shall indicate the streets and roads in which the electricity is distributed.
 - (iv) A list of all local authorities vested with the administration of any portion of the area of distribution.
 - (v) An approximate statement describing any lands, which the applicant proposes to acquire for the purpose of the licence and the means of such acquisition
11. No objection certificates to distribute or supply in an area from the Central Government as per s.15(2) (ii) of the Electricity Act or acknowledgement for the filing of the application with the Central Government seeking such approval.

Date

Signature of the applicant

ANNEXURE-XIII

FORM CB-15

[See regulations 27(4) and 28(1)CBR]

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FORM-1 : Application Form for a Transmission Licence in the State of Himachal Pradesh.

The applicant must submit the completed application in xxx copies to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, (address), alongwith application fee of Rs. xxxx (Rupees in words) in form of a DD drawn in favour of Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, payable at Shimla.

PART-A—GENERAL INFORMATION OF APPLICANT**1. Details of Applicant:**

- (a) Full name of the Applicant :
- (b) Full address of the Applicant :
- (c) Name, designation and address of the contact person :
- (d) Contact Telephone Numbers :
- Fax (Number(s)) :
- Email ID :

2. Nature and details of ownership:

- (a) Company/Firm/Co-op Society/Individual/Others :
- (b) When and where Company Incorporation/Registration
- Place of Incorporation/Registration :
- Year of Incorporation :
- Registration Number :
- Place of Registration of the firm, Co-op. Society :

(c) Name and addresses of Directors

3. Principal Shareholders/Partners/Members

4. Details of the area of transmission for which transmission licence has been sought:

- (a) Boundaries of the proposed Area of Transmission :
- (b) Coverage of Transmission Network:
- (c) Nature of other electricity licenses/authorization, if any,
for electricity transmission, distribution or trading already granted :
- (d) Funding arrangements (source and application) to meet
Supply obligations

5. Arrangement, if any, proposed with the State Transmission Utility:

6. Arrangement if any proposed with the other licensees

7. Arrangement if any proposed with the Generating Companies

8. Resume of the Organisation giving details of :

- (a) Management capability
- (b) Financial strength
- (c) Ability to attend activities in a sustainable manner

9. Prior experience (Past 5 years details for Related Business)

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/Consortium (As applicable)]

General Information	
Name and address of the project(s) developed	
Brief description of project(s) developed	
Cost of the project(s) developed – Rs. Lakhs	
Name and address of the client company(s) for whom the project(s) were developed	
Name, designation and address of Reference person of client Co (s)	

10. Details of the Assets and facilities required for the Business:

- (a) Is the applicant acquiring, existing assets or Creating New Assets?
 (b) Acquiring of Existing Assets/Construction of New Assets

Funding	
Proposed means of Finance	
Equity (Rs. Lakhs)	
Applicant	
Co-promoters	
Others	
Debt	
Domestic (Rs. Lakhs)	
Indian Financial Institutions	
Commercial Banks	
Others (specify)	
International (FC Million)	
Supplier's Credit	
Direct Borrowing	
Others (specify)	
Equivalent INR (with Exchange rate used)	
Others	
In case Asset procurement/ Project is proposed to be jointly funded by an External Agency	
Name & Address of the Agency, and contact details of the reference person of the Agency (name, address, telephone/fax numbers, email, etc.)	
Proposed Equity from the Agency (Rs. Lakhs)	

Agency's equity as a percentage of total equity (%)	
Nature of proposed tie-up between Applicant and the other agency.	
Details of debt proposed for the Asset Procurement Project	
Details of Lenders (name & address)	
Details of Loan packages indicating the loan amount, currency, Term of Loan, interest rate, up-front fees, commitment charges etc.	
Whether any guarantee is being sought for the loans from any agency.	
Is Yes, provide details	Yes/No

(c) For Applicants creating New Assets

EPC	
Whether the Applicant is proposing to employ an EPC Contractor.	Yes/No
If Yes, Name, Address & Contact details of the same.	
Proposed contract value	
Foreign Currency	
Equivalent INR (with Exchange rate used)	

(d) For Applicants employing other contractors

Other Contracts	
Whether the Applicant is proposing to employ any Contactor(s) for O&M work.	Yes/ No
If yes, Name, Address & Contact details of the same.	
Period of the Contract	
Details of the experience of the O&M contractor in similar business (es)	

Note:

- 1 Consent letters of the other Agency & Contractors to associate with the Applicant for the above project to be enclosed.
- 2 Necessary approvals and no objections to be obtained at appropriate time and forwarded to the Commission.

11. Appropriate Expertise (Personnel):—

Name of Personnel	Qualification	Specialization	Years of Experience	Status in the Firm
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

12. Financial details of other business ventures of the applicant.

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/Consortium (As applicable)]

General Information					
Names of Subsidiary Business Units	Products Manufactured/Services				
Financial Indicators	Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
Fixed Assets					
Gross Fixed Assets					
Accumulated Depreciation					
Net Fixed Assets					
Equity					
Promotions'					
Government/Financial					
Institutions					
Public					
Others					
Liabilities					
Long Term					
Short Term					
Income					
Sale of Power					
Others					
Expenses					
Admn. & General Expense					
Repairs & Maintenance					
Employee Cost					
Interest & Financial Charges					
Long Term					
Short Term					
Others					
Financial Indicators					
Overall Turnover (Rs. Lakhs)					

13. Baseline Information (Business for which Licence is sought)

[illegible]

PART B LIST OF DOCUMENTS TO ACCOMPANY LICENCE APPLICATION

1. Information relating to pre-existing licence (if any), with copy of licence/sanction
2. Copies of Company's Articles of Association, Memorandum of Association, Partnership deeds and similar constitutional documents.
3. Certification of incorporation/Registration
4. Certification for commencement of Business.
5. Original Power of Attorney of the Signatory to commit the Applicant or its Promoter.
6. Details of Income Tax registration.
7. Details of import license, if any.
8. Data relating to Management and Financial capability:
 - (a) Managerial:
 - (i) Senior management's curriculum vitae
 - (ii) Cadre strength for different categories (technical and non-technical)
 - (b) Financial:
 - (i) Bank references asserting that the Applicant is financially solvent
 - (ii) Most recent Annual Financial Statements (Balance Sheet)
 - (iii) Annual Audited Accounts for the past 3 years for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company
 - (iv) Any Accompanying notes and certifications on the above statements from reputable chartered accountant.
 - (c) Any other document evidence to substantiate the financial capabilities, technical competence and others.
9. Data relating to the Applicant's Business proposals:
 - (i) Five year Business Plan (with projection) for the proposed business for which the application relates.
 - (ii) Five year annual forecasts of costs, revenues, project financing and funding arrangements (clearly specifying the assumptions involved)
10. An approximate Statement describing any lands, which the Applicant proposes to acquire for the purpose of the licence and the means of such acquisition.
11. Acknowledgment for service of the copy of the application with the annexure and documents to the State Transmission Utility.

Date

Signature of the Applicant

ANNEXURE-XIV

FORM-CB-16

[See regulations 27(4) and 28(1)CBR]

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**FORM-1 : Application Form for a Trading Licence in the State of Himachal Pradesh**

The applicant must submit the completed application in xxx copies to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, (address), alongwith application fee of Rs. xxxx (Rupees in words) in form of a DD drawn in favour of Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, payable at Shimla.

PART-A: GENERAL INFORMATION OF APPLICANT**1. Details of Applicant:**

(a) Full name of the Applicant :

(b) Full address of the Applicant :

(c) Name, designation and address of the contact person :

(d) Contact Telephone Numbers :

Fax Number(s) ::

Email ID .:

2. Details of ownership:

(a) Company/Firm/Co-op Society/Individual/Others :

(b) When and where Company Incorporation/Registration

Place of Incorporation/Registration

Year of Incorporation

Registration Number

(c) Name and addresses of Directors

3. Principal Shareholders/Partners/Members

4. Details of the area of operation :

Nature of other electricity licenses/authorization, if any, of the applicant for electricity transmission, distribution or trading already granted :

5. Details of operation :

Maximum trading volume proposed to be undertaken by the applicant on a monthly basis for the first three years.

6. Funding arrangements (source and application) to meet the obligations

7. Arrangement for purchase of energy

8. Arrangement, if any, proposed with other existing trading and distribution licensees

9. Resume of the Organisation giving details of :

(a) Management capability

(b) Financial strength

(c) Ability to attend activities in a sustainable manner

10. Prior experience (Past 5 years details for Related Business)

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/Consortium (As applicable)]

General Information	
Name and address of the project(s) developed	
Brief description of project(s) developed	
Cost of the project(s) developed – Rs. Lakhs	
Name and address of the client company(s) for whom the project(s) were developed	
Name, designation and address of Reference person of client Co (s)	

11. Financial details of other business ventures of the applicant.

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/consortium (As applicable)]

General Information						
Names of Subsidiary Business Units		Products Manufactured/Services				
Financial Indicators		Year-1	Year-2	Year-3	Year-4	Year-5
Fixed Assets						
Gross fixed assets						
Accumulated depreciation						
Net fixed assets						
Equity						
Promotions'						
Government/Financial						
Institutions						
Public						
Others						
Liabilities						
Long Term						
Short Term						
Income						
Sale of power						
Others						
Expenses						
Admn. and General Expense						
Repairs and maintenance						
Employee cost Interest and						
Financial Charges						
Long Term						
Short Term						
Others						
Financial Indicators						
Overall turnover (Rs. Lakhs)						

Profits and returns (Rs. Lakhs)					
Net profits					
Dividends paid					
Operating ratios					
Return on equity					
Return on capital employed					
Return on net fixed assets					
Liquidity ratio					
Debt service coverage ratio					
Current ratio					
Quick ratio					
Capital adequacy and credit worthiness					
Debt/Networth					
Debt/equity					
Turnover ratio					
Total asset turnover					
Fixed asset turnover					

12. Baseline Information (Business for which Licence is sought)

[illegible]

PART B LIST OF DOCUMENTS TO ACCOMPANY LICENCE APPLICATION

1. Information relating to pre-existing licence (if any), with copy of licence/sanction
2. Copies of Company's Articles of Association, Memorandum of Association, Partnership deeds and similar constitutional documents.
3. Certification of incorporation/Registration
4. Certification for commencement of Business.
5. Original Power of Attorney of the Signatory to commit the Applicant or its Promoter.
6. Details of Income Tax registration.
7. Data relating to Management and Financial capability:
 - (a) Managerial:
 - (i) Senior management's curriculum vitae
 - (ii) Cadre strength for different categories (technical and non-technical)
 - (b) Financial:
 - (i) Bank references asserting that the Applicant is financially solvent
 - (ii) Most recent Annual Financial Statements (Balance Sheet)
 - (iii) Annual Audited Accounts for the past 3 years for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company
 - (iv) Any Accompanying notes and certifications on the above statements from reputable chartered accountant.
 - (c) Any other document evidence to substantiate the financial capabilities, technical competence and others.
8. Data relating to the Applicant's Business proposals
9. Five year Business Plan (with projection) for the proposed business for which the application relates.
10. Five year annual forecasts of costs, revenues, project financing and funding arrangements (clearly specifying the assumptions involved)
11. An approximate Statement describing any lands, which the Applicant proposes to acquire for the purpose of the licence and the means of such acquisition.

Date

Signature of the Applicant.

ANNEXURE-XV

FORM-CB-17

[See regulation 34 CBR]

**PROFORMA OF PUBLICATION
BEFORE THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION**

NOTICE

Notice is hereby given to all the interested persons that Messers (Name and Address of the Applicant) has applied to the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commissions (the Commission for grant of licence (nature of the licence) in the area (specify the area of operation). The application and other documents filed by the applicant can be inspected at the office of the applicant. And copies of the same will be available from the applicant for a price not exceeding the normal photocopy charges.

Any person interested in objecting to or otherwise making representation in regard to the grant of licence may forward the objections/representation with the Commission in Copies by hand delivery or by registered post and should serve a copy of the objection/representation to Messers at the address mentioned above .

The person filing the objection/representation should give the following particulars:—

1. Name and full address.
2. Grounds/reasons in support of the objection/representation together with documents or evidence, if available.
3. Whether he wish to be heard in person or through authorized representative at the time of hearing.

ANNEXURE-XVI

FORM-CB-18

(See regulation 49 CBR)

FORMAT FOR FURNISHING TECHNICAL DETAILS BY GENERATING COMPANIES

1. General:

- (a) Name of the Company :
- (b) Address of Registered Office :
- (c) Postal Address for communication :
- (d) Location of the proposed Generating Station :

(a) District :

(b) Taluk :

2. Particulars of proposed generating Unit(s):

- (a) Capacity in KVA :
- (b) No. of Units :
- (c) Capacity of each unit :
- (d) No. of phases :
- (e) Power Factor :
- (f) Frequency (HZ) :
- (g) Technical specifications of other equipment :
- (h) Voltage of generation :

3. Fuel for the proposed Power Plant:

- (a) Coal/Gas/Naptha :
- (b) Others – Specify fuel :
- (Strike-off whichever is not applicable)

4. Tie-up for supply of fuel:

(applicable for large unit(s) i.e. MVA and above)

- (a) Whether Fuel/Coal linkage is received if yes, particulars:
- (b) Whether Fuel Transport Agreement entered into, if yes, give details:

5. Other technical particulars:

- (a) Proposed date of commencement of generation :
- (b) Salient features of the project relating to
Technical details of Generator, Prime Mover,
Exciter, Automatic Voltage Regulation,
Protection, Interconnection with Licensee
(to be separately attached)
- (c) Planed peak generation in MW :
- (d) Operating plant load factor :
- (e) Total annual requirement of electricity in
millions of units by the industry :
- (f) Peak requirement of the industry in MW :
- (g) Voltage at which interconnection with licensee system
is desired :
- (h) Nearest supply point of interconnection with
Licensee :
- (i) Arrangements for synchronization, if generating units
are proposed to be run in parallel :
- (j) Estimated cost of proposed interconnection :

Date:

Signature

Applicability of provisions of the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code

(i) Section 193, (of the Indian Penal Code)

Punishment for false evidence:—

Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

And whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term, which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation –1 A trial before a Court-martial ^a[***] is a judicial proceeding.

Explanation –2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

(ii) Section 219 (of the Indian Penal Code)

Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law:—

Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding, any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

(iii) Section 228 (of the Indian Penal Code)

Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding:—

Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to any public servant, while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or which may extend to one thousand rupees, or with both.

(iv) Section 345 (of the Code of Criminal Procedure)

Procedure in certain cases of contempt:—

- (a) When any such offence as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or the section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is committed in the view or presence of any Civil, Criminal or Revenue Court, the Court may cause the offender to be detained in custody and may, at any time before the rising of the Court on the same day, take cognizance of the offence and, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to fine not exceeding two hundred rupees, and, in default of payment of fine, to simple imprisonment for a term which may extend to one month, unless such fine be sooner paid.
- (b) In every such case the Commission shall record the facts constituting the offence, with the statement (if any) made by the offender, as well as the finding and sentence.
- (c) If the offence is under section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the record shall show the nature and stage of the judicial proceeding in which the Court interrupted or insulted was sitting, and the nature of the interruption or insult.

(v) Section 346 (of Code of Criminal Procedure)

Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 345:—

- (1) If the Court in any case considers that a person accused of any of the offences referred to in section 345 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding two hundred rupees should be imposed upon him, or such Court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under section 345, such Court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate, or if sufficient security is not given shall forward such person in custody to such Magistrate.
- (2) The Magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with, as far as may be, as if it were instituted on a police report.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।